

2.1 2006-07 की दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन दर्शाना जारी रखा। औद्योगिक उत्पादन ने गति बनाए रखा तथा 2006-07 के दौरान वृद्धि बढ़कर 2 अंकों तक पहुंच गई, जो विनिर्माण क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि द्वारा प्रेरित थी। औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन की एक उल्लेखनीय विशेषता पूंजीगत माल क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर का बने रहना है। थोड़े दिनों की मंदी के बाद 2005-06 की दूसरी छमाही में निजी कंपनी क्षेत्र के निष्पादन में सुधार हुआ है, जो देशी तथा निर्यात मांग में उछाल द्वारा समर्थित है। निवेश का माहौल उत्साहजनक बना हुआ है। 2006-07 की पहली तीन तिमाहियों में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में तेजी रही जो मुख्यतः 'व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार' तथा 'वित्तपोषण, बीमा, भू-संपदा और व्यावसायिक सेवा' नामक उप क्षेत्रों के योगदान से हुई। दक्षिण-पश्चिम मानसून 2006 की शुरुआत में एक सप्ताह से अधिक की देरी हुई। यद्यपि मानसून का समग्र निष्पादन सामान्य के नजदीक था, पर कालिक तथा स्थानिक वितरण में समानता नहीं थी। तथापि, कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छी गति से वृद्धि होने की संभावना है।

2.2 नवम्बर 2006 से हेडलाइन मुद्रास्फीति का स्तर ऊंचा बना रहा, जो मुख्यतः प्राथमिक खाद्य वस्तुओं तथा विनिर्मित उत्पादों द्वारा चालित था। पूरे साल के दौरान उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के ऊपर बनी रही, जो मुख्यतः खाद्यान्नों की ऊंची कीमतों के प्रभाव को दर्शाता है। अक्टूबर 2006 में रिजर्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में यह देखा गया कि बढ़ रही आस्ति कीमतों तथा मूलभूत संरचना संबंधी अवरोधों में आयी सख्ती के साथ उच्च वृद्धि तथा उपभोक्ता मुद्रास्फीति के समिश्रण ने ओवरहीटिंग के खतरों तथा मौद्रिक नीति के निर्धारण के समय और दिशा के निहितार्थों की आवश्यकता पर बल दिया है। तथापि इस बात पर भी बल दिया कि यह मानना महत्वपूर्ण है कि ओवरहीटिंग की आशंका का स्वरूप अस्थायी हो सकता है क्योंकि उल्लेखनीय निवेश होने के साक्ष्य हैं, जिसके साथ समग्र उत्पादकता बढ़ेगी जिससे संभाव्य उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त कुल मांग की ओर इशारा करने वाले सभी उपलब्ध संकेतकों की निगरानी के महत्व पर बल देना जारी रखा।

2.3 2006-07 के दौरान रिजर्व बैंक ने उपलब्ध साधनों अर्थात् चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत प्रतिभूतियों के निर्गम के न्यायपूर्ण मिश्रण के साथ चलनिधि का प्रबंधन किया। प्रभावी चलनिधि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, मार्च 2007 में रिजर्व बैंक ने आशोधन करके एमएसएस के तहत

प्रतिभूतियां जारी करने का आवर्धित कार्यक्रम बनाया जो अधिक लचीले तौर पर खजाना बिलों और दिनांकित प्रतिभूतियों का मिश्रण था। तदनुसार, दैनिक रिवर्स रिपो के अवशोषण को अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए तक सीमित रखा गया। अंतर्निहित स्फीतिकारी दबावों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने पूर्वक्रयात्मक मौद्रिक नीति उपायों की एक श्रृंखला का सहारा लिया अर्थात् जून 2006 से चरणों में नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 150 आधार अंकों की एवं रिपो/रिवर्स रिपो दर में 125 / 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई। आपूर्ति पक्ष के राजकोषीय उपायों तथा ईंधन की कीमतों में कमी के साथ उक्त उपायों ने मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने में मदद की। तथापि, चलनिधि प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित करना जारी रखा कि उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण की सभी वैध अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रणाली में उपयुक्त चलनिधि बनाए रखा जाए, जो मूल्य तथा राजकोषीय स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप हो, जिस पर जनवरी 2007 में तीसरी तिमाही की समीक्षा में बल दिया गया था।

2.4 नवम्बर और दिसम्बर 2006 के मध्य तथा मार्च 2006 के मध्य के संक्षिप्त समय को छोड़कर, जब चलनिधि में कमी के कारण मांग मुद्रा दरों में उच्चस्तरीय तेजी आई, वित्तीय बाजार व्यवस्थित बने रहे। मई-जून 2006 तथा फरवरी/मार्च 2007 के दौरान ईक्विटी बाजार में भी अस्थिरता के संक्षिप्त दौर आए। इन घटनाओं को छोड़कर, वित्तीय बाजार स्थिर रहे।

2.5 वित्तीय संस्थाओं, विशेषतः अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, ने 2005-06 के दौरान कारोबार तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार देखा, जो अच्छे समष्टि आर्थिक मूलभूत तत्वों द्वारा समर्थित था। संशोधित अनुमानों के अनुसार केंद्र तथा राज्य दोनों के सार्वजनिक वित्तपोषण में कर और करेतर राजस्व दोनों में उछाल, जो उच्चतर व्यय को प्रतिफलित करने से भी अधिक था, के समर्थन से सुधार दिखाई दिया।

2.6 माल तथा सेवाओं के पण्य निर्यातों में सशक्त वृद्धि के साथ बाह्य क्षेत्र में गतिशीलता बनी रही। साल के अधिकांश हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें ऊंची और अस्थिर होने के बावजूद भुगतान संतुलन की स्थिति सुखद बनी रही। चालू खाता घाटा से अधिक मात्रा में बड़े पूंजी प्रवाहों का आना जारी रहा जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में पर्याप्त मात्रा में निवल वृद्धि हुई।

2.7 उक्त पृष्ठभूमि में इस अध्याय में 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान (उस अवधि तक जिसके लिए नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं)

**सारणी 2.1 : वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद
(1999-2000 की कीमतों पर)**

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (त्व.अनु.)	2006-07 (अग्रि.अनु.)
1	2	3	4	5	6	7	8
विकास दर							
1. कृषि और सहायक गतिविधियाँ	-0.2	6.3	-7.2	10.0	0.0	6.0	2.7
क) कृषि	-0.6	6.5	-8.1	10.9	-0.2	6.3	..
2. उद्योग	6.4	2.4	6.8	6.0	8.4	8.0	10.2
क) विनिर्माण	7.7	2.5	6.8	6.6	8.7	9.1	11.3
ख) खनन और उत्खनन	2.4	1.8	8.8	3.1	7.5	3.6	4.5
ग) विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	2.1	1.7	4.7	4.8	7.5	5.3	7.7
3. सेवाएं	5.7	6.8	7.4	8.9	10.0	10.3	11.0
क) व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट	5.2	9.6	6.9	10.3	8.4	8.2	13.0 \$
ख) परिवहन, भंडारण और संचार	11.2	8.2	13.6	15.1	15.2	13.9	
ग) वित्तपोषण, बीमा, जमीन-जायदाद और व्यावसायिक सेवाएं	4.1	7.3	8.0	5.6	8.7	10.9	11.1
घ) समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	4.8	4.1	3.9	5.4	7.9	7.7	7.8
ड) निर्माण	6.2	4.0	7.9	12.0	14.1	14.2	9.4
4. सकल देशी उत्पाद- कारक लागत पर	4.4	5.8	3.8	8.5	7.5	9.0	9.2
क्षेत्रवार संरचना							
1. कृषि और सहायक गतिविधियाँ	23.9	24.0	21.5	21.7	20.2	19.7	18.5
2. उद्योग	20.0	19.3	19.9	19.5	19.6	19.4	19.6
3. सेवाएं	56.1	56.7	58.7	58.8	60.2	60.9	61.9
4. कुल	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ज़ापन :							
वास्तविक जीडीपी 1999-2000 की कीमतों पर कारक लागत पर (करोड़ रूपए)	18,64,773	19,72,912	20,47,733	22,22,591	23,89,660	26,04,532	28,44,022
.. : उपलब्ध नहीं	त्व.अनु.:	त्वरित अनुमान	अग्रि.अनु.:	अग्रिम अनुमान			
\$: 'व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट' और 'परिवहन, भंडारण और संचार' शामिल है।							
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।							

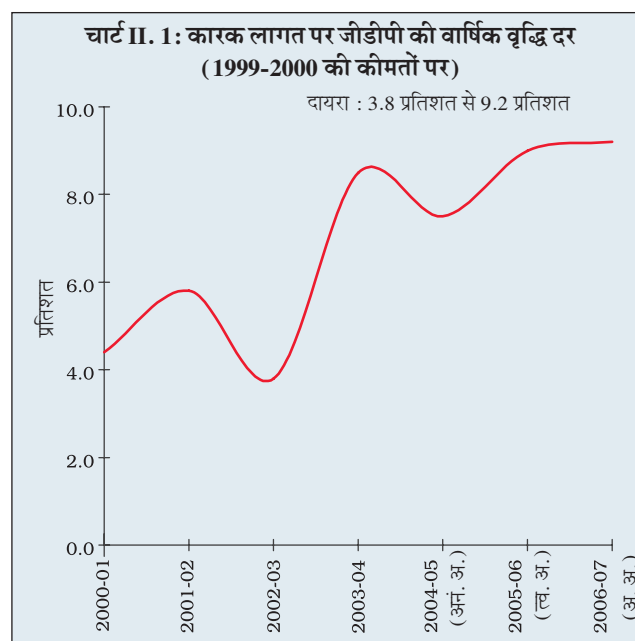
समष्टि आर्थिक गतिविधियों का ब्यौरेवार वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जहां कहीं उपलब्ध हुआ, 2007-08 के लिए नवीनतम समष्टि आर्थिक गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। खंड I में वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियां प्रस्तुत की गई हैं, खंड II में केंद्र तथा राज्य सरकार के वित्तपोषण का ब्यौरा दिया गया है। खंड III में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों सहित मौद्रिक और ऋण संबंधी गतिविधियों पर चर्चा की गई है। खंड IV में वित्तीय बाजारों की गतिविधियों का वर्णन है। वित्तीय संस्थाओं के व्यावसायिक परिचालनों को खंड V में दिया गया है। खंड VI में बाह्य क्षेत्र की गतिविधियां दी गई हैं। समग्र मूल्यांकन खंड VII में दिया गया है।

I. वास्तविक क्षेत्र

राष्ट्रीय आय

2.8 वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2004-05 के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 9.0 प्रतिशत होने के साथ 2005-06 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि दिखाई दी। 2005-06 के दौरान कार्यनिष्पादन में हुआ सुधार कृषि तथा सहायक कार्यकलापों में वृद्धि में टर्नअराऊंड और सेवा क्षेत्र में वृद्धि बने रहने द्वारा समर्थित था। औद्योगिक क्षेत्र में ऊंची

वृद्धि बनी रही हालांकि वह 2004-05 की तुलना में थोड़ी कम थी (सारणी 2.1 तथा चार्ट II.1)। कृषि तथा सहायक कार्यकलापों में हुई



**सारणी 2.2 : सकल घरेलू उत्पाद की त्रैमासिक वृद्धि दरें
(1999-2000 की कीमतों पर)**

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2001-02 से 2006-07 (औसत)	2005-06*	2006-07#	2005-06				2006-07			अप्रैल-दिसंबर	
				1ति	2ति	3ति	4ति	1ति	2ति	3ति	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. कृषि और सहायक गतिविधियाँ	3.0	6.0	2.7	4.0	4.0	8.7	5.5	3.4	1.7	1.5	6.0	2.2
1.1 कृषि	(20.9)	(19.7)	(18.5)									
2. उद्योग	7.0	8.0	10.2	9.8	6.6	7.2	7.9	9.7	10.5	10.0	7.8	10.1
2.1 खनन और उत्खनन	(19.5)	(19.4)	(19.6)									
2.2 विनिर्माण	4.9	3.6	4.5	6.0	0.1	2.7	3.0	3.4	3.1	5.7	3.0	4.1
2.3 विद्युत, गैस और जल आपूर्ति	7.5	9.1	11.3	10.7	8.1	8.2	8.9	11.3	11.9	10.7	9.0	11.3
3. सेवाएं	5.3	5.3	7.7	7.4	2.6	5.0	6.1	5.4	7.7	9.3	5.0	7.5
3.1 व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	9.1	10.3	11.0	9.5	9.5	10.3	11.0	10.4	10.7	11.1	9.8	10.8
3.2 वित्तपोषण, बीमा, जमीन-जायदाद और कारोबार सेवाएं	(59.5)	(60.9)	(61.9)									
3.3 समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	10.8	10.4	13.0	10.2	9.5	10.0	12.9	13.1	13.8	13.0	9.9	13.3
3.4 निर्माण	8.6	10.9	11.1	8.9	10.6	9.8	10.5	9.0	9.5	11.6	9.8	10.1
4. कारक लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद	6.2	7.7	7.8	7.5	7.9	8.3	7.6	7.4	6.9	7.5	7.9	7.2
	10.3	14.2	9.4	12.7	11.3	16.6	12.0	9.5	9.8	9.9	13.6	9.7
	7.3	9.0	9.2	8.4	8.0	9.3	9.3	8.9	9.2	8.6	8.6	8.9
	(100.0)	(100.0)	(100.0)									

* : त्वरित अनुमान

: अग्रिम अनुमान

.. : उपलब्ध नहीं

नोट : कोष्ठकों के आंकड़े वास्तविक जीडीपी में हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

वृद्धि खाद्यान्न और खाद्यान्नेतर दोनों उत्पादन तथा बागबानी, पशुधन, मत्स्यपालन और पादरोपण फसलों में सुधार से संभव हुई। औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न वास्तविक जीडीपी वृद्धि मुख्यतः सुदृढ़ निर्माण कार्यकलाप द्वारा चालित थी। देशी तथा निर्यात मांग में धारित वृद्धि, क्षमता उपयोग में वृद्धि, क्षमताओं का आवर्धन तथा व्यवसाय एवं उपभोक्ता विश्वास की सकारात्मकता के समर्थन से विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई। पिछले साल की दोहरे अंक वाली वृद्धि जारी रखते हुए सेवा क्षेत्र में उत्पन्न वास्तविक जीडीपी में 2005-06 के दौरान 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2005-06 के दौरान सेवा क्षेत्र प्रमुख चालक बना रहा जिसने समग्र वास्तविक जीडीपी में तीन बटा पांच का अंशदान किया। मुख्यतः 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' तथा वित्तपोषण, बीमा, भू-संपदा और व्यावसायिक सेवा' जैसे उप क्षेत्रों की अगुवाई में सेवा क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में उछाल आई।

2.9 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम अनुमानों ने 2006-07 के लिए 9.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है जो देशी आर्थिक कार्यकलापों में उछाल बने रहने की ओर इशारा करता है। 2006-07 की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसम्बर) के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि एक वर्ष पहले की तदनु रूप अवधि के 8.6 प्रतिशत की तुलना में 8.9 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर रखी गई है (सारणी 2.2)। 2006-07 की तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसम्बर) में कुल औद्योगिक उत्पादन में 2005-06 की तदनु रूप अवधि के 7.8

प्रतिशत की तुलना में 10.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। 2006-07 की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसम्बर) में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2005-06 की तदनु रूप अवधि के 9.8 प्रतिशत की तुलना में 10.8 प्रतिशत पर उच्चतर रहने का अनुमान है।

2.10 विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 2007-08 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.9 - 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है (सारणी 2.3)। इस दर पर भारत विश्व की उभरती बाजार

**सारणी 2.3 : वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि,
2007-08 : भारत के लिए पूर्वानुमान**

(प्रतिशत)

संस्थान	अद्यतन	अनुमान का महीना
1	2	3
एशियाई विकास बैंक	8.0	(मार्च 2007)
भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र	8.5	(मई 2007)
भारतीय उद्योग परिसंघ	8.5	(अप्रैल 2007)
क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड	7.9-8.4	(मार्च 2007)
राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद	8.3	(अप्रैल 2007)
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	8.4	(अप्रैल 2007)
भारतीय रिजर्व बैंक	लगभग 8.5	(अप्रैल 2007)
ज्ञापन :		
दायरा	7.9-8.5	

सारणी 2.4 : उत्पादन में वृद्धि : विभिन्न देशों के बीच तुलना

(प्रतिशत)

देश	औसत 1999-2008	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007अ	2008अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विश्व	4.4	3.7	4.8	2.5	3.1	4.0	5.3	4.9	5.4	4.9	4.9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	2.6	3.5	4.0	1.2	1.6	1.9	3.3	2.5	3.1	2.5	2.7
अन्य उभरते बाजार और विकासशील देश	6.4	4.1	6.0	4.3	5.0	6.7	7.7	7.5	7.9	7.5	7.1
अर्जेंटीना	2.9	-3.4	-0.8	-4.4	-10.9	8.8	9.0	9.2	8.5	7.5	5.5
बांग्लादेश	5.9	5.4	5.6	4.8	4.8	5.8	6.1	6.3	6.7	6.6	6.5
ब्राजील	3.1	0.3	4.3	1.3	2.7	1.1	5.7	2.9	3.7	4.4	4.2
चिली	4.0	-0.4	4.5	3.5	2.2	4.0	6.0	5.7	4.0	5.2	5.1
चीन	9.4	7.6	8.4	8.3	9.1	10.0	10.1	10.4	10.7	10.0	9.5
भारत	7.0	6.7	5.3	4.1	4.3	7.3	7.8	9.2	9.2	8.4	7.8
इंडोनेशिया	4.8	0.8	5.4	3.6	4.5	4.8	5.0	5.7	5.5	6.0	6.3
मलेशिया	5.5	6.1	8.9	0.3	4.4	5.5	7.2	5.2	5.9	5.5	5.8
मैक्सिको	3.1	3.8	6.6	-	0.8	1.4	4.2	2.8	4.8	3.4	3.5
पाकिस्तान	5.3	3.7	4.3	2.0	3.2	4.9	7.4	8.0	6.2	6.5	6.5
फ़िलीपीन्स	4.9	3.4	6.0	1.8	4.4	4.9	6.2	5.0	5.4	5.8	5.8
श्रीलंका	5.2	4.3	6.0	-1.5	4.0	6.0	5.4	6.0	7.5	7.0	7.0
थाइलैंड	4.9	4.4	4.8	2.2	5.3	7.1	6.3	4.5	5.0	4.5	4.8

अ : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान।

स्रोत : वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2007।

अर्थव्यवस्थाओं के बीच तीव्रतम वृद्धिवाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा (सारणी 2.4)।

बचत और निवेश

2.11 चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल देशी बचत (जीडीएस) की दर, जो 2000-01 से लगातार बढ़ रही है,

2005-06 में 32.4 प्रतिशत पर रखी गई है (सारणी 2.5 तथा चार्ट II.2)। 32.4 प्रतिशत पर जीडीएस की दर 1950-51 से अधिकतम है। घरेलू क्षेत्र जीडीएस में प्रमुख अंशदाता बना हुआ है तथा उसकी बचत दर 2004-05 के 21.6 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में 22.3 प्रतिशत पर रखी गयी है। 2000-01 से 2004-05 के दौरान भौतिक आस्तियों

सारणी 2.5 : सकल घरेलू बचत और निवेश

(चालू बाजार कीमतों पर जीडीपी का प्रतिशत)

क्षेत्र	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 अ	2005-06 त्व.अनु.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सकल घरेलू बचत(जीडीएस) (1.1+1.2+1.3)	24.8	23.4	23.5	26.4	29.7	31.1	32.4
1.1 घरेलू बचत	21.1	21.0	21.8	22.7	23.8	21.6	22.3
क) वित्तीय आस्तियाँ	10.6	10.2	10.8	10.3	11.3	10.2	11.7
ख) भौतिक आस्तियाँ	10.5	10.8	10.9	12.4	12.4	11.4	10.7
1.2 निजी कंपनी क्षेत्र	4.5	4.3	3.7	4.2	4.7	7.1	8.1
1.3 सार्वजनिक क्षेत्र	-0.8	-1.9	-2.0	-0.6	1.2	2.4	2.0
2. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (जीडीसीएफ)#	25.9	24.0	22.9	25.2	28.0	31.5	33.8
3. बचत-निवेश अंतर (1-2)	-1.1	-0.6	0.6	1.2	1.7	-0.4	-1.3
4. सकल पूंजी निर्माण (4.1+4.2+4.3+4.4)	26.1	24.1	23.8	25.0	26.6	29.7	32.2
4.1 घरेलू क्षेत्र	10.5	10.8	10.9	12.4	12.4	11.4	10.7
4.2 निजी कंपनी क्षेत्र	7.4	5.7	5.4	5.9	6.9	9.9	12.9
4.3 सार्वजनिक क्षेत्र	7.4	6.9	6.9	6.1	6.3	7.1	7.4
4.4 बहुमूल्य वस्तुएं@	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3	1.2

अ. : अनंतिम त्व.अनु. : त्वरित अनुमान

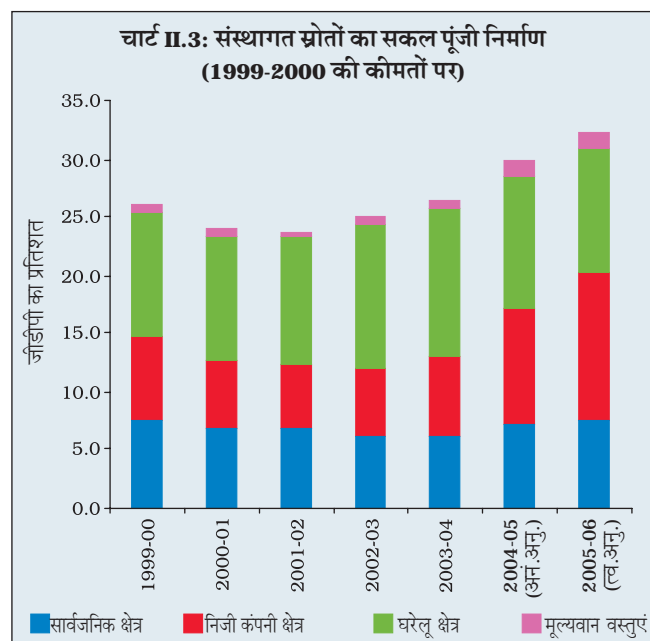
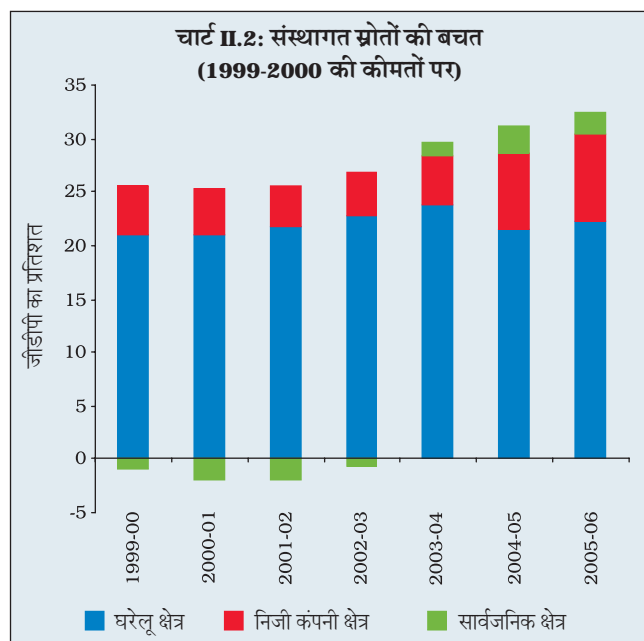
: त्रुटियों और चूक के लिए समायोजित।

@ : बहुमूल्य वस्तुओं में सकल पूंजी निर्माण में शामिल बहुमूल्य वस्तुओं के अर्जन में किए गए व्यय शामिल हैं।

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण आँकड़ों का योग, कहीं-कहीं जोड़ के बराबर नहीं है।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

हाल की आर्थिक गतिविधियां



के रूप में घरेलू क्षेत्र द्वारा की गई बचत वित्तीय आस्तियों से अधिक रही। तथापि, 2005-06 में यह प्रवृत्ति पलट गई। निजी कंपनी बचत, जो 2001-02 से स्थिरतापूर्वक बढ़ रही है, में 2005-06 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें 2003-04 से सकारात्मक बचत दर रही है, ने 2005-06 में 2.0 प्रतिशत की बचत दर दर्ज की जो राजकोषीय स्थिति में सतत सुधार से संभव हुआ।

2.12 चालू बाजार मूल्यों पर जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल देशी पूंजी निर्माण की दर सार्वजनिक निवेश तथा निजी कंपनी निवेश में सुधार के कारण 2004-05 के 31.5 प्रतिशत के स्तर से तेजी से बढ़कर 2005-06 में 33.8 प्रतिशत हो गई। बचत दर की तुलना में निवेश की

दर में उच्चतर वृद्धि 2005-06 में समग्र बचत - निवेश संतुलन में, 2004-05 के 0.4 प्रतिशत के घाटे की तुलना में, 1.3 प्रतिशत के घाटे में दिखाई देती है (सारणी 2.6 तथा चार्ट II.3)।

कृषि

2.13 2005-06 में उल्लेखनीय सुधार दशानिके बाद मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन में न्यूनतर वृद्धि की प्रत्याशा के कारण 2006-07 के दौरान कृषि वृद्धि में मंदी बने रहने की आशा है। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2006-07 के दौरान कुल खाद्य उत्पादन 211.8 मिलियन टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष (5.2 प्रतिशत) की तुलना में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सारणी 2.6 : बचत-निवेश अंतर (1999-2000 की कीमतों पर)

(चालू बाजार कीमतों पर जीडीपी का प्रतिशत)

मद	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 अं.	2005-06 त्व.अनु.
1	2	3	4	5	6	7	8
बचत-निवेश अंतर (जीडीएस-जीडीसीएफ)	-1.1	-0.6	0.6	1.2	1.6	-0.4	-1.3
निजी क्षेत्र*	7.7	8.8	9.2	8.6	9.2	7.4	6.9
सार्वजनिक क्षेत्र*	-8.2	-8.8	-8.9	-6.6	-5.2	-4.7	-5.4
चालू खाता शेष	-1.0	-0.6	0.7	1.2	2.3	-0.8	-1.3
ज्ञापन :							
बहुमूल्य वस्तुएं@	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3	1.2
अं. : अर्न्तम त्व.अनु. : त्वरित अनुमान. जीडीएस : सकल घरेलू बचत, जीडीसीएफ : सकल देशी पूंजी निर्माण							
* : निजी और सार्वजनिक निवेश सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) को दर्शाते हैं, त्रुटियाँ और चूक समायोजित नहीं हैं।							
@ : बहुमूल्य वस्तुओं में सकल पूंजी निर्माण में बहुमूल्य वस्तुओं के अर्जन के लिए किए गए व्यय शामिल हैं।							
टिप्पणी : आंकड़े सीएसओ और रिजर्व बैंक आंकड़ों से लिए गए हैं। त्रुटियों और चूक के कारण कहीं-कहीं अलग-अलग हिस्सों का योग जोड़ के बराबर नहीं है।							

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2006

2.14 दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने के समय के संबंध में अनिश्चितता तथा इसके कालिक और स्थानिक वितरण का कृषि क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दो-तिहाई कृषि क्षेत्र असिंचित है, अतः कृषि संबंधी संभाव्यता काफी सीमा तक दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति और उसके निष्पादन द्वारा निर्धारित होती है। 30 जून 2006 को जारी भारतीय मौसम विभाग की व्यापक भविष्यवाणी के अनुसार देश के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून की बरसात कुल मिलाकर दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) का 92 प्रतिशत होने की संभावना है तथा इसमें +/- 4 प्रतिशत की प्रतिरूप भूल-चूक हो सकती है। तथापि, दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वास्तविक बरसात सामान्य का 99 प्रतिशत थी जिसके फलस्वरूप मिट्टी और जलाशयों की आर्द्रता की पुनःपूर्ति हुई।

2.15 यद्यपि दक्षिण-पश्चिम मानसून 2006 का समग्र निष्पादन पिछले साल जैसा ही था तथापि इसका स्थानिक वितरण पिछले साल की तुलना में विषम था। 36 मौसम उपखंडों में से 26 उपखंडों में (पिछले साल 32 उपखंडों में) संचयी बरसात अधिक / सामान्य थी तथा 10 उपखंडों में (पिछले साल के दौरान 4 उपखंडों में) संचयी बरसात कम/अपर्याप्त/नहीं के बराबर थी (सारणी 2.7)। मौसम के दौरान, समय के भीतर बरसात सुवितरित भी नहीं थी। जून और जुलाई के दूसरे से चौथे सप्ताह तक, अगस्त के अंतिम सप्ताह में और सितंबर 2006 के मध्य में बरसात में व्यापक कमी देखी गई। विशेष तौर पर मध्य भारत में अगस्त के पहले तीन सप्ताहों के दौरान हुई अधिक बरसात के कारण देश में बरसात के परिदृश्य में पुनर्जीवन देखा गया।

सारणी 2.7 : संचयी वर्षा

श्रेणी	उप खंडों की संख्या					
	दक्षिण-पश्चिम मानसून			उत्तर-पूर्व मानसून		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
	(जून 1 से सितंबर 30)			(अक्टूबर 1 से दिसंबर 31)		
1	2	3	4	5	6	7
अधिक	0	9	6	8	11	3
सामान्य	23	23	20	10	6	6
अपूर्ण	13	4	10	17	5	14
कम वर्षा/ वर्षा नहीं	0	0	0	1	14	13

स्रोत : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।

2.16 पूरे देश में कुल मिलाकर बरसात जून में सामान्य से कम (एलपीए से 13 प्रतिशत नीचे) तथा जुलाई (एलपीए से 2 प्रतिशत नीचे) और सितंबर में (एलपीए से 1 प्रतिशत नीचे) सामान्य के आसपास थी। तथापि, अतिरिक्त बरसात के साथ अगस्त में मौसम सक्रिय था (एलपीए से 5 प्रतिशत अधिक)। इस प्रकार, सिर्फ जून के महीने में दक्षिण-पश्चिम मानसून की बरसात में कमी देखी गई तथा वह बाद के महीनों में सामान्य के निकट बनी रही। 4 समरूप क्षेत्रों के बीच, उत्तर-पूर्व भारत, उत्तर-पश्चिम भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप में दक्षिण-पश्चिम मानसून की बरसात कम थी तथा उनमें क्रमशः एलपीए का 83 प्रतिशत, 94 प्रतिशत और 95 प्रतिशत बरसात हुई। देश भर में दक्षिण-पश्चिम मानसून की बरसात के सामान्य के आसपास होने में मुख्यतः केंद्रीय भारत में हुई अतिरिक्त बरसात (एलपीए का 116 प्रतिशत) का अंशदान था। उपखंड के स्तर पर पांच उपखंडों (अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा) में मौसम के अंत में थोड़े सूखे की स्थिति रही। 533 मौसम वैज्ञानिक जिलों में से, 130 जिलों (25 प्रतिशत) में सामान्य सूखा था जबकि 30 जिलों (6 प्रतिशत) में मौसम के अंत में सख्त सूखे की स्थिति रही।

जलाशय की स्थिति

2.17 केंद्रीय जल आयोग 76 प्रमुख जलाशयों में, जो देश की कुल जलाशयों की क्षमता का लगभग 63 प्रतिशत है, जल के कुल भंडारण पर निगरानी रखता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून मौसम के अंत में (28 सितंबर 2006 की स्थिति के अनुसार), पूर्ण जलाशय स्तर (एफएलआर) के 91 प्रतिशत पर कुल जल भंडार के साथ जलाशय की स्थिति पिछले साल की स्थिति (81 प्रतिशत) तथा पिछले 10 सालों के औसत (71 प्रतिशत) से उच्चतर थी। जलाशय की सुखद स्थिति के फलस्वरूप 2006-07 के दौरान रबी की फसल का उत्पादन तथा जल विद्युत बनाने की स्थिति अच्छी रहने की आशा है। 12 अप्रैल 2007 की स्थिति के अनुसार कुल जल भंडार एफएलआर का 35 प्रतिशत (29 मार्च 2006 को 32 प्रतिशत) था। दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य के आसपास रहने तथा जल भंडार स्तरों में सुधार को देखते हुए कृषि मंत्रालय ने 2006-07 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए 220 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया जो पिछले साल के 215 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक था (सारणी 2.8)।

उत्तर-पूर्व मानसून 2006

2.18 उत्तर-पूर्व मानसून (1 अक्टूबर 2006 से 31 दिसंबर 2006 तक) के दौरान दर्ज की गई संचयी बरसात, पिछले वर्ष की तदनुसार

1 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुष्कता सूचकांक में सामान्य स्तर से अंतर को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तथा तदनुसार सूखे को अत्यधिक सूखाग्रस्त (50 प्रतिशत से अधिक), सामान्य सूखाग्रस्त (26-50 प्रतिशत) तथा कम सूखाग्रस्त (25 प्रतिशत तक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.8 : फसल-वार लक्ष्य / उपलब्धियाँ

(मिलियन टन)

फसल	2004-05		2005-06		2006-07	
	ल	उ	ल	उ	ल	अ.अनु.
1	2	3	4	5	6	7
धान	93.5	83.1	87.8	91.8	92.8	91.1
गेहूँ	79.5	68.6	75.5	69.4	75.5	73.7
मोटे अनाज	36.8	33.5	36.5	34.1	36.5	32.9
दालें	15.3	13.1	15.2	13.4	15.2	14.1
कुल खाद्यान्न	225.1	198.4	215.0	208.6	220.0	211.8
तिलहन	26.2	24.4	26.6	28.0	29.4	23.3
गन्ना	270.0	237.1	237.5	281.2	270.0	322.9
कपास*	15.0	16.4	16.5	18.5	18.5	21.0
जूट और मेस्टा **	11.8	10.3	11.3	10.8	11.3	11.3

ल : लक्ष्य उ : उपलब्धि

अ.अनु. : 4 अप्रैल 2007 को तीसरा अग्रिम अनुमान।

* : मिलियन गट्टों में, प्रत्येक 170 किलोग्राम का।

** : मिलियन गट्टों में, प्रत्येक 180 किलोग्राम का।

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अवधि के दौरान सामान्य से 10 प्रतिशत अधिक की तुलना में, सामान्य से 21 प्रतिशत कम थी। 36 मौसम वैज्ञानिक उपखंडों में से, 9 उपखंडों में (पिछले साल 17 उपखंडों में) संचयी बरसात अधिक/सामान्य थी तथा 27 उपखंडों में (पिछले साल 19 उपखंडों में) बरसात कम/अपर्याप्त/नहीं के बराबर थी (सारणी 2.7)।

खरीफ 2006

2.19 सामान्य मानसून की पृष्ठभूमि में, खरीफ 2005 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन (109.9 मिलियन टन) में पिछले वर्ष की तुलना में

6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2006-07 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 108.4 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.4 प्रतिशत कम है (सारणी 2.9)। खरीफ के खाद्यान्नों में, जहां मोटे अनाजों (6.5 प्रतिशत) तथा दालों (0.8 प्रतिशत) के उत्पादन में गिरावट आई वहीं चावल (0.3 प्रतिशत) के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ। 2005-06 के दौरान तीव्र सुधार होने के बाद, 2006-07 के दौरान खरीफ के तिलहनों के उत्पादन में तेज गिरावट आने की आशा है। तथापि, 2003-04 से निरंतर वृद्धि होने के साथ 2006-07 के दौरान गन्ना और रूई का उत्पादन नई ऊंचाई तक पहुंचने की आशा है।

रबी 2006-07

2.20 रबी 2005-06 के दौरान खाद्यान्नों के पूर्व उत्पादन में 3.7 मिलियन टन की वृद्धि हुई और वह 98.7 मिलियन टन हो गया (सारणी 2.9)। फलस्वरूप, 208.6 मिलियन टन पर 2005-06 के लिए समग्र खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रबी 2006-07 के दौरान लाभकारी खुले बाजार तथा समर्थन मूल्यों सहित मिट्टी की अनुकूल आर्द्र स्थिति के फलस्वरूप बोने की स्थिति में सुधार हुआ। अब तक (27 अप्रैल 2007 तक) रबी फसलों के तहत बोया गया क्षेत्र एक साल पहले की तुलना में लगभग 2.2 प्रतिशत अधिक है। तिलहनों और चावल को छोड़कर, बोये गये क्षेत्र के रूप में हर प्रमुख फसल समूह में सुधार दिखाई दिया है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, के अनुसार तिलहनों के अंतर्गत कम व्याप्ति का मुख्य कारण मध्य प्रदेश में अलसी और सरसों के क्षेत्र का बंगाल चना के लिए तथा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूँ के लिए किया गया उपयोग है।

सारणी 2.9 : मौसमवार कृषि उत्पादन

(मिलियन टन)

फसलें	खरीफ			रबी		
	2004-05 उ	2005-06 उ	2006-07 अ.अनु.	2004-05 उ	2005-06 उ	2006-07 अ.अनु.
1	2	3	4	5	6	7
धान	72.2	78.3	78.5	10.9	13.5	12.5
गेहूँ	68.6	69.4	73.7
मोटे अनाज	26.4	26.7	25.0	7.1	7.3	7.9
दालें	4.7	4.9	4.8	8.4	8.5	9.3
कुल खाद्यान्न	103.3	109.9	108.4	95.1	98.7	103.4
तिलहन	14.1	16.8	13.9	10.2	11.2	9.4
गन्ना	237.1	281.2	322.9
कपास*	16.4	18.5	21.0
जूट और मेस्टा **	10.3	10.8	11.3

उ : उपलब्धि। अ.अनु. : 4 अप्रैल 2007 को तीसरा अग्रिम अनुमान (2006-07)।

.. : उपलब्धि नहीं। * : मिलियन गट्टों में, प्रत्येक 170 किलोग्राम का। ** : मिलियन गट्टों में, प्रत्येक 180 किलोग्राम का।

स्रोत : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

2.21 रबी की फसल की समय पर बुवाई तथा उसके क्षेत्र में सुधार के कारण 2006-07 के दौरान रबी फसलों का भविष्य उज्ज्वल हुआ है। तदनुसार, तीसरे अग्रिम अनुमान ने रबी के खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान 103.4 मिलियन टन लगाया गया है जो पिछले साल की तुलना में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। गेहूँ का कुल उत्पादन 73.7 मिलियन टन होने की आशा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, उठाव और भंडारण

2.22 2006-07 के दौरान खाद्यान्नों (चावल और गेहूँ) की सरकारी खरीद 35.9 मिलियन टन थी जो पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 13.2 प्रतिशत कम थी (सारणी 2.10)। इसका मुख्य कारण था 2006-07 के दौरान, पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के 14.8 मिलियन टन की तुलना में, 9.2 मिलियन टन पर गेहूँ की अत्यंत कम

सारणी 2.10 : खाद्य भंडार का प्रबंधन

(मिलियन टन)

वर्ष / माह	खाद्यान्न का प्रारंभिक स्टॉक	खाद्यान्न की खरीद	खाद्यान्नों का उठाव				अंतिम स्टॉक	सुरक्षित भंडार मानक \$
			पीडीएस	ओडब्ल्यूएस	ओएमएस-देशी	निर्यात		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005								
अप्रैल	18.0	14.2	2.4	1.0	0.0	0.0	28.5	16.2
मई	28.5	3.0	2.5	0.8	0.0	0.0	27.9	
जून	27.9	0.9	2.5	1.7	0.0	0.0	25.1	
जुलाई	25.1	0.8	2.8	0.8	0.1	0.0	21.4	26.9
अगस्त	21.4	0.4	2.6	0.8	0.1	0.0	18.4	
सितंबर	18.4	0.4	2.7	0.7	0.1	0.0	15.5	
अक्टूबर	15.5	7.5	2.7	0.5	0.0	0.0	19.8	16.2
नवंबर	19.8	2.7	2.3	0.5	0.1	0.0	19.0	
दिसंबर	19.0	2.9	2.7	0.7	0.2	0.0	19.3	
2006								
जनवरी	19.3	4.0	2.7	0.8	0.1	0.0	19.5	20.0
फरवरी	19.5	2.9	2.7	0.6	0.3	0.0	18.3	
मार्च	18.3	1.9	2.5	0.9	0.2	0.0	16.6	
अप्रैल	16.6	10.3	2.5	0.3	0.0	0.0	22.8	16.2
मई	22.8	2.2	2.9	0.4	0.0	0.0	22.3	
जून	22.3	1.5	2.6	0.6	0.0	0.0	20.5	
जुलाई	20.5	0.8	2.7	0.4	0.0	0.0	17.1	26.9
अगस्त	17.1	0.5	2.7	0.4	0.0	0.0	15.5	
सितंबर	15.5	0.2	2.6	0.5	0.0	0.0	12.6	
अक्टूबर	12.6	8.0	2.5	0.3	0.0	0.0	18.6	16.2
नवंबर	18.6	2.0	2.5	0.4	0.0	0.0	17.8	
दिसंबर	17.8	2.6	2.6	0.3	0.0	0.0	17.5	
2007								
जनवरी	17.5	4.3	2.7	0.4	0.0	0.0	18.1	20.0
फरवरी	18.1	2.4	2.7	0.5	0.0	0.0	19.1	
मार्च	19.1	1.2	
अप्रैल	..	8.7	16.2
मई*	..	1.4	
ज्ञापन :								
2005-06 @	18.0	41.4	28.6	8.9	0.9	0.0	18.3	
2006-07 @	16.6	35.9	28.9	4.6	0.0	0.0	19.1	
2007-08 *	..	10.1	

पीडीएस : सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

ओडब्ल्यूएस : अन्य कल्याणकारी योजनाएँ।

ओएमएस : खुला बाजार बिक्री।

\$: 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी में कायम रखे जाने वाले न्यूनतम सुरक्षित भंडार मानकों को, 29 मार्च 2005 से नई सुरक्षित भंडार नीति के अंतर्गत, संशोधित किया गया है।

* : 8 मई 2007 तक खरीद।

@ : फरवरी के अंत तक उठाव तथा 1 मार्च का अंतिम स्टॉक।

.. : उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : अंतिम स्टॉक आँकड़े, प्रारंभिक स्टॉक और खरीदी जोड़ने और उठाव को घटाने से प्राप्त आँकड़ों से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि स्टॉकों में मोटे अनाज भी शामिल हैं।

स्रोत : उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार।

सरकारी खरीद। इसी तरह, 2006-07 के दौरान (1 अप्रैल से 28 फरवरी 2007 तक) चावल तथा गेहूँ का उठाव पिछले वर्ष की तुलनीय अवधि की तुलना में 12.7 प्रतिशत कम था। मुख्यतः अन्य कल्याण योजनाओं के तहत उठाव में आई तेज गिरावट के फलस्वरूप उक्त उठाव में गिरावट आई। इसके अलावा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूँ के उठाव में भी 14.5 प्रतिशत की गिरावट आई। भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का कुल स्टॉक 1 मार्च 2007 को 19.1 मिलियन टन था जो पिछले साल की तदनुसूचित अवधि के 18.3 मिलियन टन की तुलना में 4.3 प्रतिशत अधिक था। 2007-08 के दौरान (8 मई 2007 तक) 10.1 मिलियन टन पर गेहूँ और चावल की कुल सरकारी खरीद पिछले वर्ष की तदनुसूचित अवधि की 11.0 मिलियन टन की तुलना में 7.5 प्रतिशत कम थी।

हाल के नीतिगत पहल

2.23 ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में की गई परिकल्पना के अनुसार लगभग 4.0 प्रतिशत कृषि वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से कृषि क्षेत्र को प्रभावित करनेवाली समस्याओं का निपटारा करने के लिए पिछले साल के दौरान सरकार ने कई नए पहल किए। अन्य बातों के साथ-साथ ये इस प्रकार हैं - (i) शुष्क भूमि तथा बरसात से पोषित कृषि के उन्नयन और प्रबंधन में समर्थन देने के लिए नवम्बर 2006 में राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण बनाना, (ii) विपणन में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के परामर्श से कृषि संबंधी माल के विपणन के लिए मॉडल कानून तैयार करना, (iii) जनवरी 2006 में अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनर्जीवन के लिए पैकेज, (iv) खरीफ 2006-07 से शुरू करके 7.0 प्रतिशत ब्याज दर पर 3,00,000 रुपए तक की मूलराशि फसल ऋण के लिए उधार देने हेतु ब्याज सहायता, (v) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में जिन जिलों में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं अधिक होती हैं ऐसे 31 जिलों में किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज, तथा (vi) किसानों के समूह, पंचायती राज संस्थाओं और निजी क्षेत्र को शामिल कर जीविका की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से जुलाई 2006 में राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना शुरू करना।

2.24 अधिक व्यापक आधार वाली तथा समावेशक वृद्धि के संवर्धन के लिए केंद्रीय बजट 2007-08 में कृषि वृद्धि को बढ़ावा देने की बात सरकारी कार्यसूची में ऊपर रखी गई है। आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में 2,25,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण का लक्ष्य रखा गया है जिसका उद्देश्य 5 मिलियन नए किसानों को बैंकिंग प्रणाली की परिधि में लाना है। ग्रामीण ऋण सहकारिताओं के पुनर्वित्त के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु, नाबार्ड को अनुमति दी गई है कि वह 5,000 करोड़ रुपए के ग्रामीण बांड जारी करे तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया है कि वे उल्लेखनीय शाखा विस्तार कार्यक्रम तैयार करें। साथ ही, बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के दायरे में क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को लाया जाए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एनआरई/एफसीएनआर जमा स्वीकार करने के लिए अनुमति दी जाए तथा ऋणात्मक निवल मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चरणबद्ध कार्यक्रम में पुनः पूंजीकृत किया जाए। वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए बजट में प्रस्ताव है कि विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक हस्तक्षेपों की लागत पूरी करने के लिए नाबार्ड में एक निधि तथा प्रौद्योगिकी को अपनाने की लागत पूरी करने के लिए एक प्रौद्योगिकी निधि बनाई जाए।

2.25 किसानों पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने ज्ञान की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जिसकी वजह से कृषि की उत्पादकता ने बाधा पड़ती है। देश के अधिकांश हिस्सों में कृषि पद्धतियां इष्टतम नहीं हैं। 2007-08 के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में वर्तमान प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग करने के लिए अच्छी विस्तार प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बजट में यह भी प्रस्ताव है कि (i) समेकित तिलहन, आयल पाम, दाल और मक्का विकास कार्यक्रम का विस्तार किया जाए, (ii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत खर्च बढ़ाया जाए तथा (iii) फसलों की उत्पादकता सुधारने के लिए जल निकायों तथा भूमिगत रिचार्ज को बहाल किया जाए।

उद्योग

2.26 2006-07 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का लगातार पांचवें वर्ष तेज गति से विस्तार हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में इस उछाल का मुख्य वाहक विनिर्माण कार्य है, जिसने औद्योगिक वृद्धि में 90 प्रतिशत से अधिक का अंशदान किया है। 2006-07 के दौरान औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में 11.3 प्रतिशत की तेज द्विअंकीय वृद्धि दर्ज की गई जो 1995-96 से (13.1 प्रतिशत) अधिकतम है (सारणी 2.11)। इस तीव्र वृद्धि ने अंशदान करने वाले मुख्य कारक हैं - उपभोग की सशक्त मांग, निवेश में वृद्धि तथा क्षमता में वृद्धि। यह वृद्धि सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह विविधीकृत है। हाल के महीनों में मध्यवर्ती माल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि भारतीय उद्योग की नए सिरे से अर्जित गतिशीलता और स्पर्धात्मकता को रेखांकित करती है। मूल तथा पूंजीगत माल क्षेत्रों में अच्छा कार्य-निष्पादन बने रहना धारित उच्च औद्योगिक वृद्धि के लिए आधार प्रदान करता है।

2.27 2006-07 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र ने 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 1995-96 से, जब 14.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, सर्वाधिक है। कच्चे तेल के उच्चतर उत्पादन का लाभ उठाते हुए खनन क्षेत्र ने 5.1 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की। कच्चे तेल का अधिक उत्पादन जुलाई 2005 में मुंबई हाई में आग लगने के बाद उत्पादन में आई रुकावट से सुधार की स्थिति दर्शाता है। इस अवधि में बिजली क्षेत्र ने 7.2 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की जो मुख्यतः ताप बिजली संयंत्रों में अधिक संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) तथा जल बिजली उत्पादन में द्विअंकीय वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है।

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.11: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक-मासिक वृद्धि

(प्रतिशत)

माह / भार	सामान्य		विद्युत		खनन और उत्खनन		विनिर्माण	
	(100.00)		(10.17)		(10.47)		(79.36)	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	8.1	9.9	3.1	5.9	2.8	3.4	9.2	11.0
मई	10.8	11.7	10.5	5.0	5.2	2.9	11.3	13.3
जून	12.2	9.7	9.6	4.9	4.8	4.7	13.2	10.7
जुलाई	4.7	13.2	-0.9	8.9	-1.9	5.1	6.0	14.3
अगस्त	7.6	10.3	7.9	4.1	-2.5	-1.7	8.5	11.9
सितंबर	7.2	12.0	-0.8	11.3	-1.9	4.3	8.9	12.7
अक्टूबर	9.8	4.5	7.7	9.7	-0.1	5.9	10.9	3.8
नवंबर	6.0	15.8	3.4	8.7	-2.1	8.8	7.0	17.2
दिसंबर	5.7	13.4	3.4	9.1	-0.1	6.1	6.4	14.5
जनवरी	8.5	11.4	6.4	8.3	2.0	7.2	9.4	12.1
फरवरी	8.8	10.8	9.1	3.3	3.8	7.1	9.2	11.9
मार्च	8.9	12.9	3.4	7.9	2.0	6.2	10.1	14.1
अप्रैल-मार्च	8.2	11.3	5.2	7.2	1.0	5.1	9.1	12.3

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

2.28 विनिर्माण क्षेत्र में बना हुआ उछाल हाल के वर्षों में औद्योगिक वृद्धि की उल्लेखनीय विशेषता है। 2006-07 के दौरान, 16 विनिर्माण उद्योग समूह ने (द्विअंकीय स्तर वर्गीकरण के रूप में) सकारात्मक वृद्धि दर्ज की (सारणी 2.12)। उल्लेखनीय रूप से मशीनरी तथा उपकरण और रसायन तथा रासायनिक उत्पाद नामक दो उद्योगों ने,

जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 24 प्रतिशत भारांक है, 2006-07 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 32.9 प्रतिशत का उल्लेखनीय अंशदान किया। 'धातु उत्पाद तथा पुर्जे', 'लकड़ी और लकड़ी उत्पाद', 'चमड़ा तथा चमड़ा और फर उत्पाद', 'कागज और कागज उत्पाद' तथा 'ऊन, रेशम और मानव निर्मित रेशा वस्त्र' में टर्नअराउंड आया

सारणी 2.12 : विनिर्माण उद्योगों में वृद्धि (2-अंक स्तर वर्गीकरण) - अप्रैल-मार्च 2006-07

15 प्रतिशत से ऊपर	10-15 प्रतिशत	0-10 प्रतिशत	ऋणात्मक
1	2	3	4
1. लकड़ी और लकड़ी उत्पाद, फर्नीचर और जुड़नार (29.1)	1. परिवहन उपकरण और कल पुर्जे (14.9)	1. रसायन और रासायनिक उत्पाद, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पादों को छोड़कर (9.2)	1. जूट और अन्य वनस्पति रेशों के वस्त्र (-17.2)
2. आधारभूत धातु और मिश्रधातु (22.8)	2. सूती वस्त्र (14.8)	2. कागज और कागज उत्पाद (8.3)	
	3. मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपकरण के अलावा (14.0)	3. ऊन, रेशम और मनुष्य-निर्मित रेशों के कपड़े (8.2)	
	4. गैर धात्विक खनिज उत्पाद (12.8)	4. खाद्य उत्पाद (8.2)	
	5. रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद (12.7)	5. अन्य विनिर्माण उद्योग (6.5)	
	6. धातु उत्पाद और कल पुर्जे (11.4)	6. चमड़ा और चमड़ा और फर उत्पाद (0.3)	
	7. मादक पेय, तंबाकू और संबंधित उत्पाद (11.3)		
	8. वस्त्र उत्पाद (परिधान समेत) (11.2)		

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वृद्धि दर के हैं।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.13 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) की वृद्धि में क्षेत्रवार योगदान
(अप्रैल-मार्च)

(प्रतिशत)

उद्योग समूह	आइआइपी में भार	वृद्धि			तुलनात्मक योगदान		
		2004-05	2005-06	2006-07 अ	2004-05	2005-06	2006-07 अ
1	2	3	4	5	6	7	8
मूल माल	35.57	5.5	6.7	10.2	20.9	25.4	27.5
पूँजीगत माल	9.26	13.9	15.8	17.7	16.4	20.0	17.4
मध्यवर्ती माल	26.51	6.1	2.5	11.7	20.3	8.4	26.7
उपभोक्ता वस्तुएँ (क +ख)	28.66	11.7	12.0	10.0	42.6	46.3	28.7
क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ	5.36	14.3	15.3	9.0	12.9	14.9	6.7
ख) उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ	23.3	10.8	11.0	10.3	29.6	31.4	22.0
आइआइपी	100.0	8.4	8.2	11.3	100.0	100.0	100.0

अ : अनंतिम
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

जबकि 'जूट और अन्य वनस्पति रेशा वस्त्र' ने वर्ष के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की।

2.29 उपयोग आधारित वर्गीकरण के रूप में उद्योग का निष्पादन 2006-07 के दौरान उतना ही प्रभावी था। आधारभूत माल क्षेत्र ने 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो 1995-96 से सर्वाधिक वृद्धि है (सारणी 2.13)। आधारभूत माल क्षेत्र की उच्चतर वृद्धि में सीमेंट की तीव्र वृद्धि, उच्च स्पीड डीजल तथा अन्य विभिन्न लोहा और इस्पात उत्पादों यथा कार्बन स्टील, दंड और छड़, पाइप और ट्यूब, स्ट्रक्चरल आदि में हुई तेज वृद्धि ने अंशदान किया। मध्यवर्ती माल क्षेत्र में हुई 11.7 प्रतिशत की वृद्धि भी 1995-96 से (19.3 प्रतिशत) सर्वाधिक है। इस वृद्धि के प्रमुख वाहक कुछ धागों, पोलिएस्टर रेशा, विस्कोस स्टेपल रेशा, पीवीसी पाइप और ट्यूब तथा चमकीले टाइलों/सिरामिक टाइलों में हुई उच्चतर वृद्धि हैं। 2006-07 के दौरान पूँजीगत माल क्षेत्र ने भी, 2005-06 के 15.8 प्रतिशत की तुलना में, 17.7 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की तथा इसे पूर्ण ट्रैक्टर, बाइलर, डीजल इंजन, वस्त्र मशीनरी, सामान हैंडल करनेवाले उपकरण, संरक्षण प्रणाली/

स्विच-बोर्ड तथा प्रोसेस नियंत्रक साधनों ने बनाए रखा। 2006-07 में उपभोक्ता माल क्षेत्र ने, पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि के दौरान हुई 12.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, 10.0 प्रतिशत की सामान्यतः न्यूनतर वृद्धि दर्ज की। यह मुख्यतः कुछ खाद्य उत्पादों के ऋणात्मक निष्पादन तथा खाद्य तेलों तथा दवाओं के कारण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं तथा गैर-टिकाऊ वस्तुओं दोनों की वृद्धि में कमी के कारण हुआ।

मूलभूत संरचना

2.30 2006-07 के दौरान, 8.6 प्रतिशत पर मूल इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योगों में हुई समग्र वृद्धि (2005-06 में हुई 6.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में) 1999-00 से सर्वाधिक थी (सारणी 2.14)। उच्चतर वृद्धि मुख्यतः अवधि के दौरान बिजली एवं पेट्रोल परिशोधन उत्पादों में सशक्त वृद्धि तथा कच्चे पेट्रोल की वृद्धि में हुए टर्नअराउंड को प्रतिबिंबित करती है। मूल क्षेत्र समूहों में पेट्रोल परिशोधन उत्पादों ने उक्त अवधि के दौरान 12.6 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की।

सारणी 2.14 : ढांचागत उद्योगों की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	आइआइपी में भारांक	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अ.)
1	2	3	4	5	7	8
1. बिजली	10.17	3.2	5.1	5.2	5.2	7.2
2. कोयला	3.22	4.5	5.1	6.2	6.6	5.9
3. तैयार स्टील	5.13	7.3	9.8	8.4	11.2	10.9
4. सीमेंट	1.99	8.8	6.1	6.6	12.4	9.1
5. कच्चा पेट्रोलियम	4.17	3.4	0.7	1.8	-5.3	5.6
6. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	2.00	4.9	8.2	4.3	2.4	12.6
संमिश्र सूचकांक	26.68	5.0	6.1	5.8	6.2	8.6

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

2.31 सुदृढ़ देशी मांग के बावजूद, ऊंचे आधार ने इस्पात के उत्पादन में द्विअंकीय परंतु सामान्य वृद्धि में अंशदान किया। बढ़ती हुई देशी और बाहरी मांग ने सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि को समर्थन देना जारी रखा, हालांकि आधार प्रभाव के कारण कुछ मंदी आई थी। सितंबर में कोयला उत्पादन में हुई ऋणात्मक वृद्धि वर्ष के दौरान कोयला क्षेत्र में न्यूनतर वृद्धि में परिणत हुई। मुंबई हाई ने ओएनजीसी के संयंत्र में कच्चे तेल का उत्पादन बहाल होने के कारण तथा निजी एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के कारण कच्चे पेट्रोल ने टर्नअराउंड दर्ज किया। पूरे देश में स्थित विभिन्न तेलशोधन शालाओं में उच्चतर क्षमता उपयोग तथा पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों के उच्चतर निर्यात ने पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद को प्रभावी वृद्धि दर्ज करने के लिए समर्थ बनाया।

सेवा क्षेत्र

2.32 सेवा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में भारत की वृद्धि का प्राथमिक वाहक रहा है। 2005-06 के दौरान सेवा क्षेत्र में, 2004-05 में हुई 10.0 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर, 10.3 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि जारी रही। सेवा क्षेत्र ने वृद्धि की गति बनाए रखते हुए, उच्चतर आधार (2005 की उसी अवधि में 9.8 प्रतिशत) के बावजूद, अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान एक प्रभावी द्विअंकीय वृद्धि (10.7 प्रतिशत) दर्ज की। 'व्यापार, होटल, परिवहन और संचार' की अगुवाई में वृद्धि में तेजी आई जिसने अवधि के दौरान उप क्षेत्रों में 13.3 प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की (सारणी 2.15)।

2.33 औद्योगिक क्षेत्र के साथ सहक्रिया में वृद्धि तथा अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण व्यापार, परिवहन, संचार, निर्माण और वित्तीय सेवाओं में सुदृढ़ वृद्धि हुई। व्यापार क्षेत्र में द्विअंकीय वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि निर्यात और आयात दोनों ने तेज वृद्धि दर्ज की। देशी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, व्यवसाय और अवकाश दोनों, में तेज वृद्धि ने होटल उद्योग की

वृद्धि में मदद की। रेलवे के विकसित हो रहे राजस्व अर्जक भाड़ा ट्रैफिक तथा हवाई क्षेत्र में तेज वृद्धि ने परिवहन क्षेत्र को आगे बढ़ाया। सेल फोन के अभिदाताओं के आधार में तेज वृद्धि तथा ब्राडबैंड कनेक्शन में तीव्र वृद्धि में संचार क्षेत्र ने तेज वृद्धि को समर्थन दिया। 'वित्तपोषण, बीमा, भू-संपदा तथा व्यावसायिक सेवा' नामक उप क्षेत्र को बैंक जमाराशियों तथा खाद्येतर ऋण में अधिक वृद्धि, सार्वजनिक तथा निजी दोनों बीमा कंपनियों के बीमा कारोबार में वृद्धि और बढ़ी हुई व्यवसाय प्रोसेस आउटसोर्सिंग - सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात से फायदा हुआ। 'समुदाय, समाज और वैयक्तिक सेवा' नामक उप क्षेत्र में योजना और योजनेतर दोनों तरह के व्यय में हुई वृद्धि के कारण उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा तथा व्यवसाय-प्रक्रिया आउटसोर्सिंग

2.34 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुशल, कम खर्चीले अंग्रेजीभाषी भारतीय कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग के कारण निर्यात उन्मुख सूचना प्रौद्योगिकी तथा व्यवसाय-प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्रों में अच्छा कार्य-निष्पादन जारी रहा। सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आइटीईएस) और बीपीओ खंडों ने सेवा क्षेत्र की वृद्धि बनाए रखने में उल्लेखनीय अंशदान किया है। सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ (नैसकॉम) के अनुसार विदेशी तथा देशी उपभोक्ताओं से मांग में हुई तेज वृद्धि के कारण 2005-06 में आइटीईएस-बीपीओ का राजस्व उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 29.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारतीय आइटी-आइटीईएस उद्योग के निर्यात में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उसने 2004-05 के 17.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2005-06 में 23.6 बिलियन अमरीकी डालर का राजस्व कमाया। वैश्विक सुपुर्दगी मॉडल के विकास तथा भारतीय आधार वाली बड़ी कंपनियों के साथ आइटी आउटसोर्सिंग का बड़ा सौदा होने जैसे कारकों

सारणी 2.15 : सेवा क्षेत्र के उप - क्षेत्रों में तिमाही वृद्धि दर (आधार: 1999-2000)

(प्रतिशत)

उप-क्षेत्र	2004-05				2005-06				2006-07		
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निर्माण	12.4	8.5	14.5	13.5	12.7	11.3	16.6	12.0	9.5	9.8	9.8
व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार	11.7	12.2	10.2	11.0	10.2	9.5	10.0	12.9	13.1	13.8	13.0
वित्तपोषण, बीमा, जमीन जायदाद एवं कारोबारी सेवाएं	9.7	8.4	10.6	10.7	8.9	10.6	9.8	10.5	9.0	9.5	11.6
सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	11.2	5.1	8.9	12.7	7.5	7.9	8.3	7.6	7.4	6.9	7.5
सेवाएं	11.2	9.1	10.4	11.6	9.5	9.5	10.3	11.0	10.4	10.7	11.1
कारक लागत पर जीडीपी	8.1	6.9	5.5	8.6	8.4	8.0	9.3	9.3	8.9	9.2	8.6

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

ने निर्यात निष्पादन की उछाल में अंशदान किया। हाल के वर्षों में बड़े ग्राहकों को अपनाने, विदेशों में विलय और अधिग्रहण तथा स्थिर मूल्य मॉडल की ओर उद्योग के झुकाव के जरिए आइटी समर्थित तथा बीपीओ खंड में भारत की शक्ति बढ़ी है।

औद्योगिक संभावना

2.35 हाल के वर्षों में निरंतर अच्छा कार्य करनेवाला औद्योगिक क्षेत्र सशक्त उपभोग मांग, निवेश में वृद्धि तथा क्षमता में वृद्धि के समर्थन से 2006-07 के दौरान उल्लसित रहा। 2006-07 में खनन क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ। साधारण वृद्धि होने की आशा है क्योंकि इस्पात एवं पावर कंपनियों द्वारा उनके अपने उपभोग के लिए कोयले के भंडार को हाल में डब्लाक करने से देश में कोयला उत्पादन के कामकाज में वृद्धि होगी। पावर का क्षेत्र गैस आपूर्ति में कमी के कारण भुगत रहा है जिसके कारण गैस आधारित संयंत्र कम क्षमता पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि अच्छी तरह विविधीकृत है। देश में अच्छे औद्योगिक वातावरण को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को द्विअंकीय स्तर पर बनाये रखने की आशा है।

II. राजकोषीय स्थिति

केंद्र सरकार के वित्त

2.36 सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मौलिक तत्वों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय बजट, 2007-08 प्रस्तुत किया गया, हालांकि मुद्रास्फीति के क्षेत्र में कुछ चिंता प्रकट की गई। बजट में राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकोषीय सुधार को और सुदृढ़ करने की वचनबद्धता व्यक्त की गई है तथा राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में कटौती करने के प्रस्ताव के साथ सामाजिक क्षेत्र के व्यय के लिए उच्चतर निधियां आबंटित की गईं।

2.37 2007-08 के बजट में मुख्यतः तीव्रतर और अधिक समावेशक वृद्धि प्राप्त करने पर बल दिया गया। समावेशक वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बजट संसाधनों का अधिकांश भाग सरकार के आठ प्रमुख कार्यक्रमों के लिए आबंटित किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार शामिल हैं। वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए, बजट में बजटेतर संसाधनों को जुटाने और निवेश, विशेष तौर पर मूलभूत संरचना में निवेश, के लिए उनके उत्तोलन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर नीतियों का प्रस्ताव किया गया है।

2.38 बजट में सामान्य और स्थिर कर दरों तथा करदाता के अनुरूप कर कानूनों को लागू करने की रणनीति अपनाकर कर के क्षेत्र में प्रभावी

कार्य-निष्पादन जारी रखने की मंशा व्यक्त की गई है। प्रत्यक्ष करों में रणनीति इस प्रकार है (क) कर संरचना को युक्तयुक्त करके तथा कर आधार बढ़ाकर और सामान्य कर दर बनाये रखकर कर संरचना के भीतर विकृतियों को न्यूनतम करना, और (ख) कर प्रशासन की क्षमता और प्रभाविता को सुधारना ताकि उच्चतर निवारण स्तर के माध्यम से ऐच्छिक अनुपालन को बढ़ाया जा सके। अप्रत्यक्ष करों के मामले में रणनीति यह है कि सीमा शुल्क कम करके उसे पूर्वी एशियाई देशों के तुलनीय स्तरों पर लाया जाए, कर आधार को बढ़ाया जाए और उत्पाद शुल्क को **सेनवैट** दर पर अभिमुख किया जाए। सेवा कर के मामले में, यह रणनीति है कि कर आधार बढ़ाया जाए तथा साथ ही छोटे सेवा प्रदाताओं को छूट दी जाए। अप्रत्यक्ष करों के मामले में करनीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करना तथा 1 अप्रैल 2010 तक पूर्णतः समन्वित माल और सेवा कर को लागू करने के लिए कदम उठाना है।

संशोधित अनुमान 2006-07²

2.39 2006-07 के संशोधित अनुमानों में सभी प्रमुख घाटा संकेतकों यथा, जीडीपी से संबद्ध राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा में उनके बजट स्तरों की तुलना में सुधार दिखाई देता है। घाटा संकेतकों में मुख्यतः कर तथा करेतर दोनों प्रकार की राजस्व प्राप्तियों में सुधार, जिसने उच्चतर व्यय को प्रतितुलित कर दिया, के कारण कटौती हुई। समस्त व्यय राजस्व व्यय, विशेषतः ब्याज अदायगी, उर्वरक और ब्याज सब्सिडी और योजनेतर रक्षा से इतर पूंजीगत परिव्यय, के कारण बजट अनुमानों की तुलना में अधिक था। योजना व्यय बजट अनुमानों के अनुरूप था।

2.40 संशोधित अनुमानों में राजस्व घाटा 2.1 प्रतिशत के बजट स्तर की तुलना में 2006-07 में सकल देशी उत्पाद का 2.0 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों में 19,866 करोड़ रुपए (4.9 प्रतिशत) के उल्लेखनीय सुधार, जिसने राजस्व व्यय में वृद्धि को प्रतितुलित कर दिया, के कारण राजस्व घाटे में गिरावट आई। राजस्व घाटे में गिरावट के बावजूद सकल राजकोषीय घाटा ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों में गिरावट तथा योजनेतर रक्षा से इतर पूंजी परिव्यय में वृद्धि के कारण बजट स्तर की तुलना में 3,642 करोड़ रुपए (2.4 प्रतिशत) अधिक था। तथापि, सकल देशी उत्पाद के संबंध में यह 3.8 प्रतिशत के बजट अनुमानों की तुलना में 3.7 प्रतिशत पर कम था। सकल देशी उत्पाद के 0.1 प्रतिशत पर प्राथमिक घाटा बजट अनुमानों की तुलना में 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों में 30.8 प्रतिशत कम था (सारणी 2.16)।

2 इस खंड में अन्यथा उल्लेख न किए जाने पर 2006-07 की सभी तुलनाएं बजट अनुमानों के साथ की गई हैं।

सारणी 2. 16: केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक

(करोड़ रुपए)

मद	2005-06 (खाते)	2006-07 (बअ)	2006-07 (संअ)	2007-08 (बअ)	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
					स्तंभ 3 की तुलना में 4	स्तंभ 4 की तुलना में 5
1	2	3	4	5	6	7
सकल राजकोषीय घाटा	1,46,435 (4.1)	1,48,686 (3.8)	1,52,328 (3.7)	1,50,948 (3.3)	2.4	-0.9
राजस्व घाटा	92,299 (2.6)	84,727 (2.1)	83,436 (2.0)	71,478 (1.5)	-1.5	-14.3
सकल प्राथमिक घाटा	13,805 (0.4)	8,863 (0.2)	6,136 (0.1)	-8,047 (-0.2)	-30.8	-231.1

बअ : बजट अनुमान । संअ : संशोधित अनुमान।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत हैं।

2.41 2006-07 के लिए संशोधित अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों में बजट के स्तर से 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2006-07 के संशोधित अनुमानों में कुल कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में 25,695 करोड़ रुपए अधिक था। सभी करों के तहत वसूली बजट स्तर की तुलना में अधिक होने की आशा है। हाल ही में लागू किए गए करों में 2006-07 में सीमांत लाभ कर से 5,500 करोड़ रुपए, प्रतिभूति लेनदेन कर से 3,750 करोड़ रुपए तथा बैंकिंग नकदी लेनदेन कर से 550 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। निवल कर राजस्व [सकल कर राजस्व घटा केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ)] में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वह जीडीपी का 8.4 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.17)।

2.42 ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों के तहत, ऋणों और अग्रिमों की वसूली में बजट अनुमानों की तुलना में 31.9 प्रतिशत की गिरावट आई (सारणी 2.17)। बारहवें योजना आयोग के अधिनिर्णय के तहत ऋण माफी के प्रभाव से राज्य सरकारों के दिए गए ऋणों की वसूली 2006-07 के संशोधित अनुमानों में 4,102 करोड़ रुपए कम होने का अनुमान है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सांविधिक निकायों आदि से वसूली में 1,596 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है।

2.43 2006-07 के संशोधित अनुमानों में राजस्व व्यय बजट अनुमानों की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक था, जबकि पूंजीगत व्यय में बजट अनुमानों की तुलना में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई (सारणी 2.18)। ब्याज अदायगी, उर्वरक एवं ब्याज सब्सिडी, राज्यों को अनुदान तथा पेंशन के कारण राजस्व व्यय अधिक था। पूंजीगत व्यय में रक्षेत्र पूंजी परिव्यय तथा ऋण और अग्रिम बजट अनुमानों की तुलना में अधिक थे।

बजट अनुमान 2007-08³

2.44 पिछले साल लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, 2007-08 के केंद्रीय बजट में एफआरबीएम नियमावली, 2004 में किए गए उल्लेख के अनुसार राजकोषीय सुधार को और मजबूत करने के प्रस्ताव हैं। तदनुसार, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा, सकल राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा जैसे प्रमुख घाटा संकेतकों के पिछले वर्ष के 2.0 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में क्रमशः 1.5 प्रतिशत, 3.3 प्रतिशत और -0.2 प्रतिशत पर कम होने का बजट अनुमान लगाया गया है (सारणी 2.16)। 2007-08 के केंद्रीय बजट में भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की ईक्विटी धारिता अर्जित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। तथापि यह लेनदेन पूंजीगत व्यय द्वारा तुलना करने पर ऋणोत्तर पूंजी प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया है तथा घाटा संकेतकों पर इसका प्रभाव नहीं होगा।

2.45 2007-08 में राजस्व प्राप्तियों में 2006-07 में दर्ज की गई 21.8 प्रतिशत की उच्च वृद्धि के ऊपर 14.9 प्रतिशत वृद्धि का बजट अनुमान लगाया गया है जो प्राथमिक तौर पर सकल कर वसूलियों में 2006-07 की 27.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। प्रत्यक्ष करों में निगम कर की वसूलियों में 2006-07 की 44.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2007-08 में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। वैयक्तिक आय कर से प्राप्त राजस्व में 2006-07 की 29.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 19.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, सीमा शुल्क के तहत वसूलियों में एक वर्ष पूर्व के 25.7 प्रतिशत की तुलना में 20.7 प्रतिशत

3 इस खंड में अन्यथा उल्लेख न किए जाने पर 2007-08 की सभी तुलनाएं 2006-07 के संशोधित अनुमानों के साथ की गई हैं।

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.17 : केंद्र की प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (खाते)	2006-07 (बअ)	2006-07 (संअ)	2007-08 (बअ)	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
					स्तंभ 3 की तुलना में 4	स्तंभ 4 की तुलना में 5
1	2	3	4	5	6	7
कुल प्राप्तियाँ (1+2)	5,06,123 (14.2)	5,63,991 (14.3)	5,81,637 (14.2)	6,40,521 * (13.8)	3.1	10.1
1. राजस्व प्राप्तियाँ	3,47,462 (9.7)	4,03,465 (10.2)	4,23,331 (10.3)	4,86,422 (10.5)	4.9	14.9
i) कर आय (निवल)	2,70,264 (7.6)	3,27,205 (8.3)	3,45,971 (8.4)	4,03,872 (8.7)	5.7	16.7
ii) कर से इतर आय	77,198 (2.2)	76,260 (1.9)	77,360 (1.9)	82,550 (1.8)	1.4	6.7
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	1,58,661 (4.4)	1,60,526 (4.1)	1,58,306 (3.9)	1,54,099 * (3.3)	-1.4	-2.7
उसमें से:						
बाजार उधार	1,06,241 (3.0)	1,13,778 (2.9)	1,10,500 (2.7)	1,10,827 (2.4)	-2.9	0.3
ऋणों की वसूली	10,645 (0.3)	8,000 (0.2)	5,450 (0.1)	1,500 (0.0)	-31.9	-72.5
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की ईक्विटी का विनिवेश	1,581 (0.0)	3,840 (0.1)	528 (0.0)	1,651 * (0.0)	-86.3	212.7
ज्ञापन मदें:						
सकल कर राजस्व	3,66,152 (10.3)	4,42,153 (11.2)	4,67,848 (11.4)	5,48,122 (11.8)	5.8	17.2
उसमें से:						
i) निगम कर	1,01,277 (2.8)	1,33,010 (3.4)	1,46,497 (3.6)	1,68,401 (3.6)	10.1	15.0
ii) आय पर कर, निगम कर के आलावा #	60,749 (1.7)	73,409 (1.9)	78,210 (1.9)	93,629 (2.0)	6.5	19.7
iii) सीमा शुल्क	65,067 (1.8)	77,066 (1.9)	81,800 (2.0)	98,770 (2.1)	6.1	20.7
iv) केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,11,226 (3.1)	1,19,000 (3.0)	1,17,266 (2.9)	1,30,220 (2.8)	-1.5	11.0
v) सेवा कर	23,055 (0.6)	34,500 (0.9)	38,169 (0.9)	50,200 (1.1)	10.6	31.5
vi) प्रतिभूति लेनदेन कर	2,559 (0.1)	3,500 (0.1)	3,750 (0.1)	4,500 (0.1)	7.1	20.0
vii) बैंकिंग नकदी लेनदेन कर	321 (0.0)	500 (0.0)	550 (0.0)	645 (0.0)	10.0	17.3
viii) संघ शासित क्षेत्रों का कर (स्थानीय निकाय को समनुदेशन के बाद निवल)	1,125 (0.0)	903 (0.0)	1,341 (0.0)	1,442 (0.0)	48.5	7.5
ix) अन्य कर	773 (0.0)	265 (0.0)	265 (0.0)	315 (0.0)	0.0	18.9

बअ : बजट अनुमान. संअ : संशोधित अनुमान.

* : भा. स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की धारिता के सरकार को अंतरण संबंधी 40,000 करोड़ रुपए समायोजित।

: अनुषंगी लाभ कर सहित

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के प्रतिशत हैं।

की वृद्धि का बजट अनुमान है। तथापि, उत्पाद शुल्क की वसूली में 5.4 प्रतिशत की तुलना में 11.0 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि होने का बजट अनुमान है। करेतर राजस्व 2006-07 के 77,360 करोड़ रुपए की

तुलना में 2007-08 में बढ़कर 82,550 करोड़ रुपए होने का बजट अनुमान है, जो लाभांश और लाभों से मिलनेवाले अधिक राजस्व को दर्शाता है (सारणी 2.17)। दूसरी ओर, प्राथमिक तौर पर बारहवें वित्त

सारणी 2.18 : केंद्र के व्यय का पैटर्न

(करोड़ रुपए)

मद	2005-06 (खाता)	2006-07 (बअ)	2006-07 (संअ)	2007-08 (बअ)	घट-बढ़ (प्रतिशत)	
					स्तंभ 3 की तुलना में 4	स्तंभ 4 की तुलना में 5
1	2	3	4	5	6	7
कुल व्यय (1+2)	5,06,123 (14.2)	5,63,991 (14.3)	5,81,637 (14.2)	6,40,521 * (13.8)	3.1	10.1
1. राजस्व व्यय	4,39,761 (12.3)	4,88,192 (12.4)	5,06,767 (12.4)	5,57,900 (12.0)	3.8	10.1
ब्याज भुगतान	1,32,630 (3.7)	1,39,823 (3.5)	1,46,192 (3.6)	1,58,995 (3.4)	4.6	8.8
उपदान	47,520 (1.3)	46,213 (1.2)	53,463 (1.3)	54,330 (1.2)	15.7	1.6
राज्यों को अनुदान	30,475 (0.9)	35,361 (0.9)	36,152 (0.9)	38,403 (0.8)	2.2	6.2
रक्षा राजस्व	48,211 (1.4)	51,542 (1.3)	51,542 (1.3)	54,078 (1.2)	0.0	4.9
2. पूंजीगत व्यय	66,362 (1.9)	75,799 (1.9)	74,870 (1.8)	82,621 * (1.8)	-1.2	10.4
ऋण और अग्रिम	11,337 (0.3)	8,861 (0.2)	9,706 (0.2)	7,498 (0.2)	9.5	-22.7
रक्षा पूंजी	32,338 (0.9)	37,458 (0.9)	34,458 (0.8)	41,922 (0.9)	-8.0	21.7
गैर रक्षा पूंजी परिव्यय	22,687 (0.6)	29,480 (0.7)	30,706 (0.7)	33,201 * (0.7)	4.2	8.1

बअ : बजट अनुमान. संअ : संशोधित अनुमान.

* : भा. स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की धारिता के सरकार को अंतरण संबंधी 40,000 करोड़ रुपए समायोजित।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) के प्रतिशत हैं।

आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत दिए जानेवाले ऋणों को छोड़कर राज्यों को अन्य कोई ऋण देने से केंद्र की मुक्ति के कारण ब्याज प्राप्तियों में गिरावट आई। कम ब्याज प्राप्तियों के अन्य कारकों में राज्यों को दिए जानेवाले ऋणों को कम ब्याज दर, राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी कानून बनाने वाले राज्यों में प्रोत्साहन से संबद्ध ऋण पुनर्विन्यास का परिचालन, 2002-03 से 2004-05 तक परिचालित ऋण स्वैप योजना जिसमें राज्यों को कुछ लागत वाले ऋण की पूर्व-चुकोती की अनुमति तथा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ऋणों की पूर्व अदायगी शामिल हैं।

2.46 हाल के वर्षों में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार का सतत प्रयास है। 2007-08 में राजस्व व्यय में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि का बजट अनुमान है, जो 2006-07 के 15.2 प्रतिशत से कम है। कुल सब्सिडी में 2006-07 के 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि का बजट अनुमान है। भारतीय स्टेट बैंक में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी को सरकार को अंतरित करने संबंधी लेनदेनों के कारण खर्च होने के लिए प्रस्तावित 40,000 करोड़ रुपए का समायोजन करने पर पूंजीगत व्यय में 2006-07 के 12.8 प्रतिशत की वृद्धि की

तुलना में 2007-08 में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि का बजट अनुमान है। भारतीय स्टेट बैंक में हिस्सेदारी खरीदने संबंधी लेनदेनों को समायोजित करने पर, पूंजीगत परिव्यय में 2006-07 की 10,139 करोड़ रुपए (18.4 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 9,959 करोड़ रुपए (15.3 प्रतिशत) की वृद्धि होने का बजट अनुमान है। रक्षा पूंजी परिव्यय में 7,464 करोड़ रुपए तथा रक्षेत्र पूंजी परिव्यय में 2,495 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है (सारणी 2.18)।

2.47 निवल बाजार उधार (एमएसएस के तहत बजटित समर्थक आबंटनों को छोड़कर) से पिछले वर्ष के 72.5 प्रतिशत की तुलना में 2007-08 में जीएफडी के 73.4 प्रतिशत का वित्तपोषण किया जाएगा। बजट अनुमानों में नकद शेष की गिरावट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लघु बचतों के प्रति प्रतिभूतियों द्वारा 2006-07 में जीएफडी के केवल 2.0 प्रतिशत का वित्तपोषण किया गया था, जबकि 2007-08 में इसके द्वारा 7.0 प्रतिशत के वित्तपोषण की आशा है (सारणी 2.19)। यह वृद्धि एमएसएस से उधार लेने संबंधी राज्यों के न्यूनतम दायित्व को कम करके निवल वसूलियों का 80 प्रतिशत करने के निर्णय के बाद मोचन आगमों के पुनर्निवेश तथा लघु बचत वसूलियों से निवेश को दर्शाती है। बाह्य सहायता से पिछले वर्ष के 5.2 प्रतिशत

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.19: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का पैटर्न

(राशि करोड़ रूप में)

मद	2006-07(संअ)	2007-08 (बअ)
1	2	3
सकल राजकोषीय घाटा	1,52,328	1,50,948
<i>निम्नलिखित द्वारा वित्तपोषित :</i>		
बाजार से उधार	1,10,500 (72.5)	1,10,827 (73.4)
लघु बचतों के बदले प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश	3,010 (2.0)	10,510 (7.0)
बाह्य सहायता	7,892 (5.2)	9,111 (6.0)
राज्य भविष्य निधि कोष	5,000 (3.3)	5,000 (3.3)
राष्ट्रीय लघु बचत निधि	-3,128 (-2.1)	17,850 (11.8)
आरक्षित निधियाँ	4,265 (2.8)	738 (0.5)
जमाराशि और अग्रिम	11,647 (7.6)	-2,411 (-1.6)
डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधियाँ	1,237 (0.8)	1,261 (0.8)
नकदी शेष का आहरण	10,926 (7.2)	0 (0.0)
अन्य #	979 (0.6)	-1,938 (-1.3)

संअ : संशोधित अनुमान। बअ : बजट अनुमान।

: बचत (कर युक्त) बंधपत्र 2003 और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जमाराशि की योजना शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के प्रतिशत हैं।

की तुलना में जीएफडी के 6.0 प्रतिशत के वित्तपोषण का बजट अनुमान लगाया गया है।

राज्य वित्त

2.48 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों ने राजकोषीय सुधार तथा समेकन कार्यक्रमों का अनुसरण जारी रखा। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 25 राज्य सरकारों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी कानून बनाए हैं। 5 अप्रैल 2007 तक उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने बिक्री कर के स्थान पर मूल्य योजित कर (वीएटी) लागू कर दिया।

2.49 अपने 2006-07 के बजटों में राज्य सरकारों ने राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों का प्रस्ताव किया। राज्यों ने कर प्रणाली को व्यापक और युक्तियुक्त बनाकर राजकोषीय सशक्तीकरण पर बल दिया है। साथ ही, उन्होंने कर प्रशासन में सुधार, मौजूदा कर तथा करेतर वसूलियों को कारगर और सुदृढ़ बनाने, राजस्व के रिसाव और रस्त्र को बंद करने तथा प्रभावी व्यय प्रबंधन पर बल दिया है।

बजट अनुमान -2006-07⁴

2.50 समेकित स्थिति यह संकेत देती है कि राज्यों में हुए कुछ घटबढ़ के बावजूद, राज्य सरकारों ने 2006-07 के दौरान राजस्व संतुलन के पास तक जाने का बजट अनुमान लगाया है। राजस्व घाटे में बजटित कटौती से जीएफडी-जीडीपी अनुपात 2005-06 के 3.2 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) से 0.5 प्रतिशत अंक गिरकर 2006-07 में 2.7 प्रतिशत पर आना संभव होगा। प्राथमिक घाटा भी पिछले वर्ष के 0.7 प्रतिशत से तेजी से गिरकर 2006-07 में जीडीपी का 0.2 प्रतिशत होने का बजट अनुमान है (सारणी 2.20)। 2006-07 में

सारणी 2.20: राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(राशि करोड़ रूप में)

मद	1990-95 (औ)	1995-00 (औ)	2000-04 (औ)	2004-05	2005-06 (बअ)	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)	घट-बढ़ प्रतिशत में		
								स्तंभ 7/5	स्तंभ 7/6	स्तंभ 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सकल राजकोषीय घाटा	(2.8)	(3.4)	(4.3)	1,09,257 (3.5)	1,10,050 (3.1)	1,13,888 (3.2)	1,09,610 (2.7)	4.2	3.0	-3.8
राजस्व घाटा	(0.7)	(1.6)	(2.4)	36,423 (1.2)	24,913 (0.7)	17,178 (0.5)	4,511 (0.1)	-52.8	-31.0	-73.7
प्राथमिक घाटा	(1.1)	(1.4)	(1.5)	21,268 (0.7)	17,252 (0.5)	24,894 (0.7)	10,185 (0.2)	17.0	44.3	-59.1

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान औ. : औसत

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आँकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।

2. 1990-91 से 1998-99 तक जीडीपी पुराने आधार (1993-94) पर है जबकि 1999-2000 से नए आधार (1999-2000) पर है।

3. वर्ष 2006-07 के जीडीपी के आँकड़े के. सां. संगठन के अग्रिम अनुमानों के अनुसार हैं जबकि 2005-06 के आँकड़े त्वरित अनुमानों पर आधारित हैं।

स्रोत : 1. राजकोषीय परिवर्तन के आँकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित किए गए हैं।

2. जीडीपी के आँकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) की वेबसाइट से लिए गए हैं।

⁴ 2006-07 (बजट अनुमान) के राज्य वित्त का विश्लेषण 29 राज्य सरकारों (एनसीटी दिल्ली सहित) के बजटों पर आधारित है।

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.21 : राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	1990-95 (औ)	1995-00 (औ)	2000-04 (औ)	2004-05	2005-06 (बअ)	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)	प्रतिशत घट-बढ़		
								स्तंभ 7 / 5	स्तंभ 7 / 6	स्तंभ 8 / 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल प्राप्तियाँ (1+2)	(16.1)	(15.1)	(17.4)	5,76,762 (18.4)	5,80,092 (16.3)	6,13,379 (17.2)	6,72,116 (16.4)	6.3	5.7	9.6
1. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख)	(12.1)	(10.9)	(11.3)	3,72,075 (11.9)	4,30,679 (12.1)	4,54,243 (12.7)	5,20,148 (12.7)	22.1	5.5	14.5
(क) राज्यों का अपना राजस्व	(7.3)	(6.9)	(7.1)	2,36,668 (7.6)	2,61,796 (7.3)	2,71,518 (7.6)	3,10,540 (7.6)	14.7	3.7	14.4
राज्यों का अपना कर	(5.4)	(5.3)	(5.7)	1,89,133 (6.0)	2,15,246 (6.0)	2,24,817 (6.3)	2,57,203 (6.3)	18.9	4.4	14.4
राज्यों की कर से इतर प्राप्तियाँ	(1.8)	(1.6)	(1.4)	47,535 (1.5)	46,550 (1.3)	46,702 (1.3)	53,337 (1.3)	-1.8	0.3	14.2
(ख) केंद्रीय अंतरण	(4.9)	(4.0)	(4.2)	1,35,406 (4.3)	1,68,883 (4.7)	1,82,725 (5.1)	2,09,608 (5.1)	34.9	8.2	14.7
हिस्सेदारी योग्य कर	(2.6)	(2.4)	(2.4)	78,550 (2.5)	90,002 (2.5)	92,723 (2.6)	1,09,419 (2.7)	18.0	3.0	18.0
केंद्रीय अनुदान	(2.3)	(1.6)	(1.9)	56,857 (1.8)	78,882 (2.2)	90,002 (2.5)	1,00,188 (2.4)	58.3	14.1	11.3
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ (क+ख)	(4.0)	(4.2)	(6.0)	2,04,687 (6.5)	1,49,413 (4.2)	1,59,136 (4.5)	1,51,969 (3.7)	-22.3	6.5	-4.5
(क) केंद्र से ऋण @	(1.2)	(1.0)	(1.0)	26,157 (0.8)	31,216 (0.9)	10,911 (0.3)	13,525 (0.3)	-58.3	-65.0	24.0
(ख) अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	(2.9)	(3.2)	(5.0)	1,78,529 (5.7)	1,18,197 (3.3)	1,48,224 (4.2)	1,38,443 (3.4)	-17.0	25.4	-6.6

बअ : बजट अनुमान

संअ : संशोधित अनुमान

औ : औसत

@ : लेखा प्रणाली में 1999-2000 से बदलाव के कारण, राज्यों का लघु बचतों में हिस्सा, जो पहले केंद्र से ऋण के अंतर्गत शामिल था, आंतरिक ऋणों में शामिल किया गया है और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, 1999-2000 से पहले के वर्षों के आंकड़ों में, जैसा कि इस सारणी में बताया गया है, तुलना के लिए, लघु बचतों की जमानत पर लिए गए ऋण को शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जी डी पी के प्रतिशत हैं।

2. 1990-91 से 1998-99 तक जीडीपी पुराने आधार (1993-94) पर है जबकि 1999-2000 से आगे वह नए आधार (1999-2000) पर है।

3. वर्ष 2006-07 के आंकड़े केंद्रीय सां. सं. के अग्रिम अनुमानों के अनुसार है जबकि 2005-06 के आंकड़े शीघ्र अनुमानों पर आधारित है।

4. पूंजीगत प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल है।

5. राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्तावित उपायों के संदर्भ में राजस्व प्राप्त संबंधी 2005-06 (ब.अ.) तथा 2006-07 (ब.अ.) की क्रमशः 742 करोड़ रुपए तथा 273 करोड़ रुपए की राशि समायोजित की गई है।

स्रोत : 1. राजकोषीय परिवर्तियों के आंकड़ें राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित किए गए हैं।

2. जीडीपी के लिए आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं।

राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार बारहवें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार अधिक अनुदान एवं विभाजनीय केंद्रीय करों में वृद्धि द्वारा संभव हुआ। 2006-07 के दौरान राजस्व घाटे में तीव्र सुधार मुख्यतः केंद्र से उच्चतर अंतरणों, विशेषकर विभाजनीय केंद्रीय करों से प्रकट होगा⁵

(सारणी 2.21)। अंशतः प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर होनेवाले व्यय में कमी के कारण राजस्व व्यय में कमी के द्वारा भी 2006-07 में राजस्व घाटे में सुधार होगा। 2006-07 के दौरान पूंजीगत परिव्यय कम होने का बजट अनुमान है, हालांकि जीडीपी के अनुपात के रूप में

⁵ 2007-08 का केंद्रीय बजट यह सूचित करता है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को अंतरणों में 2006-07 (बजट अनुमान) की तुलना में 2006-07 (संशोधित अनुमान) में 10,391 करोड़ रुपए (जीडीपी के 0.3 प्रतिशत) की वृद्धि होगी।

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.22 : राज्य सरकारों के व्यय का पैटर्न

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	1990-95 (औ)	1995-00 (औ)	2000-04 (औ)	2004-05	2005-06 बअ	2005-06 संअ	2006-07 बअ	प्रतिशत घट-बढ़		
								स्तंभ 7/5	स्तंभ 7/6	स्तंभ 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल व्यय (1+2+3+4+5)	(16.0)	(15.2)	(17.3)	5,66,303 (18.1)	5,78,891 (16.2)	6,07,753 (17.0)	6,68,129 (16.3)	7.3	5.0	9.9
1. राजस्व व्यय				4,08,497	4,55,593	4,71,421	5,24,658	15.4	3.5	11.3
उसमें से :	(12.8)	(12.6)	(13.7)	(13.1)	(12.8)	(13.2)	(12.8)			
ब्याज भुगतान				87,989	93,298	88,994	99,425	1.1	-4.6	11.7
	(1.7)	(2.0)	(2.8)	(2.8)	(2.6)	(2.5)	(2.4)			
2. पूंजीगत व्यय				1,57,805	1,23,299	1,36,332	1,43,471	-13.6	10.6	5.2
उसमें से :	(3.2)	(2.7)	(3.6)	(5.0)	(3.5)	(3.8)	(3.5)			
पूंजी परिव्यय				61,559	77,048	85,350	96,506	38.6	10.8	13.1
	(1.6)	(1.4)	(1.6)	(2.0)	(2.2)	(2.4)	(2.4)			
3. विकासात्मक व्यय				2,93,538	3,26,482	3,62,300	3,92,926	23.4	11.0	8.5
	(10.8)	(9.6)	(9.7)	(9.4)	(9.2)	(10.2)	(9.6)			
4. गैर विकासात्मक व्यय				1,88,298	2,11,447	2,03,189	2,30,225	7.9	-3.9	13.3
	(4.3)	(4.9)	(6.0)	(6.0)	(5.9)	(5.7)	(5.6)			
5. अन्य*				84,467	40,962	42,265	44,978	-50.0	3.2	6.4
	(0.9)	(0.8)	(1.6)	(2.7)	(1.1)	(1.2)	(1.1)			
बअ : बजट अनुमान	संअ : संशोधित अनुमान	औ : औसत								
* : 2002-03 तक स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और आबंटन, सहायक अनुदान और योगदान, वित्त विभाग के पास रिजर्व, आंतरिक ऋण की अदायगी, केंद्र को ऋणों की चुकौती शामिल हैं। 2003-04 से, अंतर-राज्यीय निपटान, आकस्मिकता कोष, लघु बचतें, भविष्य निधि कोष इत्यादि आरक्षित निधियाँ, जमाराशि और अग्रिम, उंचत और फुटकर, आकस्मिकता कोष से विनियोजन और प्रेषण भी शामिल हैं।										
टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।										
2. 1990-91 से 1998-99 तक जीडीपी पुराने आधार (1993-94) पर है जबकि 1999-2000 से आगे वह नए आधार (1999-2000) पर है।										
3. वर्ष 2006-07 के आंकड़े केंद्रीय सां. सं. के अग्रिम अनुमानों के अनुसार है जबकि 2005-06 के आंकड़े त्वरित अनुमानों पर आधारित हैं।										
4. पूंजीगत व्यय में लोक लेखा शामिल नहीं है।										
स्रोत : 1. राजकोषीय परिवर्तियों के आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से संकलित किए गए हैं।										
2. जीडीपी के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) की वेबसाइट से प्राप्त किए गए हैं।										

इसे 2.4 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा। विकासात्मक व्यय पिछले साल की तेज वृद्धि की तुलना में 2006-07 के दौरान कम होगा (सारणी 2.22)।

2.51 जीएफसी का अपघटन यह सूचित करता है कि 2006-07 के दौरान राजकोषीय घाटा मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय के कारण हुआ क्योंकि राजस्व घाटे में तेज गिरावट आई थी। लघु बचत जीएफडी के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत बना रहा तथा उसके बाद बाजार उधार राशियों का स्थान था (सारणी 2.23)।

2.52 2006-07 के दौरान सभी राज्यों के लिए बाजार उधार राशियों का निवल आबंटन 17,242 करोड़ रुपए था। बाजार उधार का सकल आबंटन 26,597 करोड़ रुपए था जिसमें 2,803 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन

शामिल है। 2006-07 के दौरान, सभी राज्यों द्वारा जुटाया गया कुल बाजार उधार 20,825 करोड़ रुपए था। 2006-07 के दौरान बाजार ऋण जुटाने के लिए सभी राज्य सरकारों ने नीलामी का मार्ग अपनाया (सारणी 2.24)।

2.53 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार ऋणों की भारांकित औसत ब्याज दर पिछले साल के 7.63 प्रतिशत की तुलना में 8.10 प्रतिशत थी (चार्ट II.4)।

2.54 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों का साप्ताहिक औसत उपयोग पिछले वर्ष के 482 करोड़ रुपए के औसत उपयोग की तुलना में 234 करोड़ रुपए था, जो राज्यों में चलनिधि की सुखद स्थिति को दर्शाता है। 2006-07 के दौरान, सिर्फ 8 राज्यों ने सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों का तथा 2 राज्यों ने ओवरड्राफ्टों का आश्रय लिया (चार्ट II.5)।

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.23 : राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के वियोजन और वित्तपोषण का पैटर्न

(प्रतिशत)

मद	1990-95 (औ)	1995-00 (औ)	2000-04 (औ)	2004-05	2005-06 बअ	2005-06 संअ	2006-07 बअ
1	2	3	4	5	6	7	8
वियोजन (1 से 4 तक)	100	100	100	100	100	100	100
1. राजस्व घाटा	24.7	44.8	56.3	33.3	22.5	15.1	4.1
2. पूंजीगत परिव्यय	55.3	43.3	36.7	56.3	69.7	74.9	88.0
3. निवल प्रदत्त ऋण	20.0	12.2	7.0	10.3	7.8	10.0	8.8
4. विनिवेश	..	-0.2	-0.9
वित्तपोषण (1 से 11 तक)	100	100	100	100	100	100	100
1. बाजार उधार राशियाँ	16.0	16.1	24.6	31.6	16.2	16.4	20.8
2. केंद्र से ऋण	49.0	40.6	7.8	-10.8	15.7	1.9	4.4
3. एनएसएसएफ को जारी की गई प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण	-	28.9*	35.4	62.2	50.0	65.4	53.1
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से लिए गए ऋण	1.8	2.8	4.9	-**	7.7	4.9	6.9
5. राज्य भविष्य निधि	14.3	13.4	8.3	7.2	7.2	7.9	8.0
6. आरक्षित निधियाँ	6.8	5.5	4.5	6.5	3.8	2.9	4.0
7. जमाराशियाँ और अग्रिम	9.8	9.8	3.4	7.4	-2.5	-0.6	-1.1
8. उचंत और फुटकर	4.3	2.7	-0.4	-2.4	-1.4	3.3	3.3
9. प्रेषण	-1.4	-3.6	0.6	1.1	1.5	0.8	1.8
10. कुल अधिशेष (+) / घाटा (-)	4.4	-2.6	1.1	9.6	0.4	4.9	3.6
11. अन्य	-5.0	9.5	9.8	-12.4 \$	1.2	-7.9	-4.7

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान औ : औसत .. : कुछ नहीं - : नहीं लागू

* : 1999-2000 से संबंधित है क्योंकि उसे केवल उस वर्ष से ही लागू किया गया था। 1995-2000 (औ) के लिए मदों का जोड़ 100 नहीं होगा।

** : तमिलनाडु ने अपने बजट में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जारी बांडों और तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पावर बांडों को एनसीडीसी तथा अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋणों को ऋणात्मक आंकड़ों के रूप में दिखाते हुए, अपने बजट में हिसाब में लिया है। अतः समेकित स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है।

\$: तमिलनाडु सरकार द्वारा 2004-05 के दौरान जारी भूमि क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांडों (1,962 करोड़ रुपए) के कारण।

टिप्पणी : 1. वर्ष 1999-2000 से लेखाविधि में परिवर्तन के कारण केंद्र से लिए गए ऋणों में लघु बचत संग्रहणों में राज्यों के हिस्से को, जिसे आंतरिक ऋण के अंतर्गत एनएसएसएफ के अधीन जारी प्रतिभूतियों के रूप में दिखाया जाता है, शामिल नहीं किया गया है। तदनुसार प्राप्ति तथा व्यय की एक समान लेखाविधि प्रक्रिया अपनाई जाने के उद्देश्य से केंद्र से लिए गए ऋणों की चुकौती के अंतर्गत शामिल अल्प बचतों के भुगतान को इस समय आंतरिक ऋण की चुकौती के अंतर्गत दिखाया जा रहा है।

2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

3. वित्तपोषण की मदें निवल आधार पर हैं।

4. 'अन्य' मद की राशि अवशिष्ट राशि है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि में विनियोजन, विविध पूंजीगत प्राप्ति, आंतर-राज्य निपटान, भूमि क्षतिपूर्ति एवं अन्य बांड तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण, सारणी में उल्लिखित संस्थाओं को छोड़कर, शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2.55 2006-07 के दौरान 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में राज्यों का साप्ताहिक औसत निवेश पिछले साल की तदनुसूचित अवधि के 35,278 करोड़ रुपए के साप्ताहिक औसत निवेश की तुलना में 43,075 करोड़ रुपए था (चार्ट II.6)। अधिशेष नकदी शेष का बढ़ना राज्य सरकारों द्वारा नकदी एवं वित्तीय प्रबंधन के समक्ष चुनौती खड़ा कर सकता है।

संभावना

2.56 सरकार के लेनदेनों में पारदर्शिता एवं दक्षता में सुधार लाने के लिए, कई राज्यों ने अपने राजकोषों का कम्प्यूटरीकरण तथा लेनदेनों के लिए ई-अंतरण शुरू करने का प्रस्ताव किया है। बजट प्रस्तावों की

जवाबदेही में सुधार लाने के लिए, कुछ राज्यों ने 'परिणाम बजट' शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, कई राज्य सरकारों ने 'लिंग बजटिंग' शुरू करने का प्रस्ताव किया है। कुछ राज्यों ने राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के व्यापक पुनर्विन्यास, उन्हें बजट समर्थन कम करने के लिए चिरकाल से हानि उठाने वाली इकाइयों को बंद करने सहित, का प्रस्ताव किया है। कुछ राज्यों ने बढ़ रहे पेंशन संबंधी दायित्वों को नियंत्रित करने के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर नई पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। कुछ राज्यों ने रिक्त पदों को समाप्त करके, मितव्ययिता उपायों को अपनाकर तथा योजनेतर व्यय में कटौती कर गैर-विकासात्मक व्यय कम करने का भी प्रस्ताव किया है।

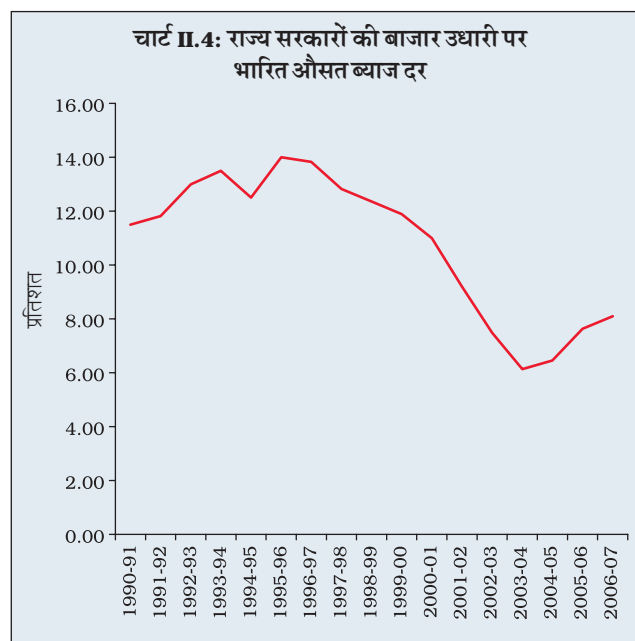
हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.24 : 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों की बाजार उधारियां

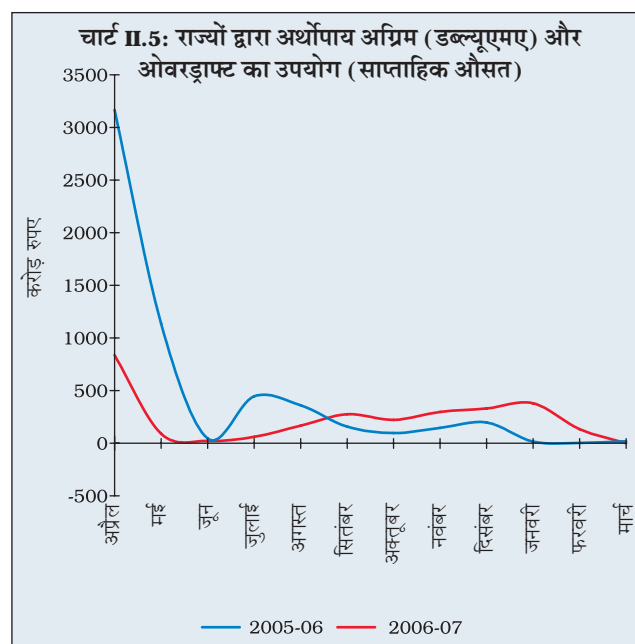
(राशि करोड़ रुपए में)

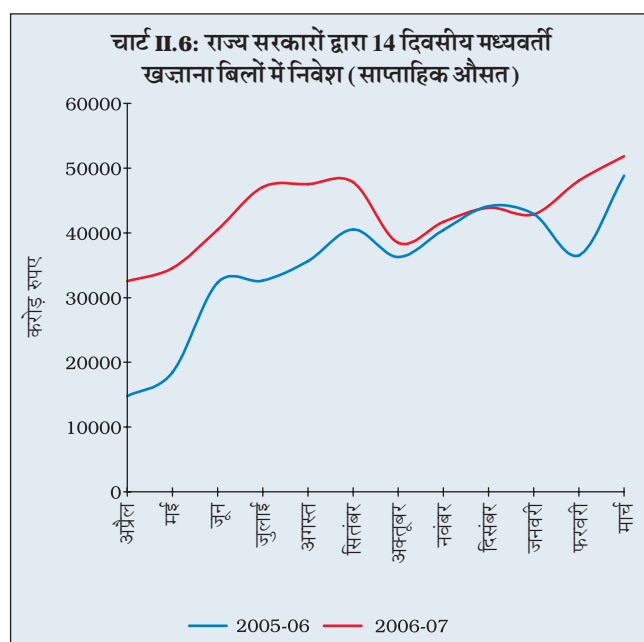
मद	तारीख	अधिकतम दर (%)	अवधि (वर्ष)	उगाही गई राशि
1	2	3	4	5
(क) तैयार निर्गम	-	-	-	-
(ख) नीलामियां				
i. पहली	27 अप्रैल 2006	7.65	10	300
ii. दूसरी	11 मई 2006	7.87	10	400
iii. दूसरी	11 मई 2006	7.89	10	500
iv. दूसरी	11 मई 2006	7.91	10	500
v. दूसरी	11 मई 2006	7.93	10	1,307
vi. दूसरी	11 मई 2006	7.95	10	881
vii. दूसरी	11 मई 2006	7.96	10	130
viii. दूसरी	11 मई 2006	7.98	10	57
ix. दूसरी	11 मई 2006	8.00	10	1,646
x. दूसरी	11 मई 2006	8.04	10	150
xi. दूसरी	11 मई 2006	8.05	10	15
xii. तीसरी	13 जुलाई 2006	8.62	10	225
xiii. तीसरी	13 जुलाई 2006	8.65	10	933
xiv. तीसरी	13 जुलाई 2006	8.66	10	300
xv. चौथी	25 अगस्त 2006	8.11	10	1,050
xvi. पांचवीं	17 अक्टूबर 2006	7.99	10	153
xvii. पांचवीं	17 अक्टूबर 2006	8.04	10	48
xviii. छठी	16 नवंबर 2006	7.74	10	2,184
xix. छठी	16 नवंबर 2006	7.80	10	91
xx. छठी	16 नवंबर 2006	7.82	10	156
xxi. सातवीं	14 दिसंबर 2006	7.81	10	340
xxii. सातवीं	14 दिसंबर 2006	7.89	10	166
xxiii. सातवीं	14 दिसंबर 2006	7.93	10	809
xxiv. सातवीं	14 दिसंबर 2006	7.94	10	455
xxv. सातवीं	14 दिसंबर 2006	7.99	10	193
xxvi. आठवीं	18 जनवरी 2007	7.96	10	500
xxvii. आठवीं	18 जनवरी 2007	7.99	10	715
xxviii. नौवीं	2 फरवरी 2007	7.95	10	200
xxix. दसवीं	22 फरवरी 2007	8.10	10	47
xxx. दसवीं	22 फरवरी 2007	8.17	10	375
xxxi. दसवीं	22 फरवरी 2007	8.19	10	800
xxxii. दसवीं	22 फरवरी 2007	8.20	10	563
xxxiii. दसवीं	22 फरवरी 2007	8.45	10	1,615
xxxiv. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.38	10	212
xxxv. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.45	10	250
xxxvi. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.40	10	470
xxxvii. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.39	10	67
xxxviii. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.39	10	70
xxxix. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.39	10	90
xxxx. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.32	10	300
xxxxi. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.25	10	200
xxxixii. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.32	10	414
xxxixiii. ग्यारहवीं	13 मार्च 2007	8.38	10	211
xxxixiv. बारहवीं	23 मार्च 2007	8.35	10	738
कुल - ख (I से xxxiv तक)				20,825
कुल योग (क+ख)				20,825

2.57 2004-05 से राजकोषीय समेकन में प्रगति के बावजूद, संरचनागत कठोरता बनी हुई है जो करेतर राजस्व में मंदी, नीचे की ओर अनम्य गैर-विकासात्मक व्यय तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में कम आबंटन में दिखाई देता है। शिक्षा और स्वास्थ्य



जैसी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तथा सड़क, जलकार्य और बिजली जैसी आर्थिक मूलभूत संरचना प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकारों को प्रमुख उत्तरदायित्व निभाना है। राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को टिकाऊ और धारणीय बनाने के लिए आर्थिक मूलभूत संरचना में पर्याप्त निवेश तथा सामाजिक सेवाओं पर व्यय की आवश्यकता होगी। इस पृष्ठभूमि में, राजकोषीय सशक्तीकरण के माध्यम से, अर्थात् राजकोषीय दुर्बलता के बजाय राजस्व प्रवाहों की गुंजाइश और उनके आकार को बढ़ाकर, राजकोषीय सुधार का वांछित मार्ग उपलब्ध होगा। उपयुक्त





उपयोगकर्ता प्रभारों के जरिए संसाधन जुटाने में वृद्धि तथा राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्विन्यास का अत्यधिक महत्व बना हुआ है।

लोक ऋण

2.58 जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त बकाया देयताएं मार्च 2006 के अंत के 78.5 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत तक 75.7 प्रतिशत रह जाने का बजट अनुमान लगाया गया है। केंद्र तथा राज्यों में चल रही राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया तथा सुदृढ़ समष्टि आर्थिक निष्पादन ने संयुक्त सरकारी देयताओं में गिरावट का बजट अनुमान लगाने में योगदान दिया है (सारणी 2.25)।

III. मौद्रिक और ऋणस्थिति

मौद्रिक स्थितियां

2.59 इस खंड में 2006-07 के दौरान मौद्रिक नीति के संचालन का आकलन किया गया है तथा इसमें मौद्रिक और ऋण स्थिति संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी गई है तथा उसके बाद रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों पर चर्चा की गई है। अप्रैल 2006 में घोषित रिजर्व बैंक के वार्षिक वक्तव्य के अनुरूप, वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा (जुलाई 2006), मध्यावधि समीक्षा (अक्टूबर 2006) तथा तीसरी तिमाही की समीक्षा (जनवरी 2007) में यह दर्शाया गया कि प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त चलनिधि बनाए रखना सुनिश्चित किया जाता रहेगा ताकि ऋण संबंधी सभी उचित आवश्यकताओं, विशेषकर उत्पादक प्रयोजनों की अपेक्षा को पूरा किया जा सके जोकि मूल्य एवं वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस लक्ष्य के प्रति यह सूचित किया गया कि यह एमएसएस, एलएएफ तथा सीआरआर सहित खुले बाजार परिचालनों के माध्यम से चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंधन की नीति जारी रखेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने पास उपलब्ध सभी नीतिगत लिखतों का लचीलेपन से उपयोग करेगा।

2.60 रिजर्व बैंक के 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा (31 अक्टूबर 2006) में यह नोट किया गया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी तरह की प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधियां पैदा होने को छोड़कर तथा मुद्रास्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के आकलन को ध्यान में रखते हुए, मौद्रिक नीति का समग्र रुख यह होगा कि ऐसा मौद्रिक एवं ब्याज दर माहौल सुनिश्चित किया जाए जो अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश मांग का समर्थन करे ताकि वृद्धि की गति बनी रहे तथा विकासमान वैश्विक एवं देशी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सभी संभव उपायों पर त्वरित गति से विचार करते हुए समष्टि आर्थिक और

सारणी 2.25 : संयुक्त देयताएं और ऋण-जीडीपी अनुपात

वर्ष (मार्च-अंत)	बकाया देयताएं (करोड़ रुपए)			ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत)		
	केंद्र	राज्य	संयुक्त	केंद्र	राज्य	संयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	3,14,558	1,28,155	3,68,824	55.3	22.5	64.9
1995-96	6,06,232	2,50,889	7,28,208	51.0	21.1	61.3
2002-03	15,59,201	7,98,921	19,83,298	63.4	32.5	80.7
2003-04	17,36,678	9,23,500	22,52,074	62.8	33.4	81.4
2004-05	19,94,422	10,42,305	25,75,146	63.8	33.3	82.4
2005-06 संअ	21,95,387	11,52,652	28,01,050	61.5	32.3	78.5
2006-07 बअ	24,73,562	12,58,672	31,04,262	60.3	30.7	75.7

संअ: संशोधित अनुमान बअ: बजट अनुमान

टिप्पणी : वर्ष 2002-03 से जीडीपी के अनुपात राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला पर आधारित हैं जिसका आधार वर्ष 1999-2000 है। वर्ष 2006-07 बअ का ऋण-जीडीपी अनुपात के.सां.संगठन के अग्रिम अनुमानों पर आधारित है।

स्रोत : केंद्र सरकार का बजट दस्तावेज और “राज्य वित्त-2006-07 के राज्य बजटों का अध्ययन”, भारतीय रिजर्व बैंक, दिसंबर 2006।

विशेष रूप से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर बल देते हुए मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से मूल्य की स्थिरता पर बल दिया जाए।

2.61 वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा में इस बात पर भी बल दिया गया कि नीति पर निगरानी रखने तथा कार्रवाई के रूप में मुद्रास्फीति की संभावना महत्वपूर्ण है और तदनुसार साल के शेष भाग में चलनिधि के प्रबंधन को नीति संबंधी अनुक्रम में प्राथमिकता प्राप्त होगी। इसके अलावा, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को भारांकों का न्यायपूर्ण संतुलन दिया गया है ताकि धारणीय आधार पर वृद्धि का समर्थन करने के लिए स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए और यह प्रदर्शित किया जाए कि एक सीमा के बाहर मुद्रास्फीति को बर्दाश्त करना रिजर्व बैंक को स्वीकार्य नहीं है तथा यह मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने का संकल्प हमेशा समय पर और उपयुक्त नीति संबंधी प्रतिसादों द्वारा समर्थित हो।

2.62 जनवरी 2007 में वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही की समीक्षा में यह सूचित किया गया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधि के उदय को छोड़कर तथा मुद्रास्फीति के बारे में संभावना सहित अर्थव्यवस्था के उस समय के आकलन को ध्यान में रखते हुए, आगे आनेवाली अवधि में मौद्रिक नीति का समग्र रुख निम्नानुसार होगा :

- अर्थव्यवस्था में निर्यात एवं निवेश संबंधी मांग को समर्थन देने वाला मौद्रिक और ब्याज दर संबंधी माहौल सुनिश्चित करते हुए कीमत में स्थिरता एवं सुनियंत्रित मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर बल दिया जाए ताकि वृद्धि की गति बनाई रखी जा सके।
- समष्टि आर्थिक तथा विशेष रूप से, वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए ऋण की गुणवत्ता एवं वित्तीय बाजारों में व्यवस्थित स्थितियों पर बल दिया जाए तथा साथ ही ऋण के अधिक विस्तार और वित्तीय समावेशन का अनुसरण किया जाए।
- मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं और वृद्धि की गति का अतिक्रमण करते हुए विकास मांग और वैश्विक एवं देशी स्थिति के लिए उपयुक्त रूप में सभी संभव उपायों के साथ तीव्रतापूर्वक प्रतिसाद किया जाए।

2.63 मौद्रिक नीति के संचयी और पिछड़े प्रभावों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने 2004 के मध्य में, उस समय मुद्रास्फीति सहन सीमा के भीतर होने के बावजूद, निभाव का क्रमिक आहरण शुरू किया। सितंबर 2004 से रिपो/रिवर्स रिपो दरों में 175/150 आधार अंकों की तथा सीआरआर में 200 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। विशिष्ट क्षेत्रों में बैंकों के एक्सपोजर को देखते हुए मानक अग्रिमों के लिए सामान्य

प्रावधानीकरण अपेक्षाओं और जोखिम भारांकों को बढ़ा दिया गया है। मौद्रिक नीति का रुख क्रमिक रूप से बदलकर वृद्धि के साथ मूल्य स्थिरता पर समान बल देने के बजाय तात्कालिक मौद्रिक उपायों के साथ मूल्य स्थिरता पर बल देना और विकासमान परिस्थितियों के प्रतिसाद में त्वरित रूप से सभी संभव उपायों का आश्रय लेना हो गया।

2.64 मौद्रिक नीति के रुख के अनुसरण में खजाना बिलों और दिनांकित प्रतिभूतियों के संमिश्र को एमएसएस के तहत अधिक लचीले रूप में जारी करने का आवर्धित कार्यक्रम शुरू करने के लिए 2 मार्च 2007 को चलनिधि प्रबंधन को आशोधित किया गया। वर्धित एमएसएस कार्यक्रम तथा अत्यंत अल्पकालिक असंतुलनों को संतुलित करने की सुविधा के रूप में एलएएफ के संचालन की जरूरत को देखते हुए 5 मार्च 2007 से दैनिक रिवर्स रिपो अवशोषणों को 3000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा तक सीमित किया गया। प्रचलित समष्टि आर्थिक, मौद्रिक एवं प्रत्याशित चलनिधि स्थितियों को देखते हुए तथा मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 30 मार्च 2007 से एलएएफ के तहत स्थिर रिपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की तथा 14 अप्रैल 2007 एवं 28 अप्रैल 2007 से दो चरणों में सीआरआर में 50 आधार अंकों की वृद्धि की। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति में निभाव को हटाने की प्रक्रिया का बलपूर्वक अनुसरण किया जा रहा है। फरवरी 2007 के मध्य से, अग्रणी केंद्रीय बैंकों में से यूरोपीयन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान में से प्रत्येक ने प्रमुख नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि की, जबकि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक साल की बेंचमार्क उधार दर में 45 आधार अंकों की (मार्च 2007 में 27 आधार अंकों तथा मई 2007 में 18 आधार अंकों की) तथा आरक्षित निधि अपेक्षाओं में 150 आधार अंकों की (5 जून 2007 से प्रभावी 50 आधार अंकों की वृद्धि सहित) वृद्धि की। यूएस फडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा तथा रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया की नीति दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा इनमें से सभी ने पूर्व नीतिगत कार्रवाई की थी।

आरक्षित मुद्रा का सर्वेक्षण

2.65 आरक्षित मुद्रा में 31 मार्च 2007 को साल-दर-साल 23.7 प्रतिशत की वृद्धि एक वर्ष पूर्व की 17.2 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक थी। सीआरआर में वृद्धि के प्रभाव को समयोजित करने पर 31 मार्च 2007 को आरक्षित मुद्रा का विस्तार 18.9 प्रतिशत था। आरक्षित मुद्रा में विस्तार की अगुवाई मुख्यतः रिजर्व बैंक की चालू विदेशी आस्तियों ने की जिसमें पिछले वर्ष के 68,834 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 2006-07 में 1,64,601 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, केंद्र को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में पिछले वर्ष की 28,417 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 2006-07 में 1,042 करोड़ रुपए की गिरावट आयी (सारणी 2.26)। 2006-07 में केंद्र को भारतीय रिजर्व

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.26 : आरक्षित मुद्रा

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	31 मार्च 2007 को बकाया	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़					
		2005-06	2006-07	2006-07			
				ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा	7,08,950	83,922 (17.2)	1,35,892 (23.7)	13,470	18,666	14,210	89,546
घटक (1+2+3)							
1. संचलन में करैसी	5,04,167	62,015 (16.8)	73,491 (17.1)	22,283	-2,011	26,871	26,348
2. रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	1,97,295	21,515 (18.9)	61,784 (45.6)	-7,204	20,224	-12,165	60,929
3. रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	7,487	393 (6.1)	617 (9.0)	-1,610	453	-495	2,269
प्रोत (1+2+3+4-5)							
1. रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को निवल ऋण	4,362	26,111	-3,775	53	2,826	-12,754	6,100
उसमें से : केंद्र को (i+ii+iii+iv-v)	4,118	28,417	-1,042	3,071	2,584	-12,568	5,871
i. ऋण तथा अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0
ii. भा.रि.बैंक द्वारा धारित राजकोषीय बिल	0	0	0	0	0	0	0
iii. भा.रि.बैंक की दिनांकित प्रतिभूतियों की धारिता	97,172	13,869	26,763	-27,610	24,944	22,733	6,696
iv. भा.रि.बैंक की रुपए सिक्कों की धारिता	12	7	-143	9	-107	97	-142
v. केंद्र सरकार की जमा राशियां	93,066	-14,541	27,662	-30,672	22,253	35,398	683
2. भा.रि.बैंक द्वारा बैंक तथा वाणिज्य क्षेत्र को ऋण	9,173	535	1,990	-3,135	3,107	2,065	-47
3. भा.रि.बैंक का एनएफईए	8,66,153	60,193 (9.8)	1,93,170 (28.7)	71,845	11,392	27,250	82,682
जिसमें से: एफसीए, पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित	-	68,834	1,64,601	28,107	10,948	31,634	93,913
4. सरकार की जनता के प्रति मुद्रा देयताएं	8,229	1,306	-525	-920	155	166	75
5. भा.रि.बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1,78,967	4,222	54,968	54,373	-1,186	2,517	-736
जापन:							
निवल देशी आस्तियां	-1,57,203	23,729	-57,277	-58,376	7,274	-13,040	6,864
रिजर्व बैंक का दिनांकित प्रतिभूतियों में प्राथमिक अंशदान	0	10,000	0	0	0	0	0
एलएएफ, रेपो (+) / रिवर्स रेपो (-)	29,185	12,080	36,435	-23,060	28,395	22,195	8,905
खुले बाजार में निवल बिक्री # *	-	3,913	5,125	1,536	1,176	389	2,024
एमएसएस के अंतर्गत संग्रहण *	62,974	-35,149	33912	4,062	8,940	-3,315	24,225
निवल खरीद (+) / बिक्री (-) प्राथमिक व्यापारी से	-	32,884	1,18,994	21,545	0	19,776	77,673
एनएफईए / रिजर्व मुद्रा £	122.2	117.4	122.2	127.0	125.0	126.5	122.2
एनएफईए / मुद्रा £	171.8	156.3	171.8	164.4	167.7	164.0	171.8
एनएफईए : निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	एफसीए : विदेशी मुद्रा आस्तियां	एलएएफ : चलनिधि समायोजन सुविधा					
* : अंकित मूल्य पर	# : राजकोषीय बिलों को छोड़कर	£ : प्रतिशत, अवधि के अंत में					
नोट :							
1. ति. 4 के आंकड़े 31 मार्च के हैं और अन्य तिमाहियों के आंकड़े रिपोर्ट करने के लिए नियत शुक्रवार के हैं।							
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं।							
3. 31 मार्च 2007 की सरकार की शेष राशियां लेखाबंदी से पहले की हैं।							

बैंक के निवल ऋण में आयी गिरावट का कारण केंद्र की उच्चतर जमा राशियां थीं जिसने, बदले में, एमएसएस के तहत प्रतिभूतियों का नया निर्गम दर्शाया। अंशतः सीआरआर में वृद्धि के कारण रिजर्व बैंक के साथ बैंकरों की जमा राशियों में वृद्धि हुई।

2.66 आरक्षित मुद्रा में साल-दर-साल विस्तार एक वर्ष पूर्व के 17.1 प्रतिशत की तुलना में 18 मई 2007 को 23.6 प्रतिशत (सीआरआर में

वृद्धि के लिए समायोजित 16.3 प्रतिशत) हुआ। रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में (पुनर्मूल्यन के लिए समायोजित) साल-दर-साल आधार पर एक वर्ष पूर्व के 90,841 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 18 मई 2007 को 1,55,105 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। केंद्र को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में एक वर्ष पूर्व के 8,458 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में 4,414 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.27 : मौद्रिक संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 31, 2007 को बकाया	घट-बढ़			
		2005-06		2006-07	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
I. आरक्षित मुद्रा	7,08,950	83,922	17.2	1,35,892	23.7
II. संकीर्ण मुद्रा (एम ₁)	9,59,875	1,43,825	21.1	1,33,497	16.2
III. व्यापक मुद्रा (एम ₃)	32,96,919	3,96,881	17.0	5,67,372	20.8
क) जनता के पास मुद्रा	4,84,171	58,248	16.4	71,052	17.2
ख) कुल जमाराशियाँ	28,05,261	3,38,081	17.1	4,95,704	21.5
i) माँग जमाराशियाँ	4,68,216	85,025	26.5	61,829	15.2
ii) मीयादी जमाराशियाँ	23,37,045	2,53,056	15.3	4,33,875	22.8
उसमें से: अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ	66,242	-16,876	-22.2	6,967	11.8
IV. एनएम ₃	33,06,958	4,21,126	18.1	5,59,370	20.4
उसमें से: वित्तीय संस्थाओं से माँग मीयादी निर्धन	86,151	11,224	15.6	3,007	3.6
V. क) एल ₁	34,21,762	4,36,397	18.1	5,70,256	20.0
उसमें से: डाक जमाराशियाँ	1,14,804	15,271	17.2	10,886	10.5
ख) एल ₂	34,24,694	4,37,206	18.1	5,70,256	20.0
ग) एल ₃	34,50,758	4,41,207	18.1	5,72,479	19.9
VI. व्यापक मुद्रा के प्रमुख घटक					
क) सरकार को निवल बैंक ऋण (i+ii)	8,32,867	17,888	2.4	66,272	8.6
i) सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	4,362	35,799		-3,775	
ii) सरकार को अन्य बैंक ऋण	8,28,505	-17,910	-2.3	70,046	9.2
ख) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	21,23,290	3,61,746	27.2	4,30,287	25.4
ग) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	9,30,319	78,291	12.1	2,04,125	28.1
जापन: अ.वा.बैंकों की सकल जमाराशि	25,94,259	3,23,913	18.1	4,85,210	23.0
अ.वा.बैंकों का खाद्येतर ऋण	18,76,672	3,54,193	31.8	4,10,285	28.0

अ.वा.बैं : अनुसूचित वाणिज्य बैंक

एनएम₃ आवासीय व्यापक मुद्रा समुच्चय है तथा एल₁, एल₂ और एल₃ मुद्रा आपूर्ति संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष: डॉ. वाइ.वी.रेड्डी, 1998) की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित चलनिधि संबंधी समुच्चय हैं। चलनिधि समुच्चयों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

एल₁ = एनएम₃ + डाक घर बचत बैंकों की चुनिंदा जमाराशियाँ एल₂ = एल₁ + मीयादी ऋणदाता संस्थाओं तथा पुनर्वित्त संस्थाओं के पास मीयादी जमाराशियाँ + वित्तीय संस्थाओं द्वारा मीयादी उधारियाँ + वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र। एल₃ = एल₂ + गैर बैंकिंग द्वितीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियाँ

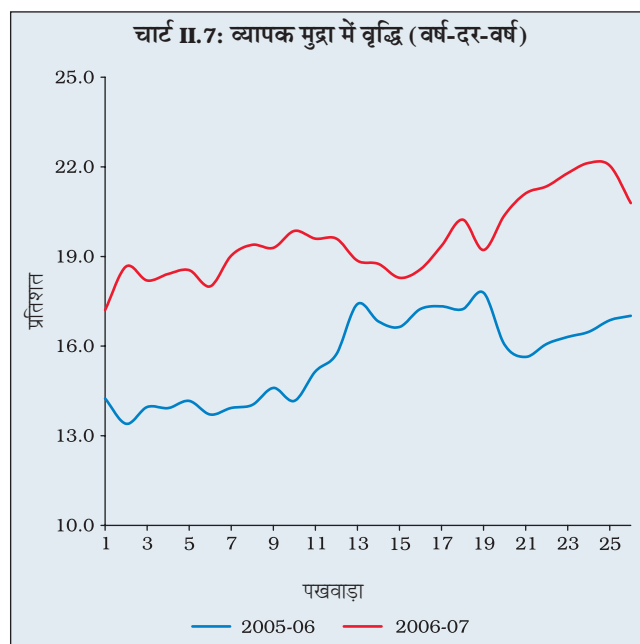
टिप्पणी: 1. आंकड़े अंतिम हैं।

- आंकड़ों में 29 दिसंबर 2005 को किए गए इंडिया मिलेनियम डिफाइज्ड के शोधन की राशि शामिल है।
- 31 मार्च 2007 की सरकार की शेष राशि लेखाबंदी से पहले की है।
- वर्ष 2006-07 के दौरान की घट-बढ़ 31 मार्च 2006 से तथा वर्ष 2005-06 की घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से हिसाब में ली गई है।
- डाकघर की जमाराशियों के आंकड़े फरवरी 2007 के हैं।

मौद्रिक सर्वेक्षण

2.67 स्थूल मुद्रा (एम₃) की वृद्धि पिछले वर्ष के 17.0 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2007 को साल-दर-साल 20.8 प्रतिशत थी (सारणी 2.27 तथा चार्ट II.7)। इस प्रकार एम₃ में वृद्धि अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में निर्धारित 15.0 प्रतिशत (साल-दर-साल) के प्रक्षेपण के ऊपर बनी रही।

2.68 उच्चतर आवधिक जमाराशियों के समर्थन से बैंकों की समस्त जमाराशियों में वृद्धि हुई। माँग जमाराशियों में एक वर्ष पूर्व के 26.5 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 31 मार्च 2007 को 15.2 प्रतिशत (साल-दर-साल) की वृद्धि दर्ज की गई। आवधिक जमाराशियों में एक वर्ष पूर्व के 15.3 प्रतिशत की तुलना में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतर ब्याज दरों और 5 वर्ष एवं उससे ऊपर की परिपक्वता वाली जमाराशियों के लिए मिलने वाले कर लाभों का परिणाम था। सहवर्ती रूप में, डाक जमाराशियों में एक वर्ष पूर्व के 17.2 प्रतिशत की तुलना में साल-दर-साल, फरवरी 2007 के अंत में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

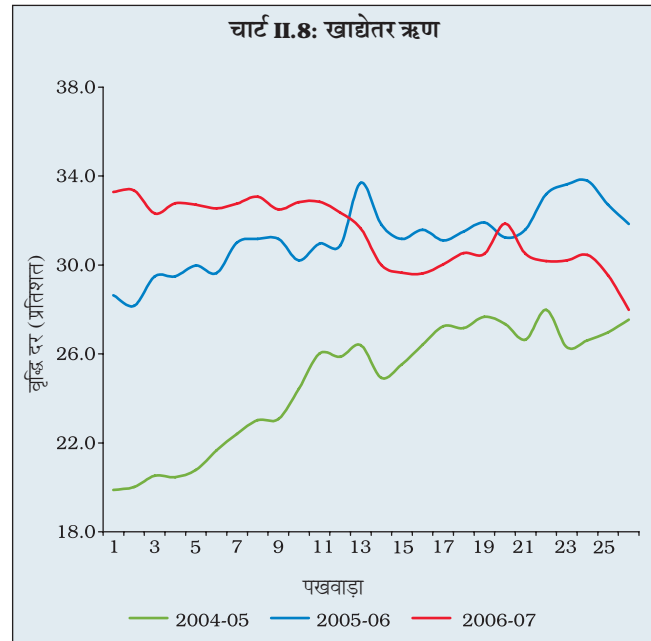


2.69 स्थूल मुद्रा (एम₃) में वृद्धि एक वर्ष पूर्व के 18.2 प्रतिशत की तुलना में 11 मई 2007 को 20.2 प्रतिशत (साल-दर-साल) थी। प्रमुख घटकों में, कुल जमाराशियों में वृद्धि एक वर्ष पूर्व के 18.6 प्रतिशत की तुलना में 21.1 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण

2.70 बैंक ऋण की मांग 2006-07 में सुदृढ़ बनी रही, अलबत्ता इसमें कुछ मंदी रही। 30 मार्च 2007 को, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदान किये खाद्येतर ऋण में 31 मार्च 2006 के 31.8 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर 28.0 प्रतिशत (साल-दर-साल) की वृद्धि हुई। 2006-07 के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.28 और चार्ट II.8)। तथापि, बैंकों के एसएलआर निवेशों में वृद्धि उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं की तुलना में कम थी। फलस्वरूप, वाणिज्य बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों की धारिताएं मार्च 2006 के अंत के 31.3 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 28.0 प्रतिशत रह गयीं।

2.71 बैंक ऋण के क्षेत्रवार विनियोजन संबंधी अनंतिम सूचना यह दर्शाती है कि ऋण में वृद्धि का आधार काफी व्यापक था। उद्योग और कृषि को ऋण की साल-दर-साल वृद्धि जनवरी 2007 के अंत में क्रमशः 28.8



प्रतिशत और 30.4 प्रतिशत थी। औद्योगिक कार्यकलाप में उछाल के अनुरूप औद्योगिक ऋण में वृद्धि मुख्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर (पावर, सड़क, बंदरगाह, दूरसंचार आदि), धातुओं, वस्त्रों, पेट्रोलियम, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग के कारण थी। आवास क्षेत्र और वाणिज्यिक भूसंपदा को ऋण की स्थिति सुदृढ़ बनी रही (सारणी 2.29)।

सारणी 2.28 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सर्वेक्षण

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	30 मार्च 2007 को बकाया राशि	घट-बढ़			
		31 मार्च 2006 को		30 मार्च 2007 को	
		सकल राशि	प्रतिशत	सकल राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
निधियों के स्रोत					
1. सकल जमाराशि	25,94,259	3,23,913	18.1	4,85,210	23.0
2. वित्तीय संस्थाओं से मांग/मीयादी वित्तपोषण	86,151	11,224	15.6	3,007	3.6
3. विदेशी मुद्रा में लिए गए अपतटीय ऋण	32,377	1,295	4.5	2,543	8.5
4. पूंजी	33,868	5,705	21.2	1,254	3.8
5. आरक्षित निधि	1,66,290	34,616	31.3	21,177	14.6
निधियों का उपयोग					
1. बैंक ऋण	19,23,192	3,54,868	30.8	4,16,115	27.6
जिसमें से: खाद्येतर ऋण	18,76,672	3,54,193	31.8	4,10,285	28.0
2. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	7,71,060	-19,514	-2.7	70,318	10.0
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	21,100	-3,295	-16.5	4,388	26.3
4. गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश	1,43,750	-11,838	-8.0	8,410	6.2
5. विदेशी मुद्रा आस्तियां	39,287	14,059	47.8	-4,207	-9.7
6. भा.रि. बैंक के पास शेष राशि	1,80,222	34,077	36.6	53,161	41.8
नोट : आंकड़े अनंतिम हैं।					

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.29 : खाद्येतर बैंक ऋण का विनियोजन

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र / उद्योग	19 जनवरी 2007 को बकाया राशि	वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़			
		2005-06 *		2006-07**	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4 तक)	16,47,521	2,56,580	25.7	3,84,187	30.4
1. कृषि और बद्ध गतिविधियाँ	2,01,927	28,089	22.4	47,044	30.4
2. उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े)	6,34,804	66,480	15.6	1,41,774	28.8
लघु उद्योग	1,03,089	7,453	10.0	20,179	24.3
3. वैयक्तिक ऋण	4,34,860	68,386	27.9	1,03,587	31.3
गृह निर्माण	2,21,072	37,431	29.1	46,501	26.6
मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम	35,627	2,378	8.0	3,517	11.0
क्रेडिट कार्ड	12,307	3,072	53.3	3,749	43.8
शिक्षा	13,910	3884	75.9	4,742	51.7
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8,731	-220	-2.4	1,690	24.0
4. अन्य सेवाएं	3,75,930	12,049	39.4	91,782	32.3
यातायात परिचालक	23,179	1,990	20.7	10,045	76.5
प्रोफेशनल व अन्य	19,377	1,513	11.4	5,252	37.2
व्यापार	99,460	13,975	24.1	24,135	32.0
स्थावर संपदा ऋण	40,790	11,225	84.4	17,899	78.2
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	41,093	6,023	26.8	10,653	35.0
ज्ञापन:					
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	5,75,282	78,172	20.5	1,11,551	24.1
उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े)	6,34,804	66,480	15.6	1,41,774	28.8
खाद्य प्रसंस्करण	35,619	3,878	15.9	7,675	27.5
वस्त्र	71,274	8,989	20.4	17,849	33.4
कागज और कागज उत्पाद	10,416	1,650	24.0	1,882	22.1
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और न्यूक्लियर ईंधन	33,991	2,203	14.1	15,399	82.8
रसायन और रासायनिक उत्पाद	51,073	5,265	13.3	6,880	15.6
रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	8,318	2,403	65.5	2,141	34.7
लोहा और इस्पात	59,356	7,841	21.8	15,096	34.1
अन्य धातु और धातु उत्पाद	20,261	2,046	17.6	6,460	46.8
अभियांत्रिकी	39,741	2,913	9.9	7,212	22.2
वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण	19,311	4,964	41.8	2,483	14.8
रत्न और आभूषण	22,249	4,276	29.9	3,053	15.9
निर्माण	17,131	3,696	45.5	5,550	47.9
इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,28,405	22,717	28.8	27,162	26.8

* : 28 जनवरी 2005 की तुलना में 20 जनवरी 2006।

** : 20 जनवरी 2006 की तुलना में 19 जनवरी 2007।

नोट : 1. आंकड़े अनंतिम हैं तथा ये चुनिंदा वाणिज्य बैंकों के हैं।

2. क्षेत्रों / उद्योगों के वर्गीकरण तथा बैंकों के कवरेज में परिवर्तन के कारण 2006 के आंकड़े पिछले आंकड़ों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

2.72 बैंक ऋण के अलावा, कंपनी क्षेत्र 2006-07 के दौरान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए निधियों के बैंकेतर स्रोतों पर निर्भर रहा। 2006-07 के दौरान, विदेश में ईक्विटी जारी करके (एडीआर/जीडीआर) संसाधन जुटाने में एक वर्ष पूर्व के स्तर से दुगुने से अधिक की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान, बाह्य वाणिज्यिक उधारों में ऋण प्रवाहों का आश्रय भी एक वर्ष पूर्व की तुलना में उच्चतर था। निधियों के आंतरिक

स्रोतों ने अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान कंपनी क्षेत्र को सुदृढ़ समर्थन देना जारी रखा (सारणी 2.30)।

2.73 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खाद्येतर ऋण में एक वर्ष पूर्व के 32.3 प्रतिशत के ऊपर 11 मई 2007 को 27.2 प्रतिशत (साल-दर-साल) की वृद्धि दर्ज की गयी, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश में 9.5 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 2.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

सारणी 2.30 : उद्योग के लिए निधियों के चुनिंदा स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	2005-06	2006-07
1	2	3
अ. उद्योग को बैंक ऋण #	1,27,192 (66,244) *	74,981 *
आ. गैर बैंकों से कंपनियों को प्रवाह		
1. पूंजी निर्गम (i+ii)	13,781	29,180
i) गैर- सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां (क + ख)	13,408	29,180
क) बंधपत्र / डिबेंचर	245	585
ख) शेयर	13,163	28,595
ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी कंपनियाँ	373	0
2. एडीआर/जीडीआर निर्गम	7,263	16,184
3. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)	45,078 (27,228) *	48,328 *
4. वाणिज्यिक पत्रों का निर्गम	-1,517	4,970
इ. मूल्यहास प्रावधान +	28,883 (22,044) *	24,557 *
ई. करोत्तर लाभ +	67,506 (52,891) *	75,460 *

: आंकड़े चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं। 2005-06 के आंकड़े नमूने के तौर पर लिए गए चुनिंदा बैंकों की संख्या में वृद्धि के कारण 2006-07 के साथ तुलनीय नहीं हैं।
+ : आंकड़े गैर वित्तीय गैर सरकारी कंपनियों के चुनिंदा नमूने के लेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित संक्षिप्त परिणामों पर आधारित हैं।
* : आंकड़े अप्रैल-दिसंबर से संबंधित हैं।

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. पूंजी निर्गम के आंकड़े सकल निर्गम से संबंधित हैं जिसमें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निर्गम शामिल नहीं हैं। पूंजी निर्गम में बैंकों के निवेश के लिए वे आंकड़े समायोजित नहीं किए गए हैं, जो उल्लेखनीय नहीं हैं।
3. एडीआर/जीडीआर निर्गम के आंकड़ों में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के निर्गम शामिल नहीं हैं।
4. बाह्य वाणिज्यिक उधार के आंकड़ों में अल्पावधि ऋण शामिल है। 2005-06 के आंकड़ों में आइएमडी शोधन शामिल नहीं है।

मूल्य की स्थिति

2.74 प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति 2006-07 के दौरान मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के अनुरूप रही। अगस्त 2006 तक हेडलाइन मुद्रास्फीति कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के अनुरूप तेज बनी रही तथा सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान आधार प्रभावों और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तीव्र

गिरावट के कारण वह नरम रही (सारणी 2.31 और चार्ट II.9)। तथापि, दिसंबर 2006 - मार्च 2007 में इसमें पुनः वृद्धि हुई। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मूल मुद्रास्फीति सुदृढ़ बनी रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (खाद्यान्न और ऊर्जा को छोड़कर) मार्च 2007 में अमरीका में 2.5 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 2.1 प्रतिशत) तथा मार्च 2007 में ओईसीडी देशों में 2.1 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 1.6 प्रतिशत) रही।

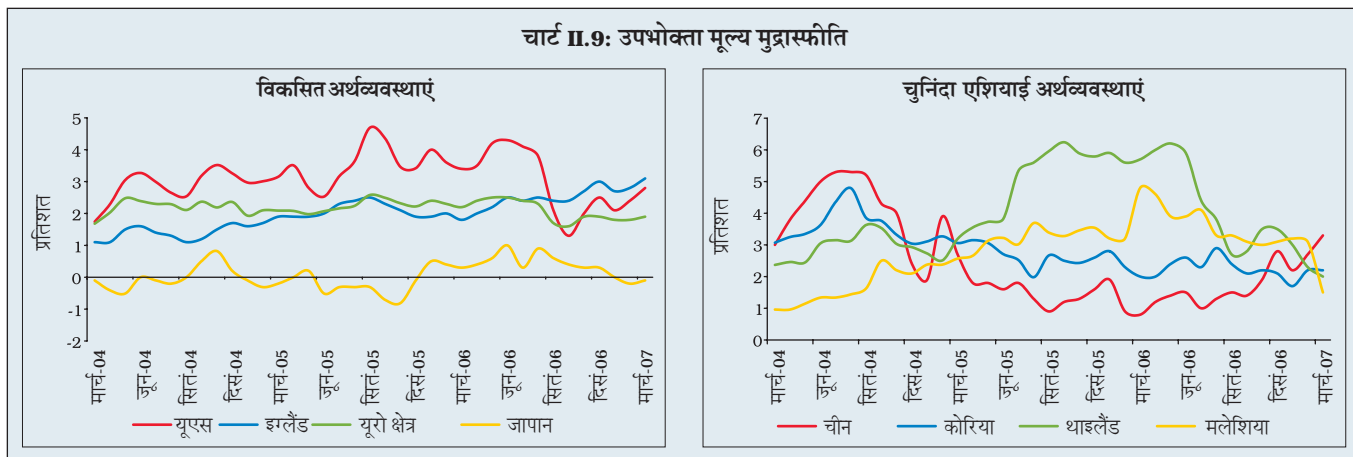
सारणी 2.31 : वार्षिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

(प्रतिशत)

देश/क्षेत्र	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 पी
1	2	3	4	5	6	7	8
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	2.1	1.5	1.8	2.0	2.3	2.3	1.8
यूएस	2.8	1.6	2.3	2.7	3.4	3.2	1.9
जापान	-0.8	-0.9	-0.2	-	-0.6	0.2	0.3
यूरो क्षेत्र	2.4	2.3	2.1	2.1	2.2	2.2	2.0
अन्य उभरते बाजार और विकासशील देश	6.7	5.8	5.8	5.6	5.4	5.3	5.4
विकासशील एशिया	2.7	2.0	2.5	4.1	3.6	4.0	3.9
चीन	0.7	-0.8	1.2	3.9	1.8	1.5	2.2
भारत	3.8	4.3	3.8	3.8	4.2	6.1	6.2

पी : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुमान
स्रोत: वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2007, आइएमएफ।

चार्ट II.9: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

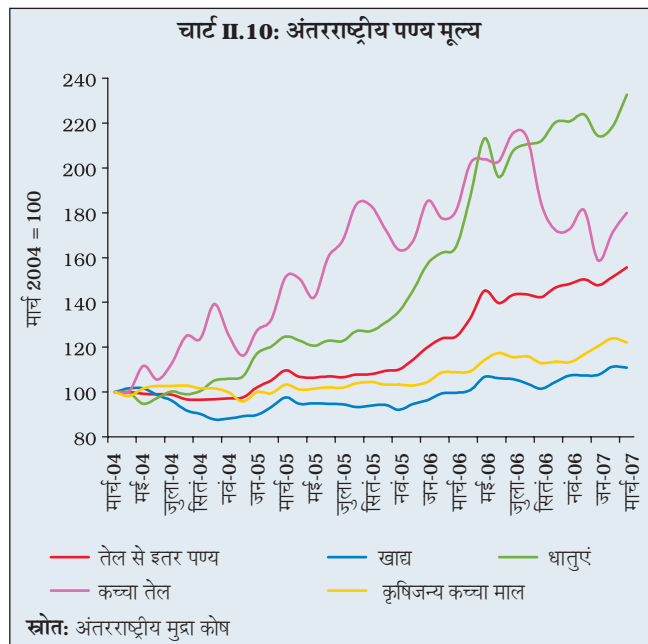


2.75 सुदृढ़ मांग को दर्शाते हुए, तेल से इतर अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें ऊँचे स्तरों पर रहीं। 2006-07 के दौरान धातुओं की कीमतों में तेजी आयी जो व्यापक तौर पर सटोरिया हित के बीच तेज मांग और आपूर्ति संबंधी अवरोधों को प्रतिबिंबित करती है (चार्ट II.10)। खाद्य मर्दों में, मार्च 2007 में (साल-दर-साल) गेहूँ की कीमतें 14 प्रतिशत ऊपर रहीं, जो व्यापक तौर पर वैश्विक उत्पादन में कमी और उपयोग में सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाता है। खाद्य तेलों की कीमतों में भी वृद्धि हुई, मार्च 2007 में (साल-दर-साल) पाम आइल में 41.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सोयाबीन तेल में 33.2 प्रतिशत की। दूसरी ओर, कच्चे तेल की कीमतें 14 जुलाई 2006 के 78.4 अमरीकी डॉलर की ऐतिहासिक ऊँचाई से नरम होकर जनवरी 2007 में वैश्विक मांग में कमी, अमरीकी स्टॉक में वृद्धि और अमरीका में कम सर्दी के कारण लगभग 51 अमरीकी डॉलर

प्रति बैरल हो गयीं। तथापि, जनवरी 2007 के अंतिम सप्ताह से पुनः बढ़कर कच्चे तेल की कीमतें मार्च 2007 के अंत तक लगभग 67 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो गयीं। हाल के महीनों में चीनी की कीमतों में नरमी आयी, जो उत्पादन की संभावनाओं में सुधार को दर्शाता है।

2.76 मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को नियंत्रित करने के लिए 2006-07 और 2007-08 (अप्रैल-मई) में कई केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति में सख्ती लायी। यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति में कुछ नरमी आने के बावजूद मूल्य बढ़ने की संभावना का जोखिम था, जिसके कारण थे - तेल की कीमतों में और वृद्धि की संभावना, प्रशासित मूल्यों एवं अप्रत्यक्ष करों में अतिरिक्त वृद्धि तथा वर्तमान में संभावित से अधिक मजदूरी संबंधी गतिविधियां। अतः यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने यूरो क्षेत्र में मध्यावधि से दीर्घावधि मुद्रास्फीति संभावनाओं को मूल्य स्थिरता के अनुरूप स्तर पर नियंत्रित रखने के लिए जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 2006 में से प्रत्येक में प्रमुख नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की - दिसंबर 2005 से कुल 175 आधार अंकों की वृद्धि। यूके में, सुदृढ़ आर्थिक कार्यकलाप, सीमित स्पेयर क्षमता, स्थूल मुद्रा और ऋण की तेज वृद्धि, आस्ति कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं के निकट अवधि में लक्ष्य से ऊपर रहने को देखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अगस्त और नवंबर 2006 तथा जनवरी और मई 2007 में हुए हर बार नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे 5.50 प्रतिशत कर दिया (सारणी 2.32)। सुदृढ़ आर्थिक कार्यकलाप और मुद्रास्फीति के अंतर्निहित दबावों के प्रतिसाद में रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया ने नवंबर 2006 में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे 6.25 प्रतिशत - मई 2006 से कुल 75 आधार अंकों की वृद्धि-कर दिया। विस्तारित अवधि तक शून्य प्रतिशत, ब्याज दर बनाये रखने के बाद, बैंक ऑफ जापान ने असंपाश्वर्कृत दिन भर की मांग दर (जिसे मार्च 2006 से मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के रूप में अपनाया गया) को जुलाई 2006 और फरवरी 2007 में हर बार 25 आधार अंक बढ़ाकर उसे 0.50 प्रतिशत कर दिया। दूसरी ओर, जून 2004 और जून

चार्ट II.10: अंतरराष्ट्रीय पण्य मूल्य



सारणी 2.32 : वैश्विक मुद्रास्फीति संकेतक

(प्रतिशत)

देश/क्षेत्र	प्रमुख नीतिगत दरें	नीतिगत दर (19 मई 2007 को)	नीतिगत दर में परिवर्तन (आधार अंक)		सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)		वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)	
			मार्च 2005 के अंत से	मार्च 2006 के अंत से	2006 (मार्च)	2007 (मार्च)	2005 (ति4)	2006 (ति4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विकसित अर्थव्यवस्थाएं								
आस्ट्रेलिया	कैश रेट	6.25 (8 नव. 2006)	75	75	3.0	2.4	2.7	2.8
कनाडा	ओवरनाइट रेट	4.25 (24 मई 2006)	175	50	2.2	2.3	2.9	2.3
यूरो क्षेत्र	प्रमुख पुनर्वित्त परिचालनों पर ब्याज दर	3.75 (8 मार्च 2007)	175	125	2.2	1.9	1.7	3.3
जापान	अनकोलेटेराइज्ड ओवरनाइट कॉल रेट	0.50 (21 फर. 2007)	**	50	-0.2	-0.1	4.0	2.3
यूके	ऑफिसियल बैंक रेट	5.50 (10 मई 2007)	75	100	1.8	3.1	1.8	3.0
यूएस	फेडरल फंड्स रेट	5.25 (29 जून 2006)	250	50	3.4	2.8	3.2	3.1
विकासशील अर्थव्यवस्थाएं								
ब्राजील	सेलिक रेट	12.50 (18 अप्रै. 2007)	(-)675	(-)400	5.3	3.0	1.4	3.8
भारत	रिवर्स रेपो रेट	6.00 (25 जुला. 2006)	125	50	4.9	6.7	9.3	8.6
	रेपो रेट	7.75 (30 मार्च 2007)	175	125				
चीन	1 वार्षिक बेंचमार्क लेंडिंग रेट	6.57 (19 मई 2007)	99	99	0.8	3.3	9.9	10.7
इंडोनेशिया	बीआइ रेट	8.75 (8 मई 2007)	25@	(-)400	15.8	6.5	4.9	6.1
इजराइल	की रेट	3.75 (22 अप्रै. 2007)	25	(-)100	3.6	-0.9	4.8	3.7
कोरिया	ओवरनाइट कॉल रेट	4.50 (10 अग. 2006)	125	50	2.0	2.2	5.3	4.0
फिलीपींस	रिवर्स रेपो रेट	7.50 (20 अक्टू. 2005)	75	0	7.6	2.2	6.1	6.5
दक्षिण अफ्रीका	रेपो रेट	9.00 (8 दिसं. 2006)	150	200	3.4	6.1	4.5	6.1
थाइलैंड	14 दिवसीय पुनर्खरीद दर	5.00 (7 जून 2006)	275	50	5.7	2.0	4.7	4.2
	1 दिवसीय पुनर्खरीद दर	4.00 (11 अप्रै. 2007)	—	(-)94 ^				

** : बैंक ऑफ जापान ने 1 मार्च 2006 से मुद्रा बाजार के परिचालनगत लक्ष्य को बैंक में चालू खाते में स्थित बकाया शेष राशि से बदलकर असंपाश्वर्कृत ओवरनाइट मांग दर करने का निर्णय लिया।

@ : यह परिवर्तन जुलाई 2005 से हुआ जब बैंक इंडोनेशिया ने मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण को औपचारिक तौर पर स्वीकार करते हुए बीआइ रेट को संदर्भ दर के रूप में स्वीकार किया।

^ : 16 जनवरी 2007 से परिवर्तित। 17 जनवरी 2007 से 14 दिवसीय पुनर्खरीद दर को नीति दर के रूप में स्वीकार किया गया।

नोट : 1. भारत के संदर्भ में मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हैं।
2. कॉलम (3) में कोष्ठकों में दी गई तारीख वह तारीख है जब नीति दर में पिछली बार परिवर्तन किया गया था।

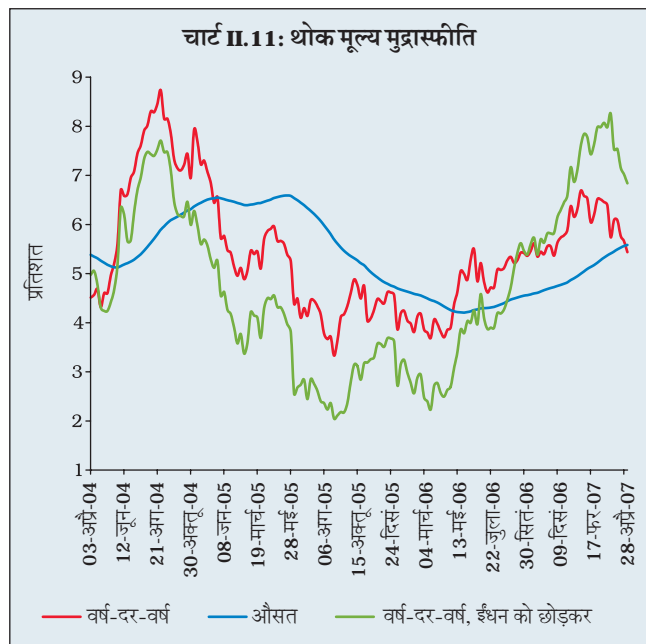
स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संबंधित केंद्रीय बैंक की वेबसाइट तथा इकॉनॉमिस्ट।

2006 के बीच लगातार 17 बार हर बार लक्षित फेडरल निधि दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके यूएस फेड रुक गया क्योंकि आर्थिक वृद्धि अपनी काफी सुदृढ़ गति से कम हो गयी जो अंशतः आवास बाजार में

सुस्ती को दर्शाता है। यूएस फेड ने संकेत दिया है कि आने वाली सूचना के निहितार्थ के अनुसार भविष्य के नीतिगत समायोजन मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि दोनों के लिए संभावना के विकास पर निर्भर होंगे।

2.77 उभरते एशिया की कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर अपेक्षतया सामान्य रही जो पूर्वोपायी मौद्रिक सख्ती तथा विनिमय दर में वृद्धि की ओर इंगित करता है। तथापि, विशेष रूप से बाहर से बड़ी मात्रा में पूंजी आगम के चलते अतिरिक्त चलनिधि संबंधी चिंताएं बरकरार हैं। चीन में उपभोक्ता वस्तु मुद्रास्फीति एक वर्ष पूर्व के 0.8 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर मार्च 2007 में 3.3 प्रतिशत हो गई। मुद्रा आपूर्ति तथा ऋण में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए पिपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2006, अगस्त 2006, मार्च 2007 में प्रत्येक बार उधार दर में 27 आधार अंक की, तथा मई 2007 में 18 आधार अंक की वृद्धि के साथ ही नई परियोजनाओं के अनुमोदन में प्रशासनिक रोक भी लगाई। उसने जुलाई 2006 से आरक्षित नकदी निधि अनुपात में आठ चरणों में 400 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे 11.50 प्रतिशत (5 जून 2007 से लागू होनेवाली 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी सहित) तक बढ़ाया। एशिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कोरिया ने अगस्त 2006 से अपनी दरें अपरिवर्तित रखीं। दूसरी ओर, वृद्धि को समर्थन देने के लिए थाइलैंड ने नीतिगत दरों में 94 आधार अंकों की (जनवरी 2007 से) तथा इंडोनेशिया ने 400 आधार अंकों की (मई 2006 से) कटौती की।

2.78 भारत में थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन के आधार पर मापी जाने वाली हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर, एक वर्ष पूर्व के 4.0 प्रतिशत के मुकाबले 31 मार्च 2007 को समाप्त सप्ताह के दौरान 5.7 प्रतिशत थी। औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (52 सप्ताह का औसत) एक वर्ष पूर्व के 4.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07 में 5.4 प्रतिशत थी (चार्ट II.11)। आपूर्ति तथा मांग दोनों पक्षों के दबावों के प्रभाव को प्रतिबिंबित करते हुए वर्ष 2006-07 में मुद्रास्फीति में जो उतार-चढ़ाव हुआ वह प्राथमिक खाद्य वस्तुओं तथा विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव से संचालित था।



2.79 प्राथमिक वस्तुओं, विशेष रूप से गेहूं, दालें, दूध, तिलहन तथा कपास की कीमतों में वृद्धि के चलते वर्ष 2006-07 में हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई (सारणी 2.33)। देश में गेहू का स्टॉक कम होने तथा ऊंची अंतरराष्ट्रीय कीमत के चलते गेहू की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलू उत्पादन में मंदी को प्रतिबिंबित करते हुए दाल की कीमतों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूध की कीमतों में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिलहन की कीमतों में, एक वर्ष पूर्व 9.2 प्रतिशत की कमी के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप 30.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समग्र रूप में, प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में 31 मार्च 2007 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.7 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 4.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.80 31 मार्च 2007 को इंधन समूह में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मुद्रास्फीति की दर, पिछले वर्ष के 8.3 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 1.0 प्रतिशत रह गई। 6 जून 2006 को पेट्रोल तथा डीजल की घरेलू कीमतों में वृद्धि के चलते 17 जून 2006 को ईंधन समूह में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 9.9 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गई। बाद में, आधार वर्ष प्रभाव तथा नवंबर 2006 और फरवरी 2007 में पेट्रोल व डीजल की घरेलू कीमतों में कमी के चलते ईंधन समूहों की मुद्रास्फीति में कमी आई। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि तेल की उच्चतर अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर पेट्रोल व डीजल तक सीमित रहा। सामाजिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए नवंबर 2004 से एलपीजी की तथा अप्रैल 2002 से मिट्टी के तेल की घरेलू कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

2.81 मुख्य रूप से खाद्य तेल/खली, सीमेंट, धातु तथा इलेक्ट्रिकल मशीनरी की कीमतों में वृद्धि के कारण विनिर्मित उत्पादों की वर्ष-दर-वर्ष आधारित मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले के 1.9 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 31 मार्च 2007 को 5.8 प्रतिशत हो गई। धातुओं की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों की प्रवृत्ति के अनुरूप बनी रहीं। 'मूल धातु, मिश्र धातु तथा उत्पाद' समूह की वर्ष-दर-वर्ष आधारित मुद्रास्फीति की दर 31 मार्च 2007 को 11.0 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पूर्व इसमें 0.6 प्रतिशत की कमी आई थी। सीमेंट की घरेलू कीमतें, अंशतः घरेलू मांग में मजबूती को प्रतिबिंबित करते हुए, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पिछले वर्ष के 14.9 प्रतिशत की वृद्धि के स्तर से और 11.6 प्रतिशत बढ़ गई। इलेक्ट्रिकल मशीनरी की कीमतों में पिछले वर्ष के 4.1 प्रतिशत की तुलना में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गेहू की घरेलू कीमतों में वृद्धि के अनुरूप अनाज मिल उत्पादों की कीमतों में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि चीनी की कीमतों में विश्व स्तर पर कमी आने के चलते उसकी घरेलू कीमतों में हाल के महीनों में नरमी आई। खाद्य तेल की कीमतों में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसमें 3.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

2.82 प्राथमिक वस्तुओं तथा विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों की रोकथाम के लिए रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की प्रत्याशा को रोकने के लिए मौद्रिक

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.33 : भारत में थोक मूल्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत)

पण्य	1अप्रैल 2006			31मार्च 2007 अ	
	भार	मुद्रास्फीति	भा.अं.	मुद्रास्फीति	भा.अं.
1	2	3	4	5	6
सभी पण्य	100.0	4.0	100.0	5.7	100.0
1. प्राथमिक वस्तुएँ	22.0	4.8	25.8	10.7	40.4
खाद्यान्न वस्तुएँ	15.4	5.9	22.5	8.3	22.3
i. चावल	2.4	2.1	1.1	5.7	2.1
ii. गेहूँ	1.4	12.7	4.3	7.6	1.9
iii. दालें	0.6	33.3	4.5	12.0	1.4
iv. सब्जियाँ	1.5	7.6	2.4	1.4	0.3
v. फल	1.5	-3.9	-1.9	5.5	1.7
vi. दूध	4.4	1.9	2.0	8.4	6.0
vii. अंडे, मांस, मछली	2.2	13.2	7.3	11.1	4.6
खाद्येतर (वस्तुएँ)	6.1	-2.4	-3.5	16.6	15.5
i. कपास	1.4	-1.7	-0.4	21.4	3.6
ii. तिलहन	2.7	-9.2	-5.5	30.6	11.0
iii. गन्ना	1.3	0.7	0.3	1.1	0.3
खनिज	0.5	43.6	6.9	17.0	2.6
2. ईंधन, ऊर्जा, बिजली और लुब्रिकेट्स	14.2	8.3	45.5	1.0	4.1
i. खनिज तेल	7.0	12.0	37.2	0.5	1.2
ii. विद्युत	5.5	4.5	8.3	2.3	2.9
iii. कोयला खनन	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
3. निर्मित उत्पाद	63.8	1.9	27.7	5.8	55.9
i. खाद्य पदार्थ	11.5	1.0	2.6	6.4	11.3
जिसमें से: चीनी	3.6	6.2	4.7	-12.7	-6.9
खाद्य तेल	2.8	-3.3	-1.8	14.7	5.1
ii. सूती वस्त्र	4.2	2.3	2.1	-1.0	-0.6
iii. मनुष्य निर्मित रेशे	4.4	-3.9	-2.1	3.7	1.3
iv. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	11.9	3.3	9.7	2.9	5.8
जिसमें से: खाद	3.7	0.2	0.1	1.8	1.0
v. मूल धातु, मिश्र धातु तथा धातु उत्पाद	8.3	-0.6	-1.5	11.0	17.6
जिसमें से: लोहा और इस्पात	3.6	-4.2	-5.1	7.5	5.8
vi. गैर धातु खनिज उत्पाद	2.5	9.6	5.4	9.0	3.7
जिसमें से: सीमेंट	1.7	14.9	5.6	11.6	3.3
vii. मशीनरी तथा मशीन औजार	8.4	3.2	5.2	8.0	8.8
जिसमें से: बिजली की मशीनरी	5.0	4.1	3.1	12.8	6.9
viii. परिवहन उपकरण और कल पुर्जे	4.3	0.9	0.8	2.1	1.2
ज्ञापन:					
खाद्य वस्तुएँ (मिश्रित)	26.9	3.9	25.1	7.5	33.6
थो.मू.सू. खाद्य वस्तुओं को छोड़कर	73.1	4.0	74.9	5.1	66.4
थो.मू.सू. ईंधन को छोड़कर	85.8	2.8	54.5	7.1	95.9

अ : अंतिम भा.अं. : भारत अंश

उपाय किए। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान सरकार ने भी इस दिशा में राजकोषीय और आपूर्ति पक्ष संबंधी कतिपय उपाय किए।

2.83 हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5 मई 2007 को 5.4 प्रतिशत थी जबकि मार्च 2007 के अंत में यह

5.7 प्रतिशत और उससे एक वर्ष पूर्व 4.4 प्रतिशत थी। प्राथमिक वस्तुओं और विनिर्मित वस्तु समूह की मुद्रास्फीति बढ़कर क्रमशः 11.1 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 5.1 प्रतिशत) और 5.1 प्रतिशत (2.3 प्रतिशत) हो गई जबकि इंधन समूह की मुद्रास्फीति घटकर 0.7 प्रतिशत (9.0 प्रतिशत)

सारणी 2.34 : भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) (वर्ष-दर-वर्ष)

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति माप	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005	मार्च 2006	जून 2006	सितं. 2006	दिसं.2006	मार्च 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सीपीआई-आइ डब्ल्यू	4.1	3.5	4.2	4.9	7.7	6.8	6.9	6.7
सीपीआई-यूएनएमई	3.8	3.4	4.0	5.0	6.5	6.6	6.9	7.6
सीपीआई-एएल	4.9	2.5	2.4	5.3	7.2	7.3	8.9	9.5
सीपीआई-आरएल	4.8	2.5	2.4	5.3	7.2	7.0	8.3	9.2
ज्ञापन:								
डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति	6.5	4.6	5.1	4.1	4.8	5.4	5.9	5.7
आइडब्ल्यू : औद्योगिक कामगार।	यूएनएमई : शहरी गैर मैन्युअल कर्मचारी।		एएल : कृषि श्रमिक।		आरएल : ग्रामीण श्रमिक।			

रह गई। औसत थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5 मई 2007 को 5.6 प्रतिशत हो गई जबकि एक वर्ष पूर्व यह दर 4.2 प्रतिशत के स्तर पर थी।

2.84 वर्ष 2006-07 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई और यह थोक मूल्य सूचकांक से अधिक के स्तर पर बनी रही। इसका कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की दर अधिक होना और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के लिए उच्चतर भार निर्धारित किया जाना है (सारणी 2.34)।

2.85 संक्षेप में, वर्ष 2006-07 के दौरान बैंक ऋण की मांग काफी अधिक रही। इस मांग की पूर्ति बैंक जमाराशियों में वृद्धि करके की गई। साथ ही, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि भी एक वर्ष पूर्व के स्तर से अधिक रही; यह वृद्धि वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषित दर से अधिक है। वर्ष 2006-07 के दौरान प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के चलते मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई और यह वृद्धि आपूर्ति तथा मांग के दबावों के पारस्परिक प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। तेल की घरेलू कीमतों में वृद्धि का असर (पास-थू) एलपीजी तथा मिट्टी के तेल की कीमतों पर नहीं पड़ा। वर्ष 2006-07 के दौरान उपभोक्ता वस्तु मूल्य मुद्रास्फीति की माप संबंधी आंकड़े थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के आंकड़ों से उच्चतर थे जो प्राथमिक खाद्य वस्तु मूल्यों में तेज वृद्धि को दर्शाते हैं।

IV. वित्तीय बाजार

2.86 वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय बाजार, उतार-चढ़ाव की कुछेक स्थितियों को छोड़कर, सुव्यवस्थित बना रहा। अल्पकालीन मुद्रा दरें, दिसंबर 2006 के मध्य तक रिवर्स रेपो और रेपो दर के दायरे में रहीं। तथापि, दिसंबर 2006 के दूसरे पखवाड़े से सरकार की नकद शेष राशि में भारी परिवर्तन और विदेशी मुद्रा के प्रवाह में भारी उतार-चढ़ाव तथा मौद्रिक नीति में कड़ाई के दौर में कतिपय सहभागियों के पास समपाश्वर्क की कमी के चलते चलनिधि में घट-बढ़ के कारण मांग दरों में बीच-बीच

में वृद्धि होती रही। वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में यूएस डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में उतार-चढ़ाव देखा गया, साथ ही मार्च 2007 के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिफल में कमी आई। वित्तीय वर्ष के दौरान ईक्विटी बाजार, मई-जून 2006 और फरवरी-मार्च 2007 के दौरान के उतार-चढ़ाव को छोड़कर, सुव्यवस्थित रहा। इस खंड में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 (जहां तक आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान वित्तीय बाजार के विभिन्न खंडों की समीक्षा तथा मूल्यांकन किया गया है।

मांग मुद्रा बाजार

2.87 वर्ष 2006-07 के दौरान, उतार-चढ़ाव वाली कुछेक अवधियों को छोड़कर, मुद्रा बाजार की स्थिति काफी अच्छी थी। वर्ष 2005-06 के उत्तरार्ध में मांग मुद्रा दरों में जो बढ़ोतरी हुई थी वह अप्रैल-मई 2006 के दौरान घट गई तथा यह रिवर्स रेपो दर (चलनिधि समायोजन सुविधा के दायरे का निचला स्तर) के आसपास रही जो चलनिधि की अच्छी उपलब्धता को दर्शाता है। 9 जून 2006 से नियत रिवर्स रेपो/रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के चलते मांग दरों में भी तदनु रूप वृद्धि हुई। नियत रिवर्स रेपो/ रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि (25 जुलाई 2006 से) के चलते जुलाई 2006 में मांग दरों में फिर से बढ़ोतरी हुई। अन्य बातों के साथ-साथ कर के अग्रिम भुगतान और ऋण की अधिक मांग के साथ त्योहारों के मौसम में मुद्रा की मांग में वृद्धि के चलते चलनिधि में कमी आने के कारण जब मांग मुद्रा दर बढ़कर 6.33 प्रतिशत हो गई तो सितंबर 2006 में तुलनामूलक रूप में चलनिधि में कमी आ गई। अक्टूबर 2006 में औसत मासिक मांग मुद्रा दर में वृद्धि हुई तथा यह 6.75 तक पहुंच गई। 31 अक्टूबर 2006 से नियत रेपो दर में 25 आधार अंक वृद्धि करके उसे 7.25 प्रतिशत किये जाने पर मांग दर में मामूली वृद्धि हुई और नवंबर 2006 के पहले तीन सप्ताह के दौरान औसत मांग दर 6.90 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। तथापि नवंबर के अंत के आसपास मांग दरों में कमी आने के कारण मासिक औसत मांग दर घटकर

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.35 : घरेलू वित्तीय बाज़ार-चयनित संकेतक

वर्ष/ महीना	माँग मुद्रा		सरकारी प्रतिभूतियाँ		विदेशी मुद्रा			चलनिधि प्रबंध		ईक्विटी				
	औसत दैनिक कारोबार (करोड़ रुपए)	औसत माँग दरें * (प्रति शत)	औसत 10-वर्षीय आय @ (प्रति शत)	स.प्रति. में औसत दैनिक कारोबार (करोड़ रुपए) +	औसत दैनिक अंतर बैंक कारोबार (अमरीकी\$ मिलियन)	औसत विनिमय दर (रुपए प्रति अमरीकी \$)	रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा बिज़नेस (-)/ खरीद (+) (अमरीकी \$ मिलियन)	औसत वायदा प्रिमियम 3- माह (प्रति शत)	औसत एमएसएस बकाया रिवर्स रेपो (एलएएफ) रुपए)	औसत दैनिक बोएसई एनएसई सेसेक्स** (करोड़ रुपए)	औसत दैनिक बोएसई एनएसई सेसेक्स** (करोड़ रुपए)	औसत बोएसई सेसेक्स** (करोड़ रुपए)	औसत एसएंडपी सीएनएक्स निपटी **	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2005-06														
अप्रैल	17,213	4.77	7.02	3,001	9,880	43.74	-	1.96	65,638	30,675	1,890	4,136	6,379	1,987
मई	15,269	4.99	7.11	3,805	10,083	43.49	-	1.57	68,539	22,754	1,971	3,946	6,483	2,002
जून	20,134	5.10	6.88	6,807	10,871	43.58	-104	1.40	70,651	13,916	2,543	4,843	6,926	2,134
जुलाई	20,046	5.02	7.13	3,698	11,003	43.54	2,473	1.56	70,758	10,754	3,095	6,150	7,337	2,237
अगस्त	16,158	5.02	7.04	4,239	11,749	43.62	1,552	0.69	71,346	34,832	3,451	6,624	7,726	2,358
सितंबर	16,292	5.05	7.04	5,207	11,040	43.92	-	0.62	67,617	30,815	3,871	6,923	8,272	2,512
अक्टूबर	17,164	5.12	7.14	2,815	13,087	44.82	-	0.69	68,602	18,608	2,955	6,040	8,220	2,487
नवंबर	22,620	5.79	7.10	3,314	11,228	45.73	-	0.67	67,041	3,268	2,635	5,480	8,552	2,575
दिसंबर	21,149	6.00	7.13	2,948	13,808	45.64	-6,541	1.51	52,040	1,452	3,516	6,814	9,162	2,773
जनवरी	17,911	6.83	7.15	3,094	16,713	44.40	-	2.60	40,219	-15,386	3,966	7,472	9,540	2,893
फरवरी	13,497	6.95	7.32	2,584	15,798	44.33	2,614	2.85	33,405	-13,532	3,688	7,125	10,090	3,019
मार्च	18,290	6.58	7.40	2,203	17,600	44.48	8,149	3.11	29,652	-6,319	5,398	9,518	10,857	3,236
2006-07														
अप्रैल	16,909	5.62	7.45	3,685	17,712	44.95	4,305	1.31	25,709	46,088	4,860	9,854	11,742	3,494
मई	18,074	5.54	7.58	3,550	18,420	45.41	504	0.87	26,457	59,505	4,355	9,155	11,599	3,437
जून	17,425	5.73	7.86	2,258	15,310	46.06	-	0.73	31,845	48,610	3,261	6,828	9,935	2,915
जुलाई	18,254	5.86	8.26	2,243	14,325	46.46	-	0.83	36,936	48,027	2,605	5,652	10,557	3,092
अगस्त	21,294	6.06	8.09	5,786	15,934	46.54	-	1.22	40,305	36,326	2,869	5,945	11,305	3,306
सितंबर	23,665	6.33	7.76	8,306	18,107	46.12	-	1.31	40,018	25,862	3,411	6,873	12,036	3,492
अक्टूबर	26,429	6.75	7.65	4,313	16,924	45.47	-	1.67	41,537	12,983	3,481	6,919	12,637	3,649
नवंबर	25,649	6.69	7.52	10,654	20,475	44.85	3,198	2.07	38,099	9,937	4,629	8,630	13,416	3,869
दिसंबर	24,168	8.63	7.55	5,362	19,932	44.64	1,818	3.20	38,148	-1,713	4,276	8,505	13,647	3,918
जनवरी	22,360	8.18	7.71	4,822	21,065 P	44.33	2,830	4.22	39,553	-10,738	4,380	8,757	13,984	4,037
फरवरी	23,254	7.16	7.90	4,386	20,050 P	44.16	11,862	3.71	40,827	648	4,680	9,483	14,143	4,079
मार्च	23,217	14.07	8.00	2,991	24,231 P	44.03	-	4.51	52,944	-11,858	3,716	7,998	12,850	3,731

* : दैनिक भारित माँग मुद्रा उधार दरों का औसत ।

: बाजार स्थिरीकरण योजना के साप्ताहिक बकाया का औसत ।

@ : दैनिक लेखाबंदी दरों का औसत ।

** : दैनिक लेखाबंदी सूचकांक का औसत ।

+ : केंद्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का एकमुश्त कारोबार ।

- : कुछ नहीं ।

अ : अनंतिम ।

6.69 प्रतिशत रह गई। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से मांग दरों में वृद्धि प्रारंभ हुई और 29 दिसंबर 2006 को यह 16.9 प्रतिशत तक पहुंच गई तथा माह के दौरान औसत दर 8.63 प्रतिशत रही। मांग दरों में वृद्धि का कारण, सीआरआर में बढ़ोतरी और कर के अग्रिम भुगतान के कारण चलनिधि की मात्रा में कमी आना है (सारणी 2.35)। तथापि जनवरी 2007 में मांग दरों में कमी आई और औसत मांग दर 8.18 प्रतिशत रही। फरवरी 2007 में मांग दर में और कमी आई और दूसरे सप्ताह के अंत तक यह 6.5 प्रतिशत रह गई। 13 फरवरी 2007 को सीआरआर में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद फरवरी के मध्य तक मांग दर बढ़कर लगभग 8.0 प्रतिशत हो गई और फरवरी के अंत तक यह घटकर 6.0 प्रतिशत तक आ गई। फरवरी 2007 के दौरान मांग दर औसतन 7.16 प्रतिशत रही।

2.88 मार्च के प्रथम सप्ताह के दौरान मांग मुद्रा दरें रेपो/रिवर्स रेपो दर के दायरे की निचली सीमा से भी नीचे तक आ गई तथा मार्च के मध्य तक मांग मुद्रा की औसत दर 5.62 प्रतिशत थी। 17 से 31 मार्च 2007 के दौरान

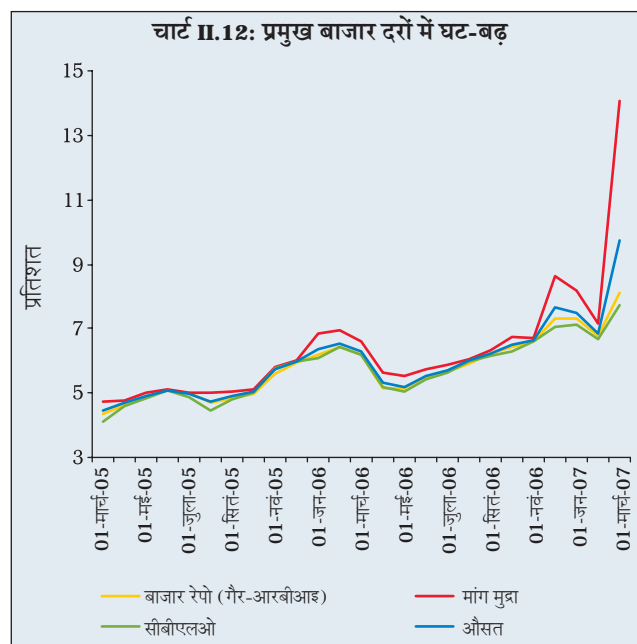
रात्रिपर्यंत मांग दर दायरे की ऊपरी सीमा से अधिक के स्तर के आसपास बनी रही और अगले पांच दिनों तक यह 20 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर थी। 21 मार्च तथा 30 मार्च 2007 को मांग दर 50 प्रतिशत से ऊपर तक पहुंच गई। माह के दौरान औसत मांग दर 14.07 प्रतिशत बनी रही। सरकार की नकदी शेष राशि में तेजी से गिरावट आने से चलनिधि की स्थिति में सुधार होने के कारण मांग मुद्रा दर में कमी आई तथा अप्रैल 2007 के पूर्वार्ध में दैनिक भारित औसत आधार पर यह दर 3.27 से 12.83 प्रतिशत के बीच रही। मौद्रिक उपाय के रूप में 30 मार्च 2007 को आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) अनुपात में बढ़ोतरी का प्रथम चरण 14 अप्रैल 2007 से लागू हो जाने और बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा संसाधन जुटाने के चलते अप्रैल के उत्तरार्ध में मांग दर बढ़कर 7.36 प्रतिशत से 15.01 प्रतिशत के बीच रही तथा इस दौरान की औसत मांग दर 9.76 प्रतिशत थी। अप्रैल 2007 में औसत मांग दर 8.33 प्रतिशत थी। मई 2007 (19 मई 2007 तक) के दौरान दैनिक भारित औसत मांग मुद्रा दरें 2.80 से

हाल की आर्थिक गतिविधियां

9.08 प्रतिशत के बीच रहीं और इसकी औसत दर 7.24 प्रतिशत अर्थात् चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रेपो दर से कम थी। हाल की अवधि में मुद्रा बाजार में बढ़ते उतार-चढ़ाव का आंशिक कारण बैंकों के बीच निधियों तथा पात्र समर्थक प्रतिभूति का असमान वितरण होना है। इस उतार-चढ़ाव को कुछ बैंकों में अस्ति देयता में हुए असंतुलन से भी बल मिला क्योंकि उनके पास समर्थक प्रतिभूतियां बहुत कम थीं तथा परिपक्वता अवधि के आसपास उनके पास प्रावधान की राशि पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। इसके कारण संपाश्वर्कृत बाजार से उधार लेने अथवा रिजर्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा का लाभ उठाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाने से उन्हें असंपाश्वर्कृत बाजार से अधिक दरों पर निधि जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एलएएफ के माध्यम से चलनिधि के लिए जो भी मांग होती रही, रिजर्व बैंक ने उसे पूरा किया। इस प्रकार, कर के अग्रिम भुगतान के कारण मार्च 2007 के उत्तरार्ध से चलनिधि में जो कमी आई वह अप्रैल/मई तक बनी रही तथा इसके कारण मांग दरों में बढ़ोतरी हुई।

संपाश्वर्कृत बाजार

2.89 अगस्त 2005 से बैंक से इतर सहभागियों (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) को गैर-संपाश्वर्कृत मुद्रा बाजार में भाग लेने के लिए रोक लगाए जाने के बाद संपाश्वर्कृत खंड मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण खंड के रूप में उभर कर सामने आया है। वर्ष 2006-07 के पहले दो महीनों में मुद्रा बाजार के संपाश्वर्कृत खंड - मार्केट रेपो (एलएएफ से बाहर) तथा संपाश्वर्कृत उधार और ऋणदायी बाध्यता खंड - की ब्याज दरों में वर्ष 2005-06 की अंतिम तिमाही के मुकाबले कमी आई है। तथापि, नियत रिवर्स रेपो दर में वृद्धि तथा उसके बाद सितंबर 2006 में चलनिधि की मात्रा में आई कमी के कारण जून 2006 से संपाश्वर्कृत मुद्रा बाजार में दरों का क्रमशः बढ़ना शुरू हुआ। मार्केट रेपो और सीबीएलओ दरें जो अप्रैल 2006 के दौरान घटकर क्रमशः 5.15 और 5.18 तक आ गई थी, दिसंबर 2006 में बढ़कर क्रमशः 7.33 और 7.05 प्रतिशत हो गईं। फरवरी 2007 के दौरान बाजार रेपो तथा सीबीएलओ खंड की दरें घटकर क्रमशः 6.76 प्रतिशत तथा 6.67 प्रतिशत हो गईं तथा मार्च 2007 में ये मांग मुद्रा बाजार दरों की तर्ज पर बढ़कर क्रमशः 8.13 तथा 7.73 प्रतिशत हो गईं। भारत औसत आधार पर सीबीएलओ दर तथा बाजार रेपो दर औसत रूप में फरवरी 2007 में 6.70 प्रतिशत तथा मार्च 2007 में 7.86 प्रतिशत थी। तथापि, वर्ष 2006-07 में इन खंडों में ब्याज दरें मांग दर से कम रहीं (चार्ट II.12)। दिसंबर 2006 के मध्य तक सीबीएलओ तथा बाजार रेपो खंड में ब्याज दरें रेपो-रिवर्स रेपो दर के दायरे में बनी रहीं। मुद्रा बाजार में चलनिधि की कमी के अनुरूप इन खंडों की ब्याज दरें भी बढ़ गईं तथा दिसंबर 2006 के उत्तरार्ध से ये दरें रेपो रेट के आसपास बनी रहीं, परंतु ये दरें मांग दरों से कम थीं। चलनिधि में कमी वाली परवर्ती अवधियों में भी संपाश्वर्कृत खंड में ब्याज दरें कमोबेश रेपो रेट



के आसपास बनी रहीं; केवल मार्च के अंत के आसपास ये दरें एलएएफ रेपो दर से काफी अधिक थीं, फिर भी ये दरें मांग दरों से नीचे थीं।

2.90 वर्ष 2006-07 के दौरान सीबीएलओ तथा बाजार रेपो दर का औसत 6.24 प्रतिशत तथा 6.34 प्रतिशत था जबकि मांग मुद्रा बाजार दर 7.22 प्रतिशत थी। सीबीएलओ और बाजार रेपो दरें दायरे के अंदर रहीं तथा अप्रैल 2007 में इनकी औसत दर क्रमशः 6.12 प्रतिशत और 6.76 प्रतिशत थी। मई 2007 के पूर्वार्ध में सीबीएलओ और बाजार रेपो दरें घटकर रिवर्स रेपो दर से नीचे आ गईं तथा तीसरे सप्ताह में ये दरें रेपो रेट के आसपास बनी रहीं। अप्रैल तथा मई 2007 (19 मई 2007 तक) के दौरान मुद्रा बाजार के संपाश्वर्कृत खंडों की दरें प्रायः एलएएफ रेपो दर के दायरे के अंदर अथवा उसके आसपास बनी रहीं।

2.91 वर्ष 2006-07 के दौरान कुल मात्रा में 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ संपाश्वर्कृत बाजार अब मुद्रा बाजार का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। म्यूच्युअल फंड तथा वित्तीय संस्थाएं सीबीएलओ बाजार के प्रमुख ऋणदाता हैं जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक प्रमुख उधारकर्ता। बाजार रेपो खंड में म्यूच्युअल फंड प्रमुख निधि प्रदाता हैं जबकि विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक तथा प्राथमिक व्यापारी प्रमुख उधारकर्ता हैं।

2.92 वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार 18 सितंबर 2006 को मांग/नोटिस तथा मियादी मुद्रा बाजार के सभी लेनदेनों के लिए स्क्रीन आधारित तयशुदा भाव बोली द्वारा निर्धारित एक प्रणाली प्रारंभ की गई है। एनडीएस-कॉल का विकास भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) द्वारा किया गया है और यह आशा की जाती है कि इससे पारदर्शिता बढ़ाने और

बेहतर मूल्य की खोज करने में सहायता मिलेगी। यद्यपि इस प्लेटफॉर्म के जरिए कारोबार करना वैकल्पिक है, तथापि अब तक 84 बैंकों (16 सहकारी बैंकों सहित) तथा 7 प्राथमिक व्यापारियों ने एनडीएस-कॉल की सदस्यता ले रखी है।

चलनिधि की स्थिति

2.93 बैंक ऋण में निरंतर बढ़ोतरी के बावजूद वर्ष 2006-07 में चलनिधि की स्थिति सामान्यतः अच्छी रही। रिजर्व बैंक स्थित केंद्र सरकार के खाते में अतिरिक्त शेष राशि में कमी आने तथा रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन के असर के चलते अप्रैल-जून 2006 के दौरान चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ। रिजर्व बैंक ने एलएएफ के अंतर्गत परिचालनों के जरिए चलनिधि का अवशोषण किया तथा मई 2006 में एमएसएस के अंतर्गत खजाना बिलों की नीलामी प्रारंभ की। एलएएफ के अंतर्गत अप्रैल-जून 2006 के दौरान रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो के जरिए औसतन 51,490 करोड़ रुपए की चलनिधि का अवशोषण किया जबकि पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च 2006) के दौरान रिपो के जरिए 11,686 करोड़ रुपए की चलनिधि का अंतःक्षेपण (इंजेक्शन) किया गया था। रिवर्स रेपो के जरिए औसत निवल अवशोषण की राशि जुलाई 2006 के 48,000 करोड़ रुपए के मुकाबले अक्टूबर 2006 में घटकर 12,983 करोड़ रुपए हो गई। नवंबर में रिवर्स रेपो के जरिए औसत निवल अवशोषण की राशि 9,937 करोड़ रुपए थी। तथापि, कर के अग्रिम भुगतान के कारण चलनिधि में कमी आने तथा ऋण की मात्रा में उच्चतर वृद्धि के साथ-साथ मुद्रास्फीति में भी बढ़ोतरी होने के कारण सीआरआर में वृद्धि किए जाने से दिसंबर 2006 तथा जनवरी 2007 में औसत क्रमशः 1,713 करोड़ रुपए तथा 10,738 करोड़ रुपए की निवल चलनिधि का अंतःक्षेपण किया गया। 3 मई 2006 से एमएसएस के अंतर्गत निर्गमों का फिर से प्रारंभ किए जाने के बाद उसके जरिए चलनिधि का अवशोषण किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में एमएसएस के अंतर्गत 33,912 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का अवशोषण किया गया था। फरवरी 2007 के दूसरे सप्ताह में एलएएफ के जरिए अवशोषण प्रारंभ किया गया तथा चलनिधि की स्थिति तथा मुद्रास्फीति की अपेक्षा को रोकने की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 13 फरवरी 2007 को सीआरआर में और बढ़ोतरी करने की घोषणा की।

2.94 फरवरी 2007 में रिवर्स रेपो के जरिए औसत दैनिक अवशोषण की राशि 648 करोड़ रुपए थी। चलनिधि की स्थिति की समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक ने 2 मार्च 2007 को चलनिधि के प्रबंधन के लिए संशोधित व्यवस्था प्रारंभ की जिसमें अति अल्पावधि के असंतुलों के संतुलक के रूप में एलएएफ सुविधा के महत्व पर बल देते हुए यह निर्णय लिया गया कि दैनिक रिवर्स रेपो नीलामियों के जरिए चलनिधि के अवशोषण को संयोजित किया जाएगा। तदनुसार 5 मार्च 2007 से दैनिक रिवर्स रेपो

अवशोषण को प्रति दिन (आबंटन यथानुपात आधार पर आनुपातिक होगा) अधिकतम 3000 करोड़ रुपए तक सीमित रखा गया जिसमें 2,000 करोड़ रुपए पहले एलएएफ के लिए और 1,000 करोड़ रुपए दूसरे एलएएफ के लिए होगा। 5 मार्च से 15 मार्च 2007 के दौरान चलनिधि की मात्रा अधिक होने के कारण दैनिक अवशोषण की राशि 3,000 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के आस-पास थी। परंतु, 16 मार्च 2007 से मुख्यतः प्रत्यक्ष कर के भुगतान की तिमाही अनुसूची के चलते प्रणाली में चलनिधि की मात्रा कम हो गई। मार्च के उत्तरार्ध के दौरान चलनिधि के अंतःक्षेपण की निवल दैनिक औसत राशि 31,124 करोड़ रुपए थी तथा पूरे माह के लिए ऐसी औसत राशि 11,858 करोड़ रुपए थी।

2.95 अप्रैल 2007 में सीआरआर में दो चरणों में वृद्धि लागू हो जाने से प्रणाली में चलनिधि की मात्रा में कमी आई जिसके चलते एलएएफ के जरिए चलनिधि का अंतःक्षेपण बढ़ गया। एलएएफ के जरिए चलनिधि का औसत दैनिक निवल अंतःक्षेपण 8,937 करोड़ रुपए था। माह के दौरान केवल सात दिन अर्थात् 9 से 15 अप्रैल 2007 के बीच, चलनिधि का अवशोषण किया गया। मई 2007 (19 मई 2007 तक) के दौरान, 7 से 13 मई 2007 के दौरान को छोड़कर, रिजर्व बैंक ने चलनिधि का अंतःक्षेपण किया।

2.96 हाल के वर्षों में चलनिधि प्रबंधन के प्रमुख मुद्दों में अप्रत्याशित रूप में बड़ी मात्रा में पूंजी का आगम होना शामिल है। इसके चलते बाहरी कारकों से चलनिधि में वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा की आपूर्ति, कीमतों तथा विनिमय दरों में बढ़ोतरी होती है। इसके कारण उपयुक्त निष्प्रभावीकरण उपायों की आवश्यकता हुई। तिमाही भुगतान अनुसूची के कारण प्रत्यक्ष कर का भुगतान एक साथ किए जाने से रिजर्व बैंक स्थित सरकार की नकदी शेष राशि में काफी बड़ी मात्रा में आवधिक घटबढ़ होता है जिसका असर कर राजस्व में भारी वृद्धि के रूप में हाल की तिमाहियों में देखा गया। सरकार की नकदी शेष राशि में अत्यधिक घटबढ़ होने से मौद्रिक आधार में अप्रत्याशित संकुचन अथवा विस्तार होता है और इसके परिणामस्वरूप मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन और कठिन हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों से एलएएफ चलनिधि प्रबंधन तथा मौद्रिक नीति दोनों के लिए प्रमुख परिचालनगत लिखत के रूप में उभरा है। दूसरी ओर, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) ने चलनिधि के अल्पावधि प्रबंधन में एलएएफ की भूमिका पर असर डाले बिना, पूंजी के निरंतर अंतर्वाह से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक लिखत के रूप में कार्य किया है। इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि एलएएफ तथा एमएसएस के लिए मार्च 2007 में स्थापित संशोधित व्यवस्था से प्रणाली में आवश्यक चलनिधि को बनाए रखने में सुविधा होगी, साथ ही मौद्रिक नीति के रुख तथा उद्देश्य के अनुसार चलनिधि से उत्पन्न स्थिति से शीघ्रता से निपटने में सुविधा होगी।

जमा प्रमाणपत्र

2.97 राजकोषीय वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों की मांग काफी अधिक रही। ऋण की निरंतर मांग को देखते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने जमा प्रमाणपत्रों के जरिए जमाराशि जुटाना प्रारंभ कर दिया। जमा प्रमाणपत्रों की बकाया राशि मार्च 2006 के अंत के 43,568 करोड़ रुपए (जारीकर्ता बैंक की सकल जमाराशि का 4.8 प्रतिशत) की तुलना में 30 मार्च 2007 में बढ़कर 93,272 करोड़ रुपए (अंतर-समूह में महत्वपूर्ण परिवर्तन सहित जारीकर्ता बैंकों की सकल जमाराशि का 4.83 प्रतिशत) हो गई। जमा प्रमाणपत्रों का समग्र भारत औसत बढ़ा दर (डब्ल्यूएडीआर), जो मार्च 2006 के अंत में बढ़कर 8.62 प्रतिशत हो गयी थी, अप्रैल 2006 के अंत में घटकर 7.03 प्रतिशत हो गई। डब्ल्यूएडीआर बढ़कर 30 मार्च 2007 को 10.75 प्रतिशत हो जाने के चलते जमा प्रमाणपत्रों की ब्याज दरों में जुलाई से पुनः वृद्धि हुई। 13 अप्रैल 2007 को जमा प्रमाणपत्रों की डब्ल्यूएडीआर 10.15 प्रतिशत थी। संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक भी जमा प्रमाणपत्रों के जरिए अधिक मात्रा में संसाधन जुटा रहे हैं। संस्थागत निवेशक, जैसे म्यूच्युअल फंड आदि अपने-अपने अल्पावधि संसाधनों के निवेश हेतु इन प्रमाणपत्रों में निवेश कर रहे हैं।

वाणिज्य पत्र

2.98 जारी किए गए वाणिज्य पत्रों (सीपी) की कुल बकाया राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2006 के 12,718 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 31 मार्च 2007 को 17,688 करोड़ रुपए हो गई। भारत औसत बढ़ा दर जो मार्च 2006 के अंत में 8.59 प्रतिशत तक बढ़ गई थी, मई 2006 के मध्य तक उसमें कमी आई। मुद्रा बाजार दरों में वृद्धि के अनुरूप वाणिज्य पत्रों की ब्याज दरों में भी अगस्त के मध्य के बाद थोड़ी-सी वृद्धि हुई। कंपनियां, मुद्रा बाजार के अन्य खंडों द्वारा दिए जा

रहे प्रतिलाभ के अनुरूप, तीन माह से अधिक अवधि की परिपक्वता वाले वाणिज्य पत्रों के लिए 10.25 प्रतिशत से 12.50 प्रतिशत तक का प्रतिलाभ दे रही हैं। वाणिज्य पत्र जारी करने वाली कंपनियों में मुख्य रूप से पट्टादायी और वित्त कंपनियां थीं। वर्ष 2006-07 के दौरान जारी किए गए वाणिज्य पत्रों में वित्तीय संस्थाओं का हिस्सा बढ़ा है। (सारणी 2.36)। 15 अप्रैल 2007 को वाणिज्य पत्रों की भारत औसत बढ़ा दर 10.5 प्रतिशत थी।

सरकारी प्रतिभूति बाजार

केंद्र सरकार की नकदी का प्रबंधन

2.99 राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की अपेक्षानुसार नयी व्यवस्था में सुगमता से संक्रमण की दृष्टि से, भारत सरकार से परामर्श करके वर्ष 2006-07 की अर्थोपाय अग्रिम व्यवस्था में संशोधन किया गया। संशोधित व्यवस्था के अनुसार अर्थोपाय अग्रिम की सीमा वर्तमान के छमाही आधार के बजाए तिमाही आधार पर निर्धारित की गई है। तदनुसार, वर्ष 2006-07 की पहली और दूसरी छमाही के लिए क्रमशः 20,000 करोड़ रुपए तथा 10,000 करोड़ रुपए की सीमा तथा तीसरी और चौथी तिमाही प्रत्येक के लिए 6,000 करोड़ रुपए की सीमा निर्धारित की गई। संक्रमणकालीन मुद्दों तथा तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार से परामर्श करके, रिजर्व बैंक द्वारा इन सीमाओं में संशोधन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, रेपो दर के अल्पावधि संदर्भ दर के रूप में उभरने के कारण अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट की ब्याज दर को रेपो दर के साथ संबद्ध किया गया है। तदनुसार अर्थोपाय अग्रिम की ब्याज दर रेपो दर पर निर्धारित की गई है जबकि ओवरड्राफ्ट की ब्याज दर को रेपो दर से दो प्रतिशत अंक अधिक निर्धारित किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान केंद्र सरकार ने कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया, लेकिन पांच अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम लिया (कुल 39 दिन), जो नकदी की अच्छी स्थिति को दर्शाता है।

केंद्र सरकार का बाजार उधार 2006-07

2.100 राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में अभिदान करने पर रिजर्व बैंक को रोक है। नई व्यवस्था में सहज संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ने संस्थागत तथा व्यापार/समाशोधन संबंधी मूलभूत सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ बाजार को गहन एवं व्यापक बनाने तथा चलनिधि की उपलब्धता में वृद्धि के लिए कई उपाय किए।

2.101 वर्ष 2006-07 के लिए केंद्र सरकार के बाजार उधार (दिनांकित प्रतिभूतियों तथा 364 दिन की राजकोषीय बिल सहित) में 1,81,875 करोड़ रुपए (निवल 1,13,778 करोड़ रुपए) की राशि का बजट किया गया था जो वर्ष 2005-06 में उगाही गई राशि वास्तविक राशि से 21,857

सारणी 2.36: वाणिज्य पत्र - प्रमुख जारीकर्ता

(राशि करोड़ रुपए में)

जारीकर्ता की श्रेणी	के अंत में		
	मार्च-05	मार्च-06	मार्च-07
1	2	3	4
पट्टादायी और वित्त	8,479 (59.6)	9,400 (73.9)	12,419 (70.2)
विनिर्माण	2,881 (20.2)	1,982 (15.6)	2,754 (15.6)
वित्तीय संस्थाएं	2,875 (20.2)	1,336 (10.5)	2,515 (14.2)
जोड़	14,235 (100)	12,718 (100)	17,688 (100)

नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

करोड़ रुपए अधिक है। 24 मार्च 2006 को केंद्र सरकार से परामर्श करके वर्ष 2006-07 के पूर्वार्ध के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम कैलेंडर की राशि 89,000 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए 81,000 करोड़ रुपए उगाहे गए थे) निर्धारित की गई। वर्ष के दौरान उगाही गई वास्तविक राशि 89,000 करोड़ रुपए थी जो निर्गम कैलेंडर के अनुरूप थी। राजकोषीय वर्ष के उत्तरार्ध के लिए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम कैलेंडर 25 सितंबर 2006 को जारी किया गया। उगाही जाने वाली कुल राशि 63,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी जिसमें से 57,000 करोड़ रुपए की राशि उगाही गई।

दिनांकित प्रतिभूतियां

2.102 वर्ष 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए केंद्र सरकार के सकल बाजार उधार की राशि 1,46,000 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1,31,000 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2006-07 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधार की राशि बजट अनुमान का 94 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की राशि के बराबर है। द्वितीयक बाजार के संबंधित खंडों में बेंचमार्क के निर्धारण के लिए तीन नई प्रतिभूतियां जारी की गईं, यथा - (i) 10 वर्षीय प्रतिभूति (7.59% सरकारी प्रतिभूति 2016, अप्रैल 2006 में पहली बार जारी); (ii) 15 वर्षीय प्रतिभूति (मई 2006 में जारी 7.94% सरकारी प्रतिभूति 2021); तथा (iii) 30 वर्षीय प्रतिभूति (जून 2006 में जारी 8.33% सरकारी प्रतिभूति 2036)। जून 2006 के दौरान प्रणाली की अतिरिक्त चलनिधि को कम करने के लिए निर्गम कैलेंडर से बाहर 4,000 करोड़ रुपए की राशि उगाही गई। जुलाई 2006 में हुई परवर्ती निलामियों में निलामी की राशि में कमी करके अतिरिक्त निर्गम का ऑफसेट किया। सरकार की उधार आवश्यकता की समीक्षा के बाद, 10-14 वर्ष के खंड (रु. 5,000 करोड़) की अनुसूचित निलामी को 12 जनवरी 2007 को हुई निलामी में रद्द किया गया। वर्ष 2006-07 के दौरान जारी की गई 33 प्रतिभूतियों में से 30 का फिर से निर्गमन किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिक व्यापारियों पर हुए अंतरण (डिवाल्बमेंट) की राशि 5,604 करोड़ रुपए थी।

2.103 2006-07 के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों का भारत औसत प्रतिफल वर्ष 2005-06 के 7.34 प्रतिशत के मुकाबले 7.89 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर था। वर्ष के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों का भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के 16.90 वर्ष के मुकाबले 14.72 वर्ष रहा।

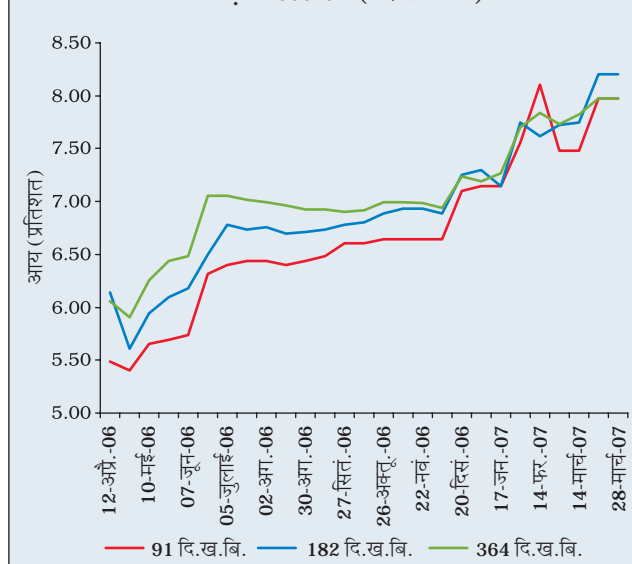
खजाना बिल

2.104 24 मार्च 2006 को जारी निर्गम कैलेंडर के अनुसार, सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशि क्रमशः 500 करोड़

रुपए (साप्ताहिक निलामी), 500 करोड़ रुपए (पाक्षिक निलामी) तथा 1,000 करोड़ रुपए (पाक्षिक निलामी) अपरिवर्तित रखी गई। अप्रैल-जून 2006 के दौरान 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के प्राथमिक बाजार प्रतिफल में विभिन्न कारणों से बढ़ोतरी हुई, जैसे मुद्रास्फीति में वृद्धि की संभावना, एमएसएस के अंतर्गत अधिक राशि का निर्गम तथा 8 जून 2006 को रेपो तथा रिवर्स रेपो दर में अप्रत्याशित वृद्धि। जुलाई से दिसंबर 2006 के दौरान प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता के चलते प्रतिफल की दर सामान्यतः स्थिर रही। तथापि, 8 दिसंबर 2006 को सीआरआर में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के प्रतिफल में, पिछली निलामियों की तुलना में क्रमशः 45 आधार अंक, 36 आधार अंक और 30 आधार अंक की वृद्धि हुई। फरवरी 2007 में सीआरआर में एक और बढ़ोतरी किए जाने तथा कर के अग्रिम भुगतान के कारण मार्च 2007 के मध्य में चलनिधि की मात्रा में कमी के चलते प्रतिफल की दरों में और वृद्धि हुई। मार्च 2007 की समाप्ति का 91 दिवसीय 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय प्राथमिक बाजार प्रतिफल क्रमशः 7.98 प्रतिशत, 8.20 प्रतिशत तथा 7.98 प्रतिशत था जो वर्ष 2006-07 की पहली निलामी की तुलना में क्रमशः 1.87 प्रतिशत, 1.59 प्रतिशत तथा 1.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है (चार्ट II.13)।

2.105 अप्रैल तथा मई 2007 के दौरान खजाना बिलों के द्वितीयक बाजार का प्रतिफल दायरे के अंदर रहा। मई 2007 के दौरान 91 दिवसीय खजाना बिलों (23 मई 2007 को), 182 दिवसीय खजाना बिलों (16 मई 2007 को), तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों (23 मई 2007 को) का प्राथमिक बाजार प्रतिफल क्रमशः 7.64 प्रतिशत 7.75 प्रतिशत तथा 7.80 प्रतिशत रहा।

चार्ट II.13 : खजाना बिलों के प्राथमिक आय में घट-बढ़ : 2006-07 (अप्रैल-मार्च)



2.106 वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों की चलनिधि की स्थिति संतोषजनक रही। आठ राज्यों ने अर्थोपाय अग्रिम लिया तथा दो राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया। राज्यों द्वारा लिए गए अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्टों का वर्ष 2006-07 का साप्ताहिक औसत 234 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2005-06 के 482 करोड़ रुपए से कम है। साथ ही, वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में निवेश का साप्ताहिक औसत 43,075 करोड़ रुपए था जो पिछले वर्ष के 35,278 करोड़ रुपए से काफी अधिक है।

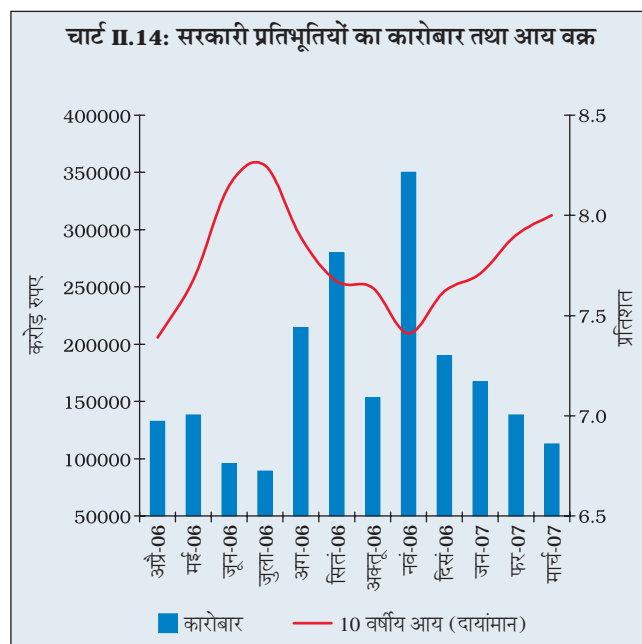
राज्य सरकारों का बाजार उधार

2.107 बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, वर्ष 2005-06 से राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय ऋण को समाप्त कर दिया गया है तथा राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि अपने संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे बाजार से सीधे धन की उगाही करें। साथ ही, राजकोषीय समेकन संबंधी प्रयासों तथा केंद्रीय अंतरण की राशि में वृद्धि के चलते जीडीपी के अनुपात के रूप में राज्यों की समग्र उधार आवश्यकता में कमी आई। इसके अलावा, राष्ट्रीय लघु बचत निधि में लगातार वृद्धि के चलते, यद्यपि यह वृद्धि घटती दर पर थी, राज्यों के स्तर पर नकद शेष राशि में तेज वृद्धि हुई और इसके कारण वर्ष 2006-07 में राज्यों द्वारा खुले बाजार से लिए गए निवल उधार (सकल उधार भी) की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में कम थी।

2.108 वर्ष 2006-07 के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए 17,242 करोड़ रुपए का निवल आबंटन (अर्न्तम) किया गया। वर्ष के दौरान 2,803 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आबंटन तथा 6,551 करोड़ रुपए के भुगतान को हिसाब में लेते हुए पिछले वर्ष के 21,729 करोड़ रुपए के वास्तविक सकल उधार की तुलना में सकल आबंटन की राशि 26,597 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के सकल उधार की राशि 20,825 करोड़ रुपए (केवल नीलामी के जरिए उगाही गई) थी जबकि पिछले वर्ष यह राशि 21,729 करोड़ रुपए (नीलामी के जरिए 8,723 करोड़ रुपए तथा सतत (टैप) निर्गम के जरिए 11,186 करोड़ रुपए) थी। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ऋणों की नीलामियों में अधिकतम प्रतिफल का स्प्रेड 50 आधार अंक से कम रहा।

2.109 वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल 8.10 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह 7.63 प्रतिशत था। इस अवधि में अधिकतम प्रतिफल 7.65 प्रतिशत तथा 8.66 प्रतिशत के बीच रहा। वित्तीय वर्ष में जारी सभी निर्गमों की परिपक्वता अवधि 10 वर्ष थी। वर्ष के दौरान छह राज्य बाजार में नहीं आए।

2.110 सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की राज्यवार सीमा की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2007-08 के लिए इन सीमाओं को



अपरिवर्तित रखा जाए। तदनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 9,875 करोड़ रुपए निर्धारित की गई।

सरकारी प्रतिभूतियों में अनुषंगी बाजार लेन-देन

2.111 मार्च 2007 में बाजार लेन-देनों की मात्रा मार्च 2007 के 2,40,478 करोड़ रुपए (इसमें से 19.1 प्रतिशत एकमुश्त लेनदेन तथा शेष रेपो से संबंधित था) की तुलना में सामान्य बढ़कर 2,64,868 करोड़ रुपए (इसमें से 21 प्रतिशत एकमुश्त लेनदेन तथा शेष रेपो से संबंधित था) हो गई। एकमुश्त खरीद की मात्रा तथा 10 वर्षीय प्रतिभूति के माह के अंत के प्रतिफल में विपरीत संबंध परिलक्षित होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार की मात्रा जुलाई 2006 में सबसे कम थी जब प्रतिफल उच्चतम स्तर पर था (चार्ट II.14)। मार्च 2006 के दौरान के 8,70,109 करोड़ रुपए के कारोबार के मुकाबले मार्च 2007 (एकमुश्त लेनदेनों का दोगुना तथा रेपो का चार गुना के रूप में परिकलित) के दौरान कारोबार बढ़कर 9,46,608 करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2007 के दौरान एनडीएस में सबसे अधिक लेनदेन वाली पांच प्रतिभूतियों का कारोबार कुल कारोबार का 57 प्रतिशत था जो प्रतिभूतियों में तरलता के असमान वितरण को दर्शाता है।

आय (प्रतिफल) में घटबढ़ तथा प्रतिफल वक्र

2.112 वर्ष 2006-07 में केंद्र सरकार का बाजार उधार कार्यक्रम पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक था। इसके अतिरिक्त, तेल की कीमतों में वृद्धि जन्य मुद्रास्फीतीय दबाव तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दर चक्र में उलटाव के चलते पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्रतिफल में कमी आई।

2.113 वर्ष 2006-07 के दौरान अनुषंगी बाजार का प्रतिफल, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा। मार्च 2006 के अंत के 7.52 प्रतिशत के स्तर से जुलाई 2006 के मध्य तक अनुषंगी बाजार के प्रतिफल में तेज वृद्धि हुई। इसके कारणों में यूएस तथा अन्य अर्थव्यवस्थाओं में कठोर मौद्रिक नीति के चलते देश में ऐसी ही नीति की संभावना, कच्चे तेल की ऊंची तथा अस्थिर कीमतें, ईंधन की घरेलू कीमतों में वृद्धि की आशंका, 11 जुलाई 2006 को हुई निलामी में प्राथमिक व्यापारियों पर अंतरण (डिवाल्वमेंट) तथा 9 जून 2006 से रिवर्स रेपो और रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी जैसे कारक थे। 11 जुलाई 2006 को 10 वर्षीय प्रतिफल बढ़कर 8.40 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। उसके बाद, यूएस फेडरल फंड दर में वृद्धि रुक जाने के कारण यूएस ट्रेजरी में निवेश बढ़ने तथा अगस्त 2006 से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में कमी के चलते प्रतिफल में वृद्धि हुई। राजकोषीय वर्ष के उत्तरार्ध के लिए निर्गम कैलेंडर की घोषणा, जो कि बाजार की अपेक्षा के अनुरूप थी, के चलते भी प्रतिफल में वृद्धि हुई। दिसंबर 2006 के प्रथम सप्ताह से प्रतिफल में वृद्धि प्रारंभ हुई जो अन्य बातों के साथ-साथ मुद्रास्फीतिकारी दबाव के चलते सीआरआर की दर में वृद्धि (दिसंबर 2006 तथा फरवरी तथा मार्च 2007), एसएलआर अध्यादेश की घोषणा तथा दिसंबर 2006 तथा मार्च 2007 में कर के अग्रिम भुगतान के कारण चलनिधि में आई कमी को दर्शाता है। मार्च 2007 के अंत में प्रतिफल की दर, अंततः 7.97 प्रतिशत पर बंद हुई।

2.114 30 मार्च 2007 को सीआरआर में बढ़ोतरी की घोषणा के कारण 3 अप्रैल 2007 तक प्रतिफल बढ़कर 8.19 प्रतिशत तक पहुंच गया। चलनिधि की स्थिति में परिवर्तन के कारण अप्रैल और मई 2007 में प्रतिफल में घट-बढ़ होती रही। 24 मई 2007 को प्रतिफल 8.19 प्रतिशत के स्तर पर था।

2.115 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की निलामियों में रिजर्व बैंक के भाग न लेने तथा राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय ऋण समाप्त किए जाने के कारण राज्यों द्वारा बाजार से संसाधन जुटाने की आवश्यकता के चलते न केवल चलनिधि की बेहतर स्थिति की आवश्यकता थी बल्कि नई व्यवस्था में सुगमता से संक्रमण के लिए बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नए लिखतों की भी आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में सरकारी प्रतिभूति बाजार को व्यापक तथा गहन बनाने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों जैसे, निष्क्रिय समेकन के लिए जोर देने, सरकारी प्रतिभूति में सॉर्ट सेलिंग तथा 'जब जारीत बाजार चरणबद्ध रूप में प्रारंभ करने तथा विद्यमान सहभागियों को कार्यकलापों में विशाखीकरण की अनुमति देने के कारण चलनिधि की स्थिति में सुधार होने और ऋण प्रबंधन के सुचारू व्यवस्थापन के लिए मूल्य की बेहतर खोज में सुविधा मिलेगी। यद्यपि वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 का समेकित बाजार उधार कार्यक्रम बड़ा था तथापि बाजार विकास संबंधी विभिन्न उपायों के चलते इसे आसानी से पूरा किया गया।

विदेशी मुद्रा बाजार

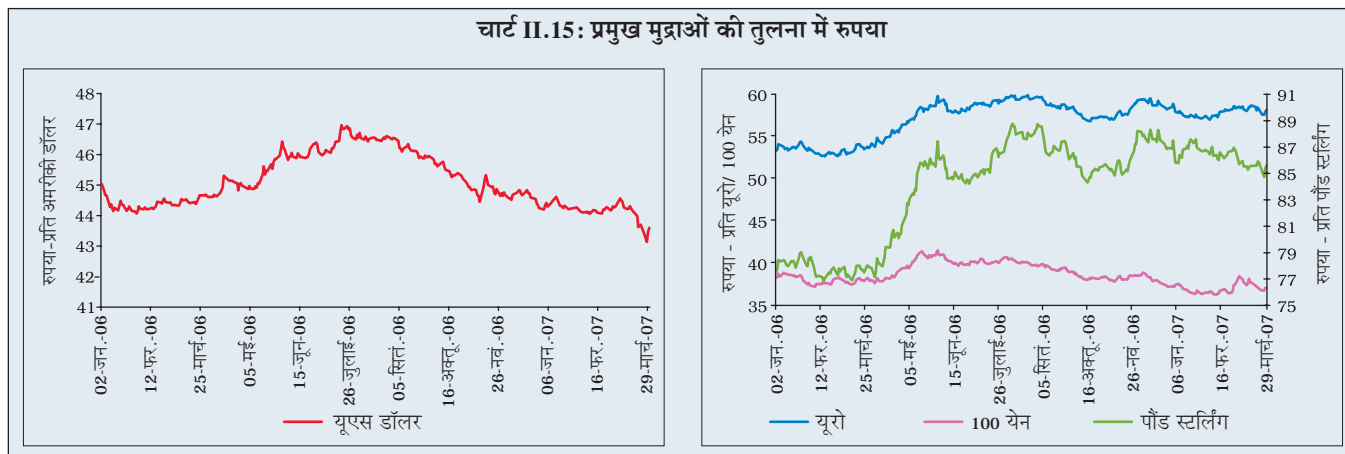
2.116 तेल की कीमतों में वृद्धि तथा आइएमडी भुगतानों के दबावों के बावजूद, विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति सामान्यतः व्यवस्थित थी तथा वर्ष 2005-06 में अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए में दोतरफा उतार-चढ़ाव देखा गया। वर्ष 2006-07 के दौरान पूंजी प्रवाह में घट-बढ़, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा बाजार में चलनिधि की स्थिति के अनुरूप अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 43.14 रुपए से 46.97 रुपए के बीच रही। मई-जुलाई 2006 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ईक्विटी बाजार में अत्यधिक बिक्री तथा प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने के कारण रुपए पर दबाव बढ़ा। मध्य पूर्व क्षेत्र में भू-राजनीतिक जोखिमों के चलते तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि ने भी रुपए पर दबाव बनाने का कार्य किया। तेल की कीमतों में कमी आने के कारण जुलाई 2006 के अंतिम सप्ताह से रुपए ने संभलना शुरू किया। नवंबर 2006 के मध्य तक अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती जारी रही तथा येन/डालर दरों में घट-बढ़ होने, तेल की कीमतों में कमी आने, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश में वृद्धि किए जाने, तथा कारपोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुदृढ़ता आने के चलते 10 नवंबर 2006 को रुपया प्रति अमरीकी डॉलर के मुकाबले 44.45 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। तथापि, नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान कारपोरेट तथा बैंकों द्वारा डालर की मांग में अत्यधिक वृद्धि के चलते डालर के मुकाबले रुपए के मूल्य में तेजी से कमी आई। अत्यधिक मात्रा में पूंजी के आने तथा बाजार में चलनिधि की कमी के चलते 16 नवंबर 2006 से रुपए में मजबूती आनी शुरू हो गई। 30 मार्च 2007 को प्रति अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 43.60 रुपए के स्तर पर था तथा 31 मार्च 2006 के मुकाबले इसमें 2.3 प्रतिशत की मजबूती आई थी। इसी अवधि में रुपए में पौंड स्टर्लिंग के मुकाबले 9.1 प्रतिशत तथा यूरो के मुकाबले 6.8 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई जबकि जापानी येन के मुकाबले इसमें 2.7 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ।

2.117 वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक (22 मई 2007 तक) मुख्यतः पूंजी के अत्यधिक अंतर्वाह के चलते रुपए में मजबूती आई। मार्च 2007 के अंत की स्थिति की तुलना में रुपए में 7.3 प्रतिशत मजबूती आई तथा 22 मई 2007 को प्रति अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 40.64 रुपए के स्तर पर था। इसी अवधि में यूरो, पौंड स्टर्लिंग तथा जापानी येन के मुकाबले रुपए में क्रमशः 6.2 प्रतिशत, 6.8 प्रतिशत तथा 10.6 प्रतिशत की मजबूती आई (चार्ट II.15)।

2.118 वर्ष 2006-07 के दौरान वायदा दर प्रीमियम पर रही। यूएस में कठोर मौद्रिक नीति के चलते ब्याज दरों के अंतर में कमी आने के अनुरूप अप्रैल-मई 2006 के दौरान वायदा प्रीमियमों में कमी आई। तथापि, घरेलू ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ब्याज दर अंतर में वृद्धि के चलते

हाल की आर्थिक गतिविधियां

चार्ट II.15: प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपया



जून 2006 से वायदा प्रीमियम में वृद्धि प्रारंभ हुई। चलनिधि की मात्रा में कमी के कारण भी वायदा प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई। तीन माह का औसत प्रीमियम जून 2006 के 0.73 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 में 4.51 प्रतिशत (चार्ट II.16) और अप्रैल 2007 में 6.91 प्रतिशत हो गया।

पूंजी बाजार

2.119 वर्ष 2006-07 में सार्वजनिक निर्गमों, निजी स्थानन तथा यूरो निर्गमों द्वारा जुटाए गए संसाधन की राशि पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक थी। वर्ष 2005-06 से शेयर बाजार में प्रारंभ हुई वृद्धि की प्रवृत्ति वर्ष 2006-07 में और भी तेज हुई तथा 8 फरवरी 2007 को बेंचमार्क बीएसइ सेसेक्स बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 14,652.09 पर बंद हुआ। तथापि, उसके बाद यूएस सब-प्राइम बंधक उधार उद्योग में संकट की खबर तथा यूएस में फरवरी में रिटेल बिक्री में अप्रत्याशित कमी, कच्चे

तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय ईक्विटी बाजार में मार्च 2007 में निवल बिक्री तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों में मंदी जैसे कारणों के चलते शेयरों की कीमतों में करेक्शन देखा गया।

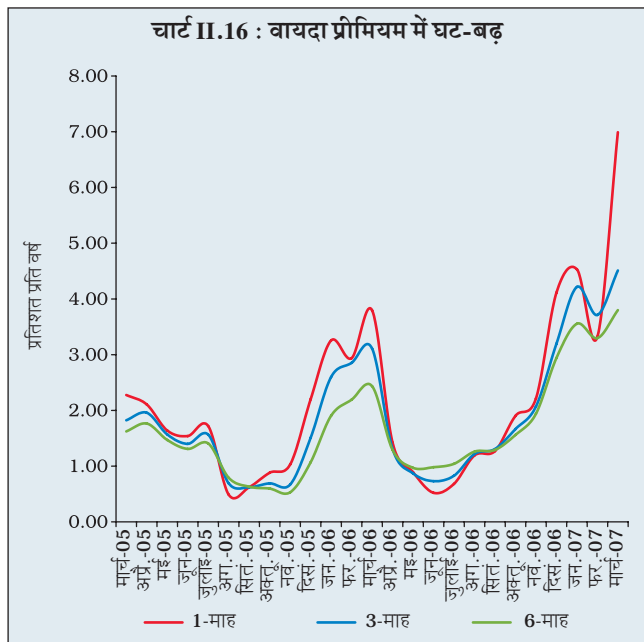
प्राथमिक बाजार

2.120 वर्ष 2006-07 के दौरान प्राथमिक बाजार में तेजी की स्थिति थी। सार्वजनिक निर्गमों के जरिए जुटाई गई राशि पिछले वर्ष के 26,940 करोड़ (138 निर्गमों से) के मुकाबले 2006-07 में 32,382 (119 निर्गमों से) करोड़ रुपए के उच्चतर स्तर पर थी (सारणी 2.37)। एक को छोड़कर शेष सभी सार्वजनिक निर्गम निजी क्षेत्र की कंपनियों के थे। 119 सार्वजनिक निर्गमों में से 116 निर्गम ईक्विटी के रूप में तथा तीन निर्गम ऋण के रूप में थे।

2.121 अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के जरिए उगाही गई राशि 1,03,169 करोड़ रुपए थी जो वर्ष 2005 की इसी अवधि में उगाही गई राशि की तुलना में 50.8 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान निजी स्थानन के जरिए जुटाई गई राशि में से सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं का हिस्सा 42.0 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2005 की इसी अवधि में यह हिस्सा 56.9 प्रतिशत था (सारणी 2.37)। अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान वित्तीय मध्यस्थों (निजी तथा सरकारी) द्वारा जुटाई गई राशि 63.3 प्रतिशत बढ़कर 71,621 करोड़ रुपए हो गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में जुटाई गई राशि 43,868 करोड़ रुपए थी।

2.122 वर्ष 2006-07 के दौरान अमेरिकन डिपाजिटरी रसीद (एडीआर) तथा वैश्विक डिपाजिटरी रसीद (जीडीआर) के जरिए यूरो निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों की राशि में 49.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 के दौरान 40 यूरो निर्गमों के जरिए 17,005 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान 48 यूरो निर्गमों के जरिए कुल 11,352 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई थी (सारणी 2.37)।

चार्ट II.16 : वायदा प्रीमियम में घट-बढ़



मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.37 : प्राथमिक बाज़ार * से संसाधन संग्रहण

(राशि करोड़ रूप में)

मद	2004-05		2005-06		2006-07#	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
क. सार्वजनिक निर्गम @ (प्रॉस्पेक्ट्स और राइट्स)	59	21,892	138	26,940	119	32,382
I. सार्वजनिक क्षेत्र	5	8,410	7	5,786	1	782
II. निजी क्षेत्र	54	13,482	131	21,154	118	31,600
ख. निजी प्लेसमेंट	910	83,405	1,112	96,369	1,195	1,03,169
I. सार्वजनिक क्षेत्र	193	47,611	168	55,164	84	43,373
II. निजी क्षेत्र	717	35,794	944	41,205	1,111	59,796
ग. यूरो निर्गम@@	12	2,730	48	11,352	40	17,005

* : ऋण और ईक्विटी दोनों सहित।

: निजी प्लेसमेंट के लिए, आंकड़े अप्रैल-दिसंबर से संबंधित हैं।

@ : बिक्री के लिए प्रस्ताव को छोड़कर।

@@ : एफसीसीबी को छोड़कर।

नोट : अनुमान एर्रेजों, वित्तीय संस्थाओं और सेबी से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

2.123 वर्ष 2006-07 के दौरान म्यूच्युअल फंडों द्वारा जुटाए गए संसाधनों (शोधन (रिडेम्सन) की राशि घटाकर) की राशि 78.1 प्रतिशत बढ़कर 93,985 करोड़ रूपए हो गई। वर्ष 2006-07 के दौरान यूटीआइ म्यूच्युअल फंड ने पिछले वर्ष के 3,424 करोड़ रूपए के मुकाबले अधिक राशि अर्थात् 7,326 करोड़ रूपए की राशि जुटाई। वर्ष 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के म्यूच्युअल फंडों को क्रमशः 7,621 करोड़ रूपए तथा 79,038 करोड़ रूपए की निवल राशि प्राप्त हुई जो पिछले वर्ष के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से अधिक है (सारणी 2.38)। योजना-वार रूप में, वर्ष 2006-07 में उगाही गई राशि में से 5.3 प्रतिशत राशि लिक्विड/मुद्रा बाजार अभिमुख योजनाओं के लिए (पिछले वर्ष के 8.0 प्रतिशत की तुलना में) तथा 63.9 प्रतिशत राशि ऋण अभिमुख योजनाओं के लिए (पिछले वर्ष 26.5 प्रतिशत) प्राप्त हुई थी। दूसरी ओर, ईक्विटी संबद्ध बचत योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि, जुटाई गई कुल निवल राशि का 4.7 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष यह राशि 6.8 प्रतिशत थी। वर्ष 2006-07 के दौरान, श्रेष्ठ प्रतिभूति (गिल्ट) अभिमुख योजनाओं के अंतर्गत निधियों का निवल बहिर्वाह 1.0 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह 3.0 प्रतिशत था।

सारणी 2.38 : म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवल संसाधन संग्रहण

(करोड़ रूपए)

श्रेणी	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
I. यूटीआइ म्यूच्युअल फंड	-2,722	3,424	7,326
II. निजी क्षेत्र	7,599	42,977	79,038
III. सार्वजनिक क्षेत्र	-2,677	6,379	7,621
कुल (I+II+III)	2,200	52,780	93,985

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी)।

अनुषंगी बाजार

2.124 10 मई 2006 तक मुख्यतः समष्टि आर्थिक बुनियादी तत्वों के सुदृढ़ होने, कंपनियों की आय में अच्छी वृद्धि होने, अंतर्राष्ट्रीय ईक्विटी बाजार में वृद्धि की प्रवृत्ति तथा धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते शेयर बाजार में तेजी बनी रही तथा उस दिन बीएसई सेंसेक्स तथा सीएनएक्स निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर क्रमशः 12612.38 तथा 3754.25 अंकों पर बंद हुआ। परंतु, वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका के चलते विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारी निवल बिक्री, लंदन मेटल एक्सचेंज में मूल धातु की कीमतों में भारी कमी, कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में वृद्धि एवं घरेलू मुद्रास्फीति में उच्चतर वृद्धि की आशंका के चलते 11 मई 2006 के प्रारंभ से बाजार में तेज करेशन हुआ। 14 जून 2006 को बीएसई सेंसेक्स घटकर 8929.44 तक आ गया जो मार्च 2006 के अंत की स्थिति से 20.8 प्रतिशत कम है। तथापि, उसके बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा म्यूच्युअल फंडों द्वारा नई खरीद, प्रमुख कंपनियों की दूसरी और तीसरी तिमाही का अच्छा कारपोरेट परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों में वृद्धि का रुख, अमरीकी डॉलर की तुलना में रूपए में बढ़ोतरी, लगभग सामान्य मानसून, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में कमी, यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में परिवर्तन न करने का निर्णय, लंदन मेटल एक्सचेंज में धातुओं की कीमतों में वृद्धि तथा अन्य क्षेत्र एवं स्टॉक विशेष संबंधी खबरों के चलते शेयर बाजार में सुधार हुआ। 8 फरवरी 2007 को बीएसई सेंसेक्स अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 14652.09 तक पहुंच कर बंद हुआ। तथापि, 9 फरवरी 2007 तथा मार्च 2007 के अंत के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका, अंतर्राष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों में अनिश्चितता, यूएस सब प्राइम बंधक उधार खंड में संकट की रिपोर्ट, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय ईक्विटी बाजारों में निवल

बिक्री के चलते प्रमुख संकेतों में निम्नगामी प्रवृत्ति देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 30 मार्च 2007 को 13,072.10 अंक पर बंद हुआ जो मार्च 2006 के अंत के स्तर से 1792 अंक अथवा 15.9 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2006-07 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 48.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 के दौरान बीएसई-500 तथा बीएसई मिडकैप में क्रमशः 9.7 प्रतिशत तथा 0.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बीएसई स्माल कैप में 1.9 प्रतिशत की कमी आई।

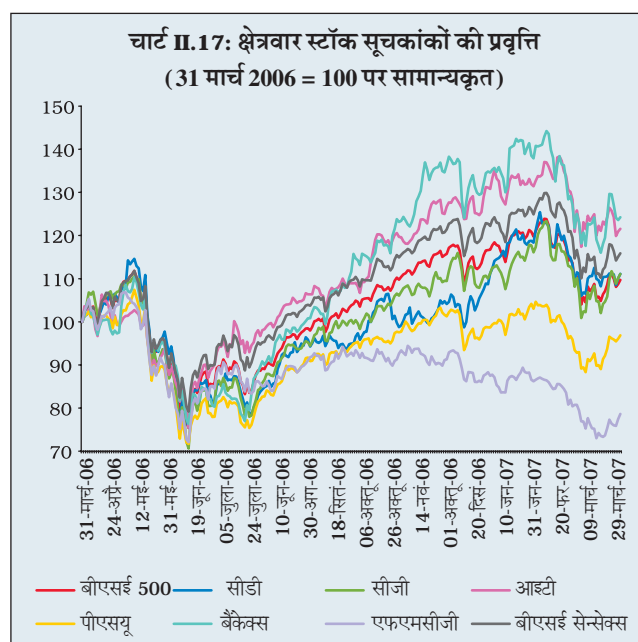
2.125 वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक (21 मई 2007 तक) घरेलू स्टॉक बाजार में वृद्धि का रुख रहा, हालांकि बीच-बीच में करेक्शन भी होते रहे। बीएसई सेंसेक्स तथा एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी 21 मई 2007 को, क्रमशः 14,418.60 तथा 4260.90 के उच्चतर स्तर पर बंद हुआ जो मार्च 2007 के अंत के स्तर से क्रमशः 10.3 प्रतिशत तथा 11.5 प्रतिशत अधिक है। चौथी तिमाही के दौरान अच्छा कारपोरेट परिणाम, मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी तथ्य, घरेलू मुद्रास्फीति की दर में कमी, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों में तेजी की प्रवृत्ति, भारतीय ईक्विटी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा म्यूच्युअल फंडों द्वारा निवल खरीद, लंदन मेटल एक्सचेंज में धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी तथा भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की रिपोर्ट ने बाजार के रुख को प्रभावित किया।

2.126 बंबई स्टॉक एक्सचेंज का बाजार पूंजीकरण मार्च 2006 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 84.7 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2007 के अंत में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 86.5 प्रतिशत हो गया। अप्रैल-मार्च 2006-07 के दौरान बीएसई तथा एनएसई का कुल कारोबार (टर्नओवर) 28,99,916 करोड़ रुपए का था जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। बीएसई

सारणी 2.39 : शेयर बाजारों की प्रवृत्तियाँ

मद	बीएसई		एनएसई	
	अप्रैल-मार्च			
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1. औसत बीएसई सेंसेक्स /एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी	8280	12277	2513	3572
2. उतार-चढ़ाव (भिन्नता का गुणांक)	16.72	11.09	15.60	10.36
3. कारोबार (करोड़ रुपए)	8,16,074	9,56,185	15,69,556	19,44,645
4. बाजार पूंजीकरण (अवधि के अंत का) (करोड़ रुपए)	30,22,191	35,45,041	28,13,201	33,67,350
(जीडीपी का प्रतिशत)	84.7	86.5	78.9	82.1
5. पी/ई अनुपात (अवधि के अंत का)	20.92	20.33	20.26	18.40

स्रोत : मुंबई शेयर बाजार (बीएसई) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)।



सेंसेक्स का मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात मार्च 2007 के अंत में 20.33 था जोकि मार्च 2006 के अंत के 20.92 से कम है (सारणी 2.39)। 23 मई 2007 को मूल्य-आय अनुपात 21.04 था। वर्ष 2006-07 में इसमें उतार-चढ़ाव में कमी आई।

2.127 क्षेत्रवार प्रवृत्ति से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2006-07 के दौरान तेल तथा गैस, आइटी, बैंकिंग, पूंजीगत वस्तुओं तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के शेयरों में खरीदारी देखी गई जबकि एफएमसीजी, स्वास्थ्य क्षेत्र, ऑटो, धातु तथा सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा (चार्ट II.17)। विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते तेल तथा गैस क्षेत्र के शेयरों में उछाल आया, विदेशों में आइटी तथा आइटी समर्थित सेवाओं की बढ़ती मांग तथा आइटी कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन के चलते इन शेयरों की मांग में जो बढ़ोतरी हुई उसका लाभ आइटी स्टॉक को मिला। बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों की मांग में वृद्धि के कारणों में क्षमता में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए ऋण की मांग में वृद्धि, आधारभूत परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा व्यक्तिगत ऋण में उच्च वृद्धि प्रमुख हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र वृद्धि के कारण निवेश संबंधी कार्यकलापों में बढ़ोतरी होने तथा औद्योगिक तथा संरचनात्मक क्षेत्र के कार्य निष्पादन में वृद्धि के चलते पूंजीगत क्षेत्र के शेयरों में मजबूती आई। दूसरी ओर, स्टील की कीमतों में वृद्धि तथा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ऑटो क्षेत्र के शेयर गिरे जबकि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण मांग में कमी आने से एफएमसीजी स्टॉक में गिरावट देखी गई।

2.128 सेबी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय ईक्विटी में वर्ष 2006-07 का 25,236 करोड़ रुपए का निवेश वर्ष 2005-06 की तुलना में कम है। तथापि, पिछले वर्ष की

सारणी 2.40 : शेयर बाजार में संस्थागत निवेश

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विदेशी संस्थागत निवेशकर्ता		म्यूचुअल फंड	
	ईक्विटी	ऋण	ईक्विटी	ऋण
1	2	3	4	5
2001-02	8,067	685	-3,796	10,959
2002-03	2,528	60	-2,067	12,604
2003-04	39,959	5,805	1,308	22,701
2004-05	44,123	1,759	448	16,987
2005-06	48,542	-7,065	14,302	36,801
2006-07	25,236	5,605	9,024	52,546

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

निवल बिकवाली की तुलना में, इस वर्ष ऋण लिखतों में निवेश की राशि 5,605 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2006-07 के दौरान म्यूचुअल

सारणी 2.41 : राष्ट्रीय शेयर बाजार में नकदी के मुकाबले डेरिवेटिव्स बाजार में कारोबार

(करोड़ रुपए)

वर्ष	डेरिवेटिव्स	नकदी
1	2	3
2001-02	1,01,926	5,13,167
2002-03	4,39,862	6,17,989
2003-04	21,30,610	10,99,535
2004-05	25,46,982	11,40,071
2005-06	48,24,174	15,69,556
2006-07	73,56,242	19,45,285

स्रोत: राष्ट्रीय शेयर बाजार

फंड द्वारा ईक्विटी में निवेश की राशि 9,024 करोड़ रुपए थी जोकि पिछले वर्ष की तुलना में कम है। परंतु, वर्ष 2006-07 में म्यूचुअल फंड द्वारा ऋण लिखतों में निवेश की राशि 52,546 करोड़ रुपए थी जो वर्ष 2005-06 की तुलना में काफी अधिक है (सारणी 2.40)। वर्ष 2007-08 के दौरान (22 मई 2007 तक) विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा म्यूचुअल फंडों द्वारा निवल निवेश की राशि क्रमशः 8,785 करोड़ रुपए तथा 2,704 करोड़ रुपए थी।

2.129 वर्ष 2006-07 के दौरान एनएसइ के डेरिवेटिव खंड का कुल कारोबार नकद खंड के कारोबार से काफी अधिक था (सारणी 2.41)।

V. बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं

2.130 बेहतर समष्टि आर्थिक कार्य-निष्पादन ने सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के कारोबार परिचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन में सहायता की। वर्ष 2005-06 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों में 18.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों की औसत कारक (फैक्टर) लागत वर्तमान मूल्यों में मार्च 2005 के अंत के 82.8 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2006 के अंत में बढ़कर 86.9 प्रतिशत हो गई, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र की तेज वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि के चलते लगातार दूसरे वर्ष भी बैंक ऋण में विस्तार देखा गया।

2.131 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण तथा अग्रिमों में वर्ष 2004-05 के 33.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2005-06 में पिछले स्तर से और 31.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि रिटेल क्षेत्र में ऋण का विस्तार, विशेष रूप से आवास तथा कॉमर्शियल रियल एस्टेट ऋण के रूप में काफी अधिक होने पर भी ऋण का विस्तार व्यापक था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण में पिछले वर्ष के 40.3 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 2005-06 में 33.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऋण में वृद्धि का लाभ मुख्यतः कृषि तथा आवास क्षेत्र को प्राप्त हुआ जिन्हें 2005-06 के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वृद्धिशील उधार के दो तिहाई से भी अधिक का हिस्सा प्राप्त हुआ। लघु उद्योगों को दिए गए ऋण में भी वृद्धि हुई। ऋण की अत्यधिक खपन के चलते वृद्धिशील ऋण जमा अनुपात वर्ष भर 100 प्रतिशत के ऊपर रहा। यद्यपि जमाराशियों में वृद्धि की दर (वर्ष 2005-06 में 17.8 प्रतिशत) पिछले वर्ष (16.6 प्रतिशत) के मुकाबले अधिक थी, फिर भी, ऋण की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त न होने के कारण उसे पूरा करने के लिए बैंकों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचनी पड़ी।

2.132 समूह के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसमें 5.9 प्रतिशत की कमी आई थी तथा इस वृद्धि का कारण ब्याज से इतर आय में अभूतपूर्व वृद्धि होना है (सारणी 2.42)। तथापि, निवल लाभ कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में लगभग पिछले वर्ष के समान था। मार्च 2006 के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां तथा निवल अनर्जक आस्तियां क्रमशः 3.3 प्रतिशत तथा 1.2 प्रतिशत थीं जो मार्च 2005 के अंत के क्रमशः 5.2 प्रतिशत तथा 2.0 प्रतिशत से काफी कम है। जोखिम भारित आस्तियों में भारी वृद्धि, कुछ क्षेत्रों में उधार के लिए जोखिम का अधिक भार तथा बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार लगाए जाने के बावजूद बैंक का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात लगभग पिछले वर्ष के स्तर (मार्च 2005 में 12.8 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2006 के अंत में 12.3 प्रतिशत) पर बना रहा।

2.133 वर्ष 2005-06 के दौरान मुख्यतः जमाराशि में वृद्धि के चलते शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन में थोड़ी वृद्धि देखी गई। ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेश में थोड़ी वृद्धि देखी गई जबकि गैर-एसएलआर निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। निधियों के अल्पावधि अभिनियोजन (डिप्लॉइमेंट) में तेज वृद्धि देखी गई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। शहरी सहकारी

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.42: चुनिंदा बैंक समूहों के महत्वपूर्ण प्राचल (पैरामीटर्स)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	1996-97	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
परिचालन व्यय/कुल आस्तियां					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2.9	2.2	2.2	2.1	2.1
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2.9	2.3	2.2	2.1	2.1
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.5	2.1	2.0	2.0	2.1
निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0
विदेशी बैंक	3.0	2.8	2.8	2.9	2.8
स्प्रेड/कुल आस्तियां					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3.2	2.8	2.9	2.8	2.8
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3.2	2.9	3.0	2.9	2.9
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2.9	2.5	2.6	2.7	2.7
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.9	1.7	2.0	2.2	2.1
विदेशी बैंक	4.1	3.4	3.6	3.3	3.5
निवल लाभ/कुल आस्तियां					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	0.7	1.0	1.1	0.9	0.9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	0.6	1.0	1.1	0.9	0.8
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.9	1.2	1.2	0.3	0.6
निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.7	0.9	0.8	1.1	1.0
विदेशी बैंक	1.2	1.6	1.7	1.3	1.5
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	15.7	8.8	7.2	5.2	3.3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	17.8	9.4	7.8	5.5	3.7
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	10.7	8.9	7.6	6.0	4.3
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.6	7.6	5.0	3.6	1.7
विदेशी बैंक	4.3	5.3	4.6	2.8	1.9
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	8.1	4.4	2.9	2.0	1.2
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	9.2	4.5	3.0	2.1	1.3
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	6.6	5.5	3.8	2.7	1.6
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2.0	4.6	2.4	1.9	0.8
विदेशी बैंक	1.9	1.8	1.5	0.8	0.8
सीआरएआर					
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	10.4	12.7	12.9	12.8	12.3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.0	12.6	13.2	12.9	12.2
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	11.7	12.8	13.7	12.5	11.7
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.3	11.3	10.2	12.1	12.6
विदेशी बैंक	..	15.2	15.0	14.0	13.0
.. : अनुपलब्ध.					

बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता, ऋण पोर्टफोलियो के समग्र तथा सापेक्ष दोनों रूप में उल्लेखनीय सुधार हुआ (सारणी 2.43)।

2.134 नब्बे के दशक के प्रारंभ तक, वित्तीय संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रत्याभूत बांडों द्वारा रियायती दरों पर संसाधन उपलब्ध कराकर तथा भारतीय रिजर्व बैंक की दीर्घावधि परिचालन (एलटीओ) निधि से अग्रिम प्रदान करके निधि उपलब्ध कराई जाती थी। इस समय, वित्तीय संस्थाएं अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों प्रकार के संसाधन जुटा सकती हैं तथा ऐसा बकाया संसाधन किसी भी समय लेखा परीक्षित अद्यतन तुलनपत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) के 10 गुना से अधिक नहीं

होना चाहिए। इस समग्र सीमा के अधीन आठ संस्थाओं, अर्थात् आइएफसीआई, एग्जिम बैंक, सिडबी, आइआइबीआई, टीएफसीआई, नाबार्ड तथा एनएचबी के लिए एक “अम्ब्रेला लिमिट” निर्धारित की गई है। अम्ब्रेला लिमिट के अनुसार इन वित्तीय संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था मीयादी राशि (टर्म मनी), वाणिज्य पत्र, जमा प्रमाणपत्र, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट, तथा मीयादी जमाराशि के रूप में लेखा परीक्षित अद्यतन तुलनपत्र के अनुसार अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के 100 प्रतिशत तक संसाधन जुटा सकती है।

2.135 संसाधन जुटाने के लिए इन चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की सकल अम्ब्रेला लिमिट को 31 मार्च 2006 के 16,657 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.43: शहरी सहकारी बैंक - चुनिंदा वित्तीय संकेतक

संकेतक	2004-05	2005-06
1	2	3
प्रमुख समुच्चयों में वृद्धि (प्रतिशत)		
जमाराशि	-4.7	6.9
ऋण	-1.6	5.2
वित्तीय संकेतक@ (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
परिचालन लाभ	0.8	1.1
निवल लाभ	0.2	0.5
स्प्रेड	1.8	1.9
सकल अनर्जक आस्तियां (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)	23.4	19.7

@ : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित।

मार्च 2007 को 19,001 करोड़ रुपए किया गया। इन संस्थाओं द्वारा अंब्रेला लिमिटेड के अंतर्गत जुटाई गई राशि में से 31 मार्च 2006 को 1,204 करोड़ रुपए (सकल सीमा का 7.2 प्रतिशत) तथा 30 मार्च 2007 को 3,293 करोड़ रुपए (सकल सीमा का 17.33 प्रतिशत) की राशि बकाया थी। 30 मार्च 2007 की बकाया स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं ने सबसे अधिक वाणिज्य पत्र (2,540 करोड़ रुपए) तथा उसके बाद जमा प्रमाणपत्र (664 करोड़ रुपए), मीयादी जमाराशि (90 करोड़ रुपए) के जरिए बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाए। वर्ष 2006-07 के दौरान जिन वित्तीय संस्थाओं ने इन लिखतों के जरिए संसाधन जुटाए उनमें एकिजम बैंक, एनएचबी तथा सिडबी शामिल हैं। किसी भी वित्तीय संस्था ने इस अवधि में टर्म मनी अथवा इंटर कारपोरेट डिपॉजिट के जरिए संसाधन नहीं जुटाए।

2.136 वर्ष 2005-06 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ (सारणी 2.44)। वर्ष 2005-06 के दौरान अखिल

सारणी 2.44 : वित्तीय संस्थाएं - चुनिंदा निष्पादन संकेतक

संकेतक	2004-05	2005-06
1	2	3
तुलनपत्र संकेतक (आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
परिचालन लाभ	1.2	1.4
निवल लाभ	0.8	1.0
स्प्रेड	1.6	1.8
संसाधन प्रवाह (करोड़ रुपए)		
स्वीकृतियां	9,091	11,942
संवितरण	6,279	9,237
टिप्पणी : 1. तुलनपत्र संकेतक के डाटा आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, एगिजम बैंक, टीएफसीआइ, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी से संबंधित हैं।		
2. संसाधन प्रवाह के आंकड़े आइएफसीआइ, सिडबी और आइआइबीआइ से संबंधित हैं।		

सारणी 2.45 : एनबीएफसी के समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	(मार्च के अंत में)		
	2004	2005	2006
1	2	3	4
देयताएं			
1. प्रदत्त पूंजी	2,327 (7.1)	2,206 (6.1)	1,949 (5.5)
2. रिजर्व और अधिशेष	4,414 (13.5)	4,544 (12.6)	4,838 (13.6)
3. जनता की जमाराशि	4,317 (13.2)	3,926 (10.9)	2,667 (7.5)
4. उधार	20,852 (63.7)	23,044 (64.0)	23,641 (66.5)
5. अन्य देयताएं	844 (2.6)	2,283 (6.3)	2,466 (6.9)
कुल देयताएं / आस्तियाँ	32,754	36,003	35,561
आस्तियाँ			
1. निवेश			
i) एसएलआर निवेश	1,707 (5.2)	2,237 (6.2)	1,314 (3.7)
ii) गैर एसएलआर निवेश	2,110 (6.4)	1,720 (4.8)	2,275 (6.4)
2. ऋण और अग्रिम	12,363 (37.7)	12,749 (35.4)	9,199 (25.9)
3. किराया खरीद आस्तियां	11,649 (35.6)	14,400 (40.0)	19,893 (55.9)
4. उपस्कर पट्टा आस्तियां	3,036 (9.3)	2,025 (5.6)	1,620 (4.6)
5. बिल संबंधी कारोबार	436 (1.3)	471 (1.3)	45 (0.1)
6. अन्य आस्तियां	1,453 (4.4)	2,401 (6.7)	1,215 (3.4)
टिप्पणी : 1. सूचना देने वाली कंपनियों की संख्या 2005 के 703 से कम होकर 2006 में 466 रह गई।			
2. कोष्ठकों के आंकड़े कुल देयता/आस्ति का प्रतिशत दर्शाते हैं।			

भारतीय वित्तीय संस्थाओं, विशेषीकृत वित्तीय संस्थाओं, तथा निवेश संस्थाओं सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित राशि में क्रमशः 38.9 प्रतिशत तथा 33.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 45.1 प्रतिशत तथा 37.0 प्रतिशत की तेज गिरावट हुई थी। वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग सभी श्रेणियों की वित्तीय संस्थाओं के कार्य-निष्पादन में काफी अच्छी वृद्धि देखी गई जबकि वर्ष 2004-05 के दौरान उनका कार्य-निष्पादन मिलाजुला था।

2.137 वित्तीय संस्थाओं का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर), हानि पर चल रही दो संस्थाओं को छोड़कर, निर्धारित मानदंड के काफी ऊपर बना हुआ था। तथापि, वर्ष के दौरान लगातार वित्तीय हानि के चलते आइआइबीआइ तथा आइएफसीआइ के सीआरएआर में कमी

हाल की आर्थिक गतिविधियां

आई। उच्चतर उधार दर तथा निधि की उगाही की लागत में कमी आने के चलते वित्तीय संस्थाओं के स्प्रेड में बढ़ोतरी हुई तथा सकल आस्तियों की तुलना में निवल ब्याज आय का प्रतिशत वर्ष 2004-05 के 1.6 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया। वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं की ब्याज से इतर आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2.138 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) (आरएनबीसी को छोड़कर) की सकल आस्ति/देयताओं में, वर्ष 2004-05 में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत वर्ष 2005-06 में 1.2 प्रतिशत की कमी आई (सारणी 2.45)। एनबीएफसी द्वारा लिए गए उधारों में, जोकि उनकी निधियों का प्रमुख स्रोत है, पिछले वर्ष की 10.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, वर्ष 2005-06 में 2.6 प्रतिशत की कम दर पर वृद्धि हुई। वर्ष 2005-06 के दौरान एनबीएफसी की स्वयं की निधि (पूँजी तथा आरक्षित निधि) में थोड़ी-सी वृद्धि हुई जबकि उनकी जनता से ली गई जमाराशि में 32.1 प्रतिशत की कमी आई। आस्ति पक्ष में, ऋण तथा अग्रिम और किराया खरीद आस्तियां कुल आस्तियों का तीन-

सारणी 2.46 : अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों की प्रोफाइल

(राशि करोड़ रूपए)

मद	मार्च के अंत में		
	2004	2005	2006
1	2	3	4
I. आस्ति (I से V तक)	20,362	19,057	21,891
(i) अभांरित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	5,824	2,037	2,346
(ii) बैंकों में सावधि जमा	2,033	4,859	6,070
(iii) बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र*	6,048	9,225	9,577
(iv) अन्य निवेश	2,059	1,639	1,658
(v) अन्य आस्तियाँ	4,398	1,297	2,240
II. निवल स्वाधिकृत निधि	1,002	1,065	1,183
III. कुल आय (I+II)	2,055	1,532	1,620
(i) निधि आय	2,055	1,530	1,616
(ii) शुल्क आय	-	2	3
IV. कुल व्यय (I+II+III)	1,813	1,396	1,439
(i) वित्तीय लागत	1,368	1,176	1,165
(ii) परिचालन लागत	129	146	159
(iii) अन्य लागत	316	74	115
V. कर के लिए प्रावधान	32	48	22
VI. परिचालन लाभ (क.पू.ला.)	242	136	180
VII. निवल लाभ (क.ला.)	210	88	158

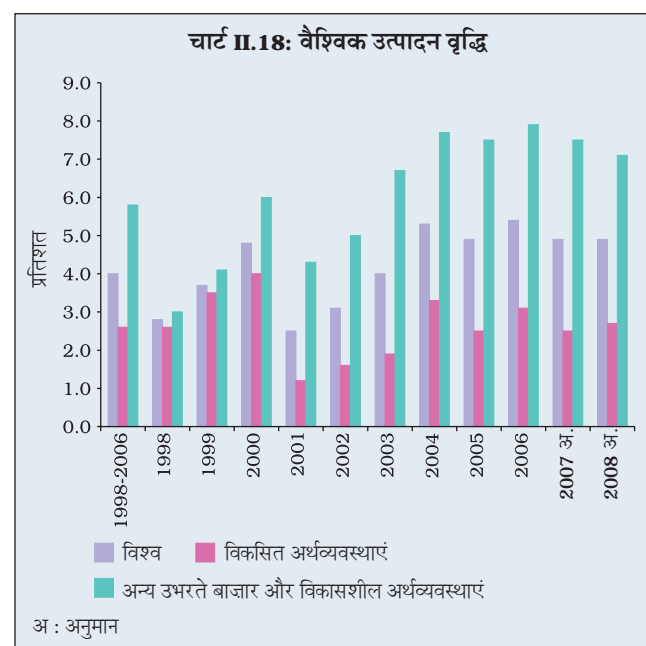
* : सरकारी कंपनियों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं/निगमों के
- : शून्य / नगण्य.

नोट : 1. क.पू.ला. - कर पूर्व लाभ
2. क.ला. - करोत्तर लाभ

चौथाई हिस्सा थीं। वर्ष 2005-06 के दौरान जहां ऋण तथा अग्रिमों में 27.8 प्रतिशत की कमी आई वहीं किराया खरीद आस्तियों में 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान, एनबीएफसी समूह में, जहां किराया खरीद वित्त कंपनियों की आस्ति/देयताओं में वृद्धि हुई वहीं उपस्कर पट्टा कंपनियों, निवेश तथा ऋण कंपनियों की आस्ति/देयताओं में कमी आई। यह मुख्यतः जमाराशि तथा उधार के जरिए उगाहे गए संसाधनों के प्रभाव को दर्शाता है। मार्च 2006 के अंत में किराया खरीद वित्त कंपनियां सबसे बड़े एनबीएफसी समूह के रूप में उभरी थीं। उसके बाद आकार के अनुसार उपस्कर पट्टा कंपनियों, निवेश कंपनियों तथा ऋण कंपनियों का स्थान काफी नीचे था।

2.139 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान तीन आरएनबीसी की आस्तियों में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंक के पास मीयादी जमाराशि के रूप में रखी गई तथा भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में स्थित उनकी आस्तियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई जबकि बांडों/डिबेंचरों तथा अन्य निवेश के रूप में स्थित उनकी आस्तियों में थोड़ी सी वृद्धि हुई (सारणी 2.46)। वर्ष 2005-06 के दौरान आरएनबीसी की निवल स्वाधिकृत निधि में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.140 सरकार, रिजर्व बैंक तथा स्वयं बैंकों द्वारा किए गए लगातार प्रयास के चलते प्रतिस्पर्धी, स्वस्थ तथा ऊर्जस्वित वित्तीय प्रणाली का विकास हुआ। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता तथा मजबूती के लक्षण, समग्र रूप में, वैश्विक स्तर के समतुल्य है। यह उपलब्धि विवेकपूर्ण मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के सतत प्रयास तथा बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के दबाव की पृष्ठभूमि में हासिल की गई है।



सारणी 2.47 : देश-वार वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर)

(प्रतिशत)

देश/क्षेत्र	2005	2006-ति1	2006-ति2	2006-ति3	2006-ति4	2006	2007-ति1	2007 प्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विकसित अर्थव्यवस्था								
यूरो क्षेत्र	1.4	2.2	2.8	2.8	3.3	2.7	3.1	2.3
जापान	1.9	3.0	2.1	1.4	2.2	2.2	2.0	2.3
कोरिया	4.2	6.3	5.1	4.8	4.0	5.0	4.0	4.4
ओईसीडी	2.5	3.3	3.3	2.9	3.3	3.0	..	2.5
यूके	1.9	2.4	2.8	2.9	3.0	2.7	2.8	2.9
यूएस	3.2	3.7	3.5	3.0	3.1	3.3	2.1	2.2
उभरती अर्थव्यवस्थाएं								
अर्जेंटीना	9.2	8.6	7.9	8.7	8.6	8.5	..	7.5
ब्राजील	2.9	3.4	1.2	3.2	3.8	3.7	..	4.4
चीन	10.4	10.3	10.9	10.7	10.7	10.7	11.1	10.0
भारत	9.2	9.3	8.9	9.2	8.6	9.2	..	8.4
इंडोनेशिया	5.7	5.0	5.0	5.9	6.1	5.5	..	6.0
मलेशिया	5.2	5.3	6.2	5.8	5.7	5.9	..	5.5
थाइलैंड	4.5	6.1	5.0	4.7	4.2	5.0	..	4.5

प्र : आइएमएफ प्रक्षेपण .. अनुपलब्ध

स्रोत : आइएमएफ, दि इकोनॉमिस्ट, ओईसीडी एंड ईसीबी बुलेटिन, मई 2007।

VI. बाह्य क्षेत्र

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

2.141 वर्ष 2006 में विश्व अर्थव्यवस्था में वृद्धि काफी तेज गति से हुई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2005 के 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के मुकाबले वर्ष 2006 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.4 प्रतिशत वृद्धि दर का आकलन किया है तथा यह भी अनुमान लगाया है कि वर्ष 2007 में यह दर घटकर 4.9 प्रतिशत रह जाएगी (चार्ट II.18)। वर्ष 2006 की तीसरी तिमाही में वृद्धि दर में थोड़ी-सी गिरावट आने के बावजूद यूएस, जापान, ओईसीडी देश सहित सभी प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में चौथी तिमाही में उच्चतर वृद्धि हुई, परंतु वर्ष 2007 की पहली तिमाही में इसमें गिरावट आई।

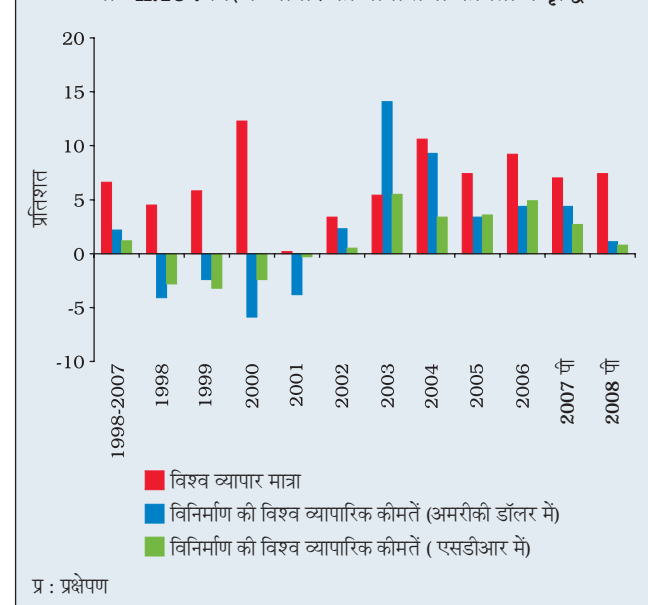
2.142 यूएस में वर्ष 2006 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में (जीडीपी) (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि तीसरी तिमाही में यह दर 3.0 प्रतिशत थी (सारणी 2.47)। चौथी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि का मुख्य कारण टिकाऊ वस्तुओं से इतर वस्तुओं के निजी उपभोग व्यय में वृद्धि के साथ-साथ आयात में कमी व निर्यात में वृद्धि होना है। वर्ष 2006 के लिए जीडीपी की समग्र वृद्धि वर्ष 2005 के मुकाबले थोड़ी अधिक थी। निर्यात में भारी वृद्धि तथा घरेलू मांग में बढ़ोतरी के चलते वर्ष 2006 में जापान की अर्थव्यवस्था में सुधार होना जारी रहा। घरेलू तथा बाह्य मांग की अच्छी स्थिति के चलते चीन के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जारी रही। अचल आस्तियों में निवेश की दर काफी अधिक थी यद्यपि 2006 के मध्य तक कठोर उपायों के लागू करने के चलते इसमें कमी आई।

2.143 वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना के कुछ जोखिम भी हैं। तथापि, वृद्धि की संभावना की जोखिम उतनी डरावनी नहीं है जितना कि पहले

सोचा गया था। यद्यपि, संतोषजनक वैश्विक वृद्धि के संबंध में समग्र जोखिम धारणाएं सामान्य हैं, तथापि कतिपय अनिश्चितताएं तथा चिंताएं बनी हुई हैं, जैसे - उत्पादन में कमी के चलते मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ना, तेल की कीमतों में वृद्धि, आवास क्षेत्र में खराब स्थिति के बने रहने पर यूएस की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मंदी आ जाने की आशंका, वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव तथा वैश्विक असंतुलन के अनियमित समायोजन की संभावना।

2.144 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व व्यापार की मात्रा में वर्ष 2006 में 9.2 प्रतिशत (वर्ष 2005 में 7.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, परंतु

चार्ट II.19 : विश्व व्यापार की मात्रा तथा कीमतों में वृद्धि



प्र : प्रक्षेपण

यह वृद्धि दर वर्ष 2007 में घटकर 7.0 प्रतिशत तक आ जाने की संभावना है। विनिर्मित वस्तुओं के वैश्विक व्यापार के मूल्य में बढ़ोतरी हुई और यह वर्ष 2005 के 3.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006 में 4.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.19)। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, उभरते तथा विकासशील देशों में निवल निजी पूंजी के आगम में थोड़ी कमी आई तथा 2005 के 257.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2006 में यह घटकर 255.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया तथा प्राइवेट पोर्टफोलियो आगम में कमी की संभावना के चलते वर्ष 2007 में पूंजी का आगम और घटकर 252.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रह जाने की संभावना है।

2.145 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में, मई-जून 2006 की थोड़ी अवधि के उतार-चढ़ाव के बाद कुछ समय के लिए मंदी का दौर रहा। जून के अंत के बाद से विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों के मूल्यों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। प्रमुख विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ईक्विटी बाजारों में थोड़ी गिरावट के बाद तेजी का दौर प्रारंभ हुआ और ईक्विटी की कीमतें मई 2006 की महत्वपूर्ण ऊंचाई से भी ऊपर चली गईं। अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 2006 के अंत के आसपास वित्तीय बाजार में तेजी बनी रही। फरवरी-मार्च 2007 में वित्तीय उतार-चढ़ाव की एकाध घटनाओं तथा यूएस सब प्राइम बंधक बाजार के संबंध में बढ़ती चिंताओं के बावजूद वित्तीय बाजार में उछाल बना रहा तथा ईक्विटी बाजार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर के आसपास बना रहा। इसके अतिरिक्त, वास्तविक दीर्घावधि बांड प्रतिलाभ, दीर्घावधि प्रवृत्ति के नीचे रहा तथा अधिकांश बाजारों में जोखिम स्प्रेड में कमी आई।

2.146 वर्ष 2006 के दौरान पेट्रोलियम की औसत स्पॉट कीमतों में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पेट्रोलियम की औसत स्पॉट कीमत जुलाई 2006 में 78.4 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने के बाद अक्टूबर- दिसंबर 2006 के दौरान तेजी से घटकर 58-61 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल तक आ गई जो मध्य-पूर्व में तनाव में कमी, तेल बाजारों में मांग संतुलन में सुधार तथा वर्ष 2006 के उत्तरार्ध में मौसम की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2007 के प्रारंभ में तेल की कीमतें घटकर 50 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल के थोड़े ऊपर तक आ गई, परंतु मार्च 2007 के अंत तक यह बढ़कर लगभग 65 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। ठंडे मौसम के कारण तेल की मांग में बढ़ोतरी, ओपेक द्वारा उत्पादन में कटौती, ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं में इंटेंसिटी में कमी के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव फिर से बढ़ने से भी मार्च के अंत में कीमतों में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 11 मई 2007 को जारी अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2007 के लिए तेल की वैश्विक मांग की मात्रा 85.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन निर्धारित की है जो वर्ष 2006 के 84.2 मिलियन बैरल प्रति दिन के स्तर से अधिक है।

भारत का वाणिज्यिक माल व्यापार

2.147 वर्ष 2005-06 के दौरान भारत के वाणिज्यिक माल व्यापार में निर्यात तथा आयात दोनों में उच्च वृद्धि बनी रही। डीजीसीआइएंडएस के

सारणी 2.48 : वैश्विक वाणिज्यिक माल के निर्यात में वृद्धि (प्रतिशत)

देश/क्षेत्र	जनवरी-दिसंबर	
	2005	2006
1	2	3
विश्व	13.9	15.6
औद्योगिक देश	8.5	12.6
यूनाइटेड स्टेट्स	10.8	14.5
जापान	5.2	9.2
जर्मनी	7.3	15.1
विकासशील देश	21.9	19.6
चीन	28.4	27.2
भारत	29.6	21.5
कोरिया	12.0	14.4
इंडोनेशिया	18.2	16.5
मलेशिया	12.0	14.0
सिंगापुर	15.6	18.4
थाइलैंड	14.5	18.7

स्रोत: 1. इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स, आईएमएफ।
2. डीजीसीआइएंडएस, भारत के लिए।

अनुसार पिछले वर्ष के 31 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2005-06 में निर्यात में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात में वृद्धि के कारण मुख्यतः वैश्विक मांग की अनुकूल स्थिति, भारतीय विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती प्रतियोगितात्मकता, वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी तथा समर्थनकारी घरेलू नीतिगत उपाय थे। वर्ष 2005 में भारत, निर्यातकर्ता देश के रूप में तेजी से उभरने वाले देशों में से एक था (सारणी 2.48)। कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के चलते तेल के आयातों में तीव्र वृद्धि होने के कारण वर्ष 2005-06 में वाणिज्यिक माल आयात में पिछले वर्ष की 43 प्रतिशत वृद्धि के स्तर से और 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात की तुलना में आयात काफी अधिक होने के कारण व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 28.0 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 40.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

2.148 वर्ष 2005-06 के दौरान प्रमुख उत्पाद समूहों में वृद्धि के साथ, निर्यात में वृद्धि का आधार व्यापक था। वर्ष 2005-06 के दौरान प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की गति बनी रही। कोटा मुक्त वातावरण में वस्त्र तथा तत्संबंधी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि जारी रही। प्रौद्योगिकी प्रधान वस्तुओं, जैसे यातायात संबंधी उपकरण तथा मशीनरी और उपकरणों में भी अच्छी वृद्धि देखी गई। वर्ष 2005-06 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 65 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई तथा यह निर्यात की प्रमुख वस्तु के रूप में उभरा है।

2.149 आयात के क्षेत्र में, वर्ष 2005-06 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मुख्यतः कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के चलते तेल के आयात में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2005-06 के दौरान कच्चे तेल की औसत दर (भारतीय बास्केट) 55.3 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल थी जो पिछले वर्ष की दर से 42.2 प्रतिशत अधिक है। मात्रा की दृष्टि से,

मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

सारणी 2.49 : भारत का विदेश व्यापार

(मिलि. अम. डॉलर)

मद	अप्रैल-मार्च			
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
निर्यात	63,843	83,536	103,101	124,598
	(21.1)	(30.8)	(23.4)	(20.9)
तेल	3,568	6989	11526	..
	(38.5)	(95.9)	(64.9)	..
तेल से इतर	60,274	76,547	91,575	..
	(20.2)	(27.0)	(19.6)	..
आयात	78,149	111,517	143,430	181,343
	(27.3)	(42.7)	(28.6)	(26.4)
तेल	20,569	29,844	43,963	57,308
	(16.6)	(45.1)	(47.3)	(30.4)
तेल से इतर	57,580	81,673	99,466	124,035
	(31.5)	(41.8)	(21.8)	(24.7)
व्यापार संतुलन	-14,307	-27,981	-40,329	-56,745
तेल	-17,001	-22,855	-32,437	..
तेल से इतर	2,694	-5,127	-7,892	..

.. : अनुपलब्ध

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े वार्षिक वृद्धि दरें हैं।

स्रोत : डीजीसीआइएंडएस।

पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेंट के आयात में पिछले वर्ष के 5.5 प्रतिशत की तुलना में 4.2 प्रतिशत की कम वृद्धि हुई।

2.150 वर्ष 2005-06 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मुख्यतः सोना, चांदी और मोती तथा कम मूल्यवान रत्नों की आयात में कमी के चलते तेल से इतर वस्तुओं के आयात की दर में कमी आई। मुख्यतः औद्योगिक निविष्टियों के आयातों (गैर तेल आयात, सोना तथा चांदी, थोक खपतवाली वस्तुएं, विनिर्मित खाद तथा प्रोफेशनल आयात घटाकर) में पिछले वर्ष के 41.4 प्रतिशत की वृद्धि के स्तर से 34.7 प्रतिशत की और वृद्धि हुई।

वर्ष 2005-06 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात (मुख्यतः धातु, मशीन उपकरण, मशीनरी तथा इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं) में 49.9 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पूर्व 37.5 प्रतिशत) भारतीय विनिर्माण उद्योगों में औद्योगिक कार्यकलापों में सुदृढ़ वृद्धि के चलते निवेश की निरंतर मांग तथा क्षमता निर्माण को दर्शाता है।

2.151 वर्ष 2005-06 (अप्रैल-मार्च) के दौरान निर्यात के गंतव्य देश के रूप में 16.8 प्रतिशत निर्यात के साथ यूएसए प्रमुख गंतव्य देश के रूप में बना रहा, उसके बाद यूएइ (8.3 प्रतिशत), चीन (6.6 प्रतिशत), सिंगापुर (5.3 प्रतिशत) तथा यूके (4.9 प्रतिशत) का स्थान था।

2.152 वर्ष 2006-07 के दौरान वाणिज्यिक माल के निर्यात में 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी 2.49)। आयातों में 26.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जिसमें से आयातों में वृद्धि का 64.9 प्रतिशत हिस्सा तेल से इतर वस्तुओं का था। राजकोषीय वर्ष के प्रारंभ में तेल से इतर वस्तुओं के आयात में वृद्धि की दर कम थी, परंतु सितंबर 2006 से इसमें और बढ़ोतरी प्रारंभ हुई। दूसरी ओर, तेल की कीमतों में नरमी आने के चलते तेल के आयात मूल्य में कमी आई।

2.153 वर्ष 2006-07 के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 40.3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 56.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अप्रैल- जनवरी 2006-07 के दौरान, गैर तेल व्यापार घाटे में 52.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 14.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि इसी अवधि में तेल खाते में घाटा 23.2 प्रतिशत बढ़कर 32.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

2.154 वस्तु-वार रूप में, वर्ष 2006-07 (अप्रैल-जनवरी) के निर्यात की स्थिति संबंधी आंकड़े भारी असमानता दर्शाते हैं (सारणी 2.50)। इंजीनियरिंग

सारणी 2.50 : भारत के प्रमुख निर्यात

मद	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-मार्च		अप्रैल-जनवरी		अप्रैल-जनवरी	
	मिलि. अम. डॉलर		वृद्धि दर (प्रतिशत)		(मिलि. अम. डॉलर)		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्राथमिक उत्पाद	13553	16377	36.9	20.8	12761	14959	29.4	17.2
कृषि और संबद्ध उत्पाद	8475	10213	12.5	20.5	8026	9598	22.3	19.6
अयस्क और खनिज	5079	6164	114.4	21.4	4735	5361	43.3	13.2
विनिर्मित वस्तुएं	60731	72230	25.2	18.9	58041	67372	22.9	16.1
चमड़ा और विनिर्मित वस्तुएं	2422	2691	12.0	11.1	2203	2401	12.1	9.0
रसायन और संबंधित उत्पाद	12444	14757	31.7	18.6	11726	13427	20.4	14.5
अभियांत्रिकी सामान	17348	21463	39.8	23.7	17175	23468	30.5	36.6
कपड़ा और कपड़ा उत्पाद	13555	16350	6.0	20.6	13145	13965	23.0	6.2
रत्न और आभूषण	13762	15529	30.2	12.8	12593	12850	17.5	2.0
हस्तशिल्प	377	458	-24.5	21.3	385	306	22.3	-20.7
गलीचे	636	848	8.7	33.2	694	742	34.9	6.8
पेट्रोलियम उत्पाद	6989	11526	95.9	64.9	9452	15331	66.8	62.2
कुल निर्यात	83536	103101	30.8	23.4	82396	101846	27.7	23.6

स्रोत : डीजीसीआइएंडएस।

हाल की आर्थिक गतिविधियां

सारणी 2.51 : भारतीय निर्यात के प्रमुख गंतव्य देश

देश	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-मार्च		अप्रैल-जनवरी		अप्रैल-जनवरी	
	(मिलि. अम. डॉलर)		वृद्धि दर (प्रतिशत)		(मिलि. अम. डॉलर)		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
यूएसए	13766	17353	19.8	26.1	14108	15486	27.2	9.8
यूईई	7348	8592	43.4	16.9	6847	9873	20.5	44.2
यूके	3681	5059	21.8	37.4	4164	4547	46.7	9.2
हांगकांग	3692	4471	13.2	21.1	3584	3676	25.9	2.6
जर्मनी	2826	3586	11.1	26.9	2842	3164	30.4	11.3
चीन	5616	6759	90.0	20.4	5177	6438	45.6	24.3
जापान	2128	2481	24.5	16.6	1999	2266	24.9	13.3
बेल्जियम	2510	2871	39.0	14.4	2294	2803	17.9	22.2
सिंगापुर	4001	5425	88.3	35.6	4382	4766	45.7	8.8
इटली	2286	2519	32.2	10.2	1967	2910	12.7	48.0
बांग्लादेश	1631	1664	-6.3	2.0	1354	1310	6.5	-3.2
श्रीलंका	1413	2025	7.1	43.3	1648	1712	48.1	3.9
फ्रांस	1681	2080	31.2	23.7	1665	1707	25.5	2.5

स्रोत : डीजीसीआइएडएस।

वस्तुओं तथा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में उच्च वृद्धि हुई, जबकि अन्य प्रमुख वस्तुओं, जैसे प्राथमिक उत्पादों, रसायन तथा तत्संबंधी उत्पादों, वस्त्र तथा रत्न और जवाहरात के निर्यात में कमी आई। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में, अमरीकी डालर में 62.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो निर्यात में कुल वृद्धि का 30.2 प्रतिशत है। अप्रैल-जनवरी 2006-07 के दौरान चाय, तम्बाकू, मसाले तथा चीनी व शीरा के निर्यात में उच्च वृद्धि दर के बावजूद कृषि तथा तत्संबंधी उत्पादों के निर्यात की दर में कमी आई। विनिर्मित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की 22.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में घटकर 16.1 प्रतिशत रह गई। विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी की

प्रमुख मदों में इंजीनियरी वस्तुओं (जैसे मशीनरी तथा उपस्कर, धातुओं से निर्मित वस्तुएं, लोहा तथा स्टील एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) के निर्यात में तेज वृद्धि हुई जबकि रत्नों तथा आभूषणों, रसायन, चमड़ा, वस्त्र तथा हस्तशिल्प का निर्यात घटा अथवा इनके निर्यात की वृद्धि की दर में कमी आई।

2.155 वर्ष 2006-07 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान यूईई को निर्यात में 44.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके चलते कुल निर्यात में उसका हिस्सा 9.7 प्रतिशत हो गया। भारत से यूएस, चीन, सिंगापुर, तथा यूरोपियन यूनियन में निर्यात में कमी आई जबकि पूर्वी यूरोप तथा अफ्रीका में निर्यात में काफी वृद्धि हुई (सारणी 2.51)।

सारणी 2.52 : भारत के प्रमुख आयात

देश	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-मार्च		अप्रैल-जनवरी		अप्रैल-जनवरी	
	(मिलि. अम. डॉलर)		वृद्धि दर (प्रतिशत)		(मिलि. अम. डॉलर)		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और संबंधित सामग्री	29844	43963	45.1	47.3	35647	47609	48.3	33.6
खाद्य तेल	2465	2024	-3.0	-17.9	1627	1798	18.5	10.5
अलौह धातुएं	1310	1844	38.1	40.8	1519	2142	43.2	41.0
धातु लौहिय अयस्क और धातु के स्क्रेप	2468	3882	90.5	57.3	3126	6815	61.7	118.0
लोहा और इस्पात	2670	4572	77.3	71.3	3844	5046	88.6	31.3
पूँजीगत सामान	25135	37666	37.5	49.9	25900	34299	39.9	32.4
मोती, मूल्यवान व कम मूल्यवान पत्थर	9423	9134	32.2	-3.1	8028	5966	10.9	-25.7
टेक्सटाइल यार्न, फैब्रिक आदि.	1571	2051	24.9	30.5	1748	1815	37.7	3.8
रसायन, जैविक और अजैविक	5700	6984	41.4	22.5	5783	6444	30.0	11.4
सोना और चांदी	11150	11318	62.6	1.5	9189	12344	2.9	34.3
कुल आयात	111517	143430	42.7	33.8	117872	148291	35.1	25.8

स्रोत : डीजीसीआइएडएस।

सारणी 2.53 : भारत का चालू खाता

(मिलि. अम. डॉलर)

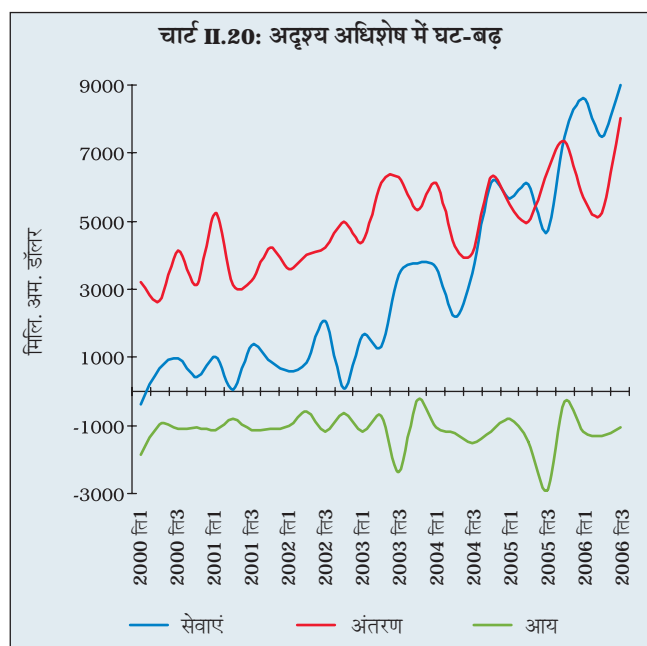
मद	अप्रैल-दिसंबर					
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 आं.सं.	2005 आं.सं.	2006 अ.
1	2	3	4	5	6	7
I. व्यापारिक माल शेष	-10,690	-13,718	-33,702	-51,841	-40,089	-52,302
II. अदृश्य मदों का शेष (क + ख + ग)	17,035	27,801	31,232	42,655	28,147	40,481
क) सेवाएं	3,643	10,144	15,426	23,881	16,416	25,064
i) यात्रा	-29	1,435	1,417	1,389	788	981
ii) परिवहन	-736	879	144	-1,550	-1087	-450
iii) बीमा	19	56	148	22	100	365
iv) जी.एन.आइ.ई.	65	28	-10	-197	-107	-97
v) विविध	4,324	7,746	13,727	24,217	16,722	24,265
जिसमें से:						
सॉफ्टवेयर सेवाएं	8,863	12,324	16,900	22,262	15,597	20,143
ख) अंतरण	16,838	22,162	20,785	24,284	16,937	18,943
i) सरकारी	451	554	260	182	63	115
ii) निजी	16,387	21,608	20,525	24,102	16,874	18,828
ग) आय	-3,446	-4,505	-4,979	-5,510	-5,206	-3,526
i) निवेश आय	-3,544	-3,757	-4,095	-4,921	-4,741	-3,100
ii) कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	98	-748	-884	-589	-465	-426
कुल चालू खाता	6,345	14,083	-2,470	-9,186	-11,942	-11,821

जीएनआईई : सरकारी जो अन्यत्र शामिल नहीं है।

अ : अनंतिम

आं.सं. : आंशिक रूप में संशोधित।

2.156 वर्ष 2006-07 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान निर्यात से संबंधित वस्तुओं के आयात, मुख्यतः मोती, मूल्यवान तथा कम मूल्यवान रत्नों के आयात में कमी आई जबकि सोना तथा चांदी, पूंजीगत वस्तुओं तथा पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (पीओएल) के आयात में वृद्धि की गति बनी रही। अप्रैल-जनवरी 2006 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 32.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो घरेलू औद्योगिक वस्तु की मांग में लगातार तेजी को दर्शाता है (सारणी 2.52)।

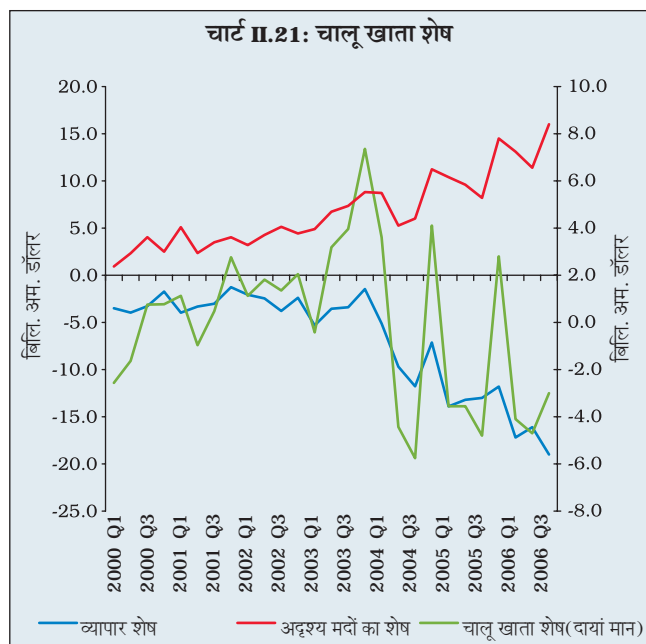


भुगतान संतुलन

चालू खाता

2.157 अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान अदृश्य मदों के अधिशेष में निरंतर वृद्धि ने बढ़ते वाणिज्यिक व्यापार घाटे के असर को कम करने का कार्य किया (सारणी 2.53 तथा चार्ट II.20)। अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान, अदृश्य मदों से प्राप्तियों में 29.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण विदेश में रहने वाले भारतीयों द्वारा प्रेषित राशि में वृद्धि के अलावा सॉफ्टवेयर निर्यात, अन्य प्रोफेशनल तथा व्यापारिक सेवाओं, यात्रा तथा यातायात में महत्वपूर्ण निरंतर वृद्धि होना है। अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान सॉफ्टवेयर सेवा के अंतर्गत निवल अधिशेष (20.1 बिलियन अमरीकी डालर) की राशि में अप्रैल-दिसंबर 2005 के स्तर से 29.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर 2006 में व्यापार सेवा से प्राप्त राशि में बढ़ोतरी होकर 4.0 बिलियन अमरीकी डालर (पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1.5 बिलियन अमरीकी डालर) तक पहुंच जाने का मुख्य कारण व्यापार संबंधित सेवाओं, व्यापार तथा प्रबंधन संबंधी परामर्शी सेवाओं, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी सेवाओं तथा कार्यालयों के रखरखाव संबंधी सेवाओं में बढ़ोतरी होना है। निजी अंतरण (निवल) की राशि जिसमें मुख्यतः विदेश में कार्यरत भारतीयों का प्रेषण शामिल है, अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान बढ़कर 18.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई जबकि अप्रैल-दिसंबर 2005 के दौरान यह राशि 16.9 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। निवेश आय शेषराशि में घाटा बना रहा, क्योंकि बाहरी देयताओं के संबंध में भुगतान की राशि बाहरी आस्तियों से प्राप्त आय से अधिक थी।

हाल की आर्थिक गतिविधियां



2.158 समग्र रूप में, अदृश्य वस्तु (सेवा, अंतरण तथा आय सहित) मदों के अंतर्गत निवल अधिशेष की राशि अप्रैल-दिसंबर 2005 के 28.1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान 40.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गई (चार्ट II.21)। अदृश्य वस्तु मदों से संबंधित निवल अधिशेष के उच्चतर रहने के कारण चालू खाते में घाटे की राशि 11.8 बिलियन अमरीकी डालर थी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के घाटे के प्रायः समान (11.9 बिलियन अमरीकी डालर) है।

पूंजी खाता

2.159 वर्ष 2006-07 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान भारत में पूंजी का आगम काफी बड़ी मात्रा में हुआ। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक

सारणी 2.54 : पूंजी प्रवाह (निवल)

(मिलि. अम. डॉलर)

मद	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-दिसंबर	
	2004-05	2005-06 आं.सं.	2005 आं.सं.	2006 अ
1	2	3	4	5
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	3.7	4.7	3.3	5.8
संविभाग निवेश	9.3	12.5	8.2	5.2
बाहरी सहायता	1.9	1.7	1.1	0.9
बाहरी वाणिज्यिक उधार	5.2	2.7	-1.2	9.1
एन आर आइ जमाराशि	-1.0	2.8	1.1	3.2
अन्य बैंकिंग पूंजी	4.9	-1.4	0.7	-2.1
अल्पावधि ऋण	3.8	1.7	1.7	1.3
अन्य पूंजी	0.2	-1.3	-1.5	3.9
कुल	28.0	23.4	13.4	27.3
अ. : अनंतिम	आं.सं. : आंशिक रूप में संशोधित			

सारणी 2.55 : श्रेणी के अनुसार विदेशी निवेश प्रवाह

(मिलि. अम. डॉलर)

मद	अप्रैल-फरवरी			
	2004-05	2005-06 अ.	2005-06	2006-07अ.
1	2	3	4	5
अ. प्रत्यक्ष निवेश (I+II+III)	6051	7722	5948	17142
1. इक्विटी (क+ख+ग+घ+ङ)	3778	5820	4510	15343
क. सरकारी				
(एसआइए/एफआइपीबी)	1062	1126	1030	2096
ख. भा. रि. बैंक	1258	2233	1559	6737
ग. एनआरआइ	-	-	-	-
घ. शेयर अभिग्रहण*	930	2181	1711	6149
ङ. अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी #	528	280	210	361
II. पुनर्निवेशित आय \$	1904	1676	1257	1730
III. अन्य पूंजी \$\$	369	226	181	69
आ. संविभाग निवेश (क+ख+ग)	9315	12492	11527	9409
क. जीडीआर/एडीआर ##	613	2552	2270	3751
ख. एफआइआइ**	8686	9926	9243	5658
ग. अपतटीय निधि और अन्य	16	14	14	-
ग. कुल (अ+आ)	15366	20214	17475	26551

अ : अनंतिम

* : अनिवासी द्वारा फेमा, 1999 की धारा 6 के अंतर्गत भारतीय कंपनी के शेयरों के अभिग्रहण से संबंधित है। ऐसे अभिग्रहण संबंधी डाटा जनवरी 1996 से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

: अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी की 2005-06 तथा 2006-07 के आंकड़े आकलित आंकड़े हैं।

\$: 2005-06 और 2006-07 के आंकड़ों का अनुमान पिछले दो वर्षों के औसत के आधार पर किया गया है।

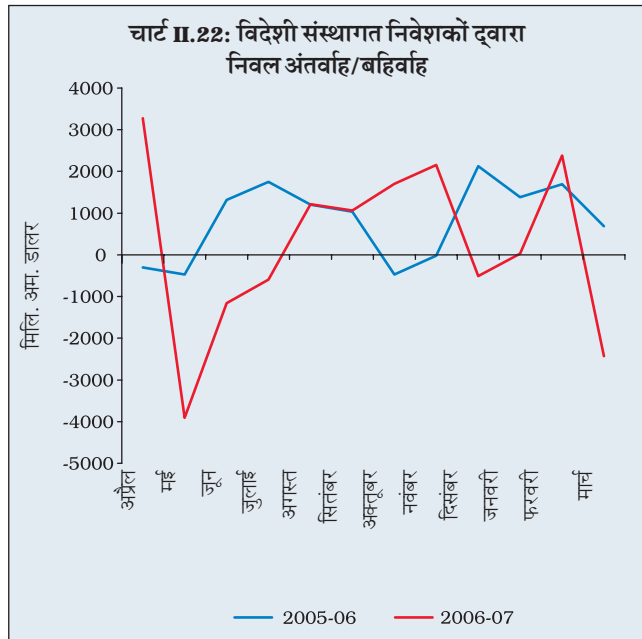
\$\$: आंकड़े एफडीआइ इकाइयों के अंतर कंपनी ऋण लेनदेन से संबंधित हैं।

: भारतीय कंपनियों द्वारा जीडीआर और एडीआर के माध्यम से जुटाई गई राशि है।

** : एफआइआइ के निवल निधि आगम हैं।

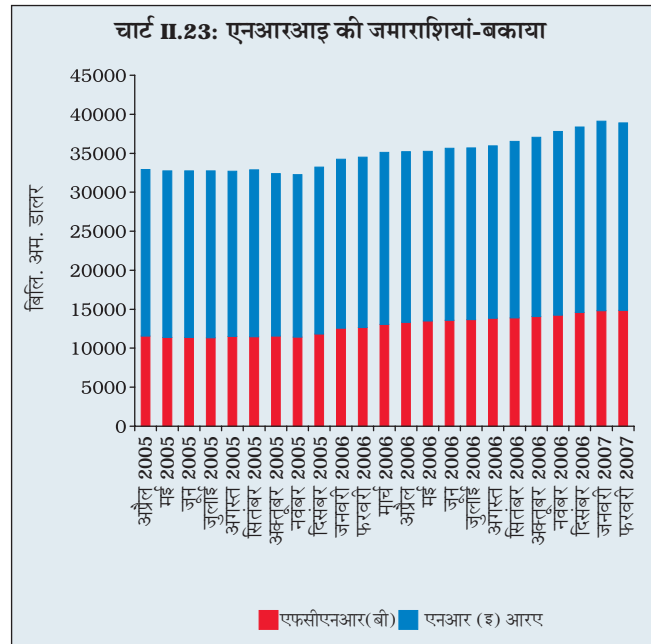
उधार, अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों तथा पोर्टफोलियो निवेश में मजबूती बनी रहने के चलते पिछले वर्ष के मुकाबले निवल पूंजी अंतर्वाह (27.3 बिलियन अमरीकी डालर) में बढ़ोतरी हुई (सारणी 2.54)।

2.160 वर्ष 2006-07 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान विदेशी निवेश अंतर्वाह में लगातार भारी वृद्धि जारी रही। अप्रैल-फरवरी के दौरान भारत में 17.1 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (अनिगमित संस्थाओं की इक्विटी पूंजी, पुनः निवेश की गई आय, संबद्ध संस्थाओं के बीच हुए अंतर-कंपनी ऋण लेनदनों सहित) हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में निवेश की तुलना में तीन गुना से थोड़ा कम है (सारणी 2.55)। विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों (एफडीआइ) में वृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख तत्वों के सुदृढ़ होने, एफडीआइ संबंधी नीतियों को युक्तिसंगत व उदार बनाने के लिए नीतिगत उपाय किए जाने तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाए जाने जैसी बातों को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष 2006 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित रूट के जरिए कई नए क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति दी गई, जैसे ग्रीनफील्ड



एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, प्राकृतिक गैस/एलएनजी पाइप लाइन, कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग, निर्यात ट्रेडिंग और औद्योगिक विस्फोटक और जोखिम वाले रसायन। स्वयं के उपयोग के लिए कोयला तथा ग्रेनाइट के खनन एवं पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस क्षेत्र में मार्केटिंग के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया है। सरकार ने एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार में, पूर्वानुमोदन के बाद, एफडीआई में 51 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, इसके साथ-साथ कतिपय शर्तों के अधीन टीवी चैनलों की अपलिंकिंग हेतु एफडीआई की सीमा में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मुख्यतः निर्माण क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र, कंप्यूटर तथा कारोबारी सेवा एवं निर्माण क्षेत्र में हुआ है। मारिशस, यूएस तथा युनाइटेड किंगडम भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रमुख स्रोत थे।

2.161 अंतर्राष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों में गिरावट के कारण घरेलू ईक्विटी बाजारों में मंदी आने के चलते विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवल अंतर्वाह मई-जुलाई 2006 के दौरान ऋणात्मक स्तर पर आ गया। तथापि, अगस्त 2006 तथा नवंबर 2006 के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में भारी खरीदारी की (चार्ट II.22)। दिसंबर 2006 के दौरान थाईलैंड द्वारा पूंजी नियंत्रण के क्षेत्र में सख्ती बरतने के कारण एशिया के ईक्विटी बाजारों में उतार-चढ़ाव आने के चलते विदेशी संस्थागत निवेशकों के अंतर्वाह में फिर से ऋणात्मक प्रवृत्ति देखी गई। जनवरी 2007 के मध्य तथा फरवरी 2007 के तीसरे सप्ताह के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों के अंतर्वाह में वृद्धि के बाद फरवरी 2007 के अंतिम सप्ताह से उसमें ऋणात्मक प्रवृत्ति देखी गई जिसका कारण यूएस की अर्थव्यवस्था में मंदी की चिंताओं के चलते एशिया के ईक्विटी बाजारों में तेज गिरावट आना है।



2.162 वर्ष 2006-07 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों के संचयी निवल अंतर्वाह की राशि 3.2 बिलियन अमरीकी डालर थी (पिछले वर्ष 9.9 बिलियन अमरीकी डालर थी)। सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की संख्या मार्च 2007 के अंत में बढ़कर 996 हो गई (मार्च 2006 के अंत में 882)। अप्रैल-फरवरी 2006-07 के दौरान एडीआर/जीडीआर जारी करके बाहर से जुटाए गए संसाधनों की राशि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान जुटाई गई राशि से अधिक थी (सारणी 2.55)।

2.163 अप्रैल-फरवरी 2006-07 के दौरान अनिवासी भारतीयों की जमाराशि के अंतर्गत प्राप्त अंतर्वाह की राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के 2.0 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 3.5 बिलियन अमरीकी डालर थी जो अंशतः उच्चतर ब्याज दर के प्रभाव को दर्शाता है (सारणी 2.56 तथा चार्ट II.23)। एनआरआई जमाराशियों पर उच्चतम ब्याज दरें अमरीकी डॉलर के लिबॉर/स्वैप दर + 100 आधार अंक से नवंबर 2005 तथा अप्रैल 2006 में प्रत्येक बार 25-25 अंक बढ़ाई गईं।

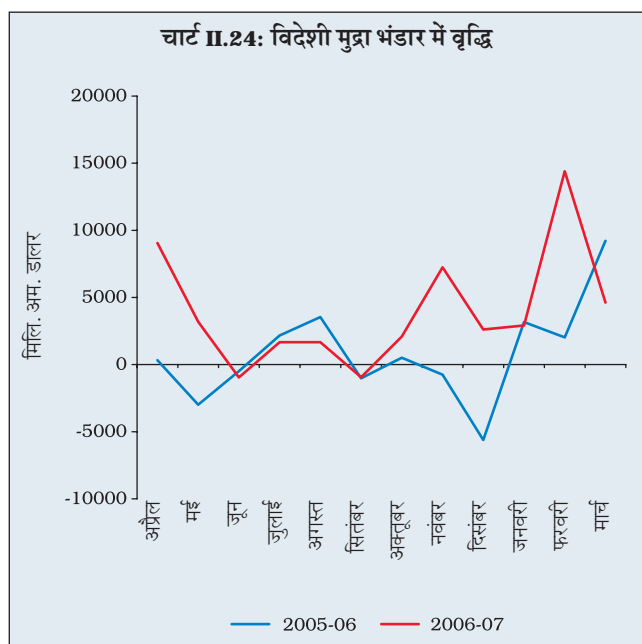
सारणी 2.56 : एनआरआई जमाराशि योजना के अंतर्गत अंतर्वाह

(मिलि. अम. डॉलर)

योजना	अप्रैल-मार्च		अप्रैल-फरवरी	
	2004-05	2005-06	2005-06	2006-07अ.
1	2	3	4	5
एफसीएनआर (बी)	492	1,612	1,219	1,804
एनआर (इ) आरए	84	1,177	807	1,744
कुल	576	2,789	2,026	3,548
अ : अनंतिम				

एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की उच्चतम ब्याज दर मार्च 2006 में ‘‘लिबोर/स्वैप दर - 25 आधार अंक’’ से ‘‘संबंधित मुद्रा परिपक्वता के लिए लिबोर/स्वैप दर’’ से 25 आधार अंक बढ़ाया गया। बाद में, वर्ष 2006-07 की वार्षिक नीति की 31 जनवरी 2007 को घोषित तीसरी तिमाही की समीक्षा में एनआर(इ) आरए तथा एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए उच्चतम ब्याज दर क्रमशः 50 आधार अंक तथा 25 आधार अंक कम किया गया।

2.164 हाल के वर्षों में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का महत्व काफी बढ़ गया है। भारतीयों द्वारा विदेशों में निवेश, संयुक्त उद्यमों (जेवी) तथा पूर्णतः स्वामित्ववाली सब्सिडियरी में निवेश, भारतीय उद्यमियों द्वारा वैश्विक व्यापार को बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने आए हैं, साथ ही ये संयंत्र तथा मशीनरी तथा वस्तुओं के निर्यात के बढ़ते स्रोत के रूप में भी उभरे हैं। संयुक्त उद्यमों को भारत तथा अन्य देश के बीच आर्थिक सहयोग के माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ऐसे विदेशी निवेशों से होने वाले महत्वपूर्ण लाभ हैं - टेक्नोलॉजी तथा कौशल का अंतरण, अनुसंधान तथा विकास के परिणामों का साक्षा उपयोग, व्यापक वैश्विक बाजार तक पहुंच, ब्रांड की छबि में अभिवृद्धि, रोजगार का सृजन तथा भारत एवं संबंधित देश में स्थित कच्चे माल का बेहतर उपयोग। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश का क्षेत्र आईटी तथा संबंधित सेवा क्षेत्र की कंपनियों के अधिग्रहण से प्रारंभ हुआ था, परंतु अब यह प्रक्रिया अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल तथा पेट्रोलियम में फैल गयी है। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में कंपनियों का अधिग्रहण किए जाने के चलते अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि बनी रही। इसे प्रतिबिंबित करते हुए भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश की राशि अप्रैल-दिसंबर



सारणी 2.57 : बाहरी ऋण के घटक

मद	के अंत में		अवधि के दौरान घट-बढ़	
	मार्च 06	दिसंबर 06	(मिलि. अम. डॉलर)	(मिलि. अम. डॉलर) (प्रति शत)
1	2	3	4	5
1. बहुपक्षीय	32,559 (25.8)	34,569 (24.2)	2,010	6.2
2. द्विपक्षीय	15,727 (12.4)	15,770 (11.1)	43	0.3
3. आइएमएफ	0	0	0	0.0
4. व्यापार ऋण				
क. 1 वर्ष से अधिक	5,398 (4.3)	5,957 (4.2)	559	10.4
ख. 1 वर्ष तक*	8,696 (6.9)	10,015 (7.0)	1,319	15.2
5. वाणिज्यिक उधार	26,869 (21.2)	35,980 (25.2)	9,111	33.9
6. एनआरआई जमाराशि (दीर्घावधि)	35,134 (27.8)	38,382 (26.9)	3,248	9.2
7. रुपया ऋण	2,031 (1.6)	1,983 (1.4)	-48	-2.3
8. कुल ऋण	1,26,414 (100.0)	1,42,656 (100.0)	16,242	12.8
<i>जापान मदें:</i>				
क. दीर्घावधि ऋण	1,17,718 (93.1)	1,32,641 (93.0)	14,923	12.7
ख. अल्पावधि ऋण	8,696 (6.9)	10,015 (7.0)	1,319	15.2

* : आपूर्तिकर्ता का 180दिन तक का क्रेडिट शामिल नहीं है।
नोट : कोष्ठकों के आंकड़े कुल ऋण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

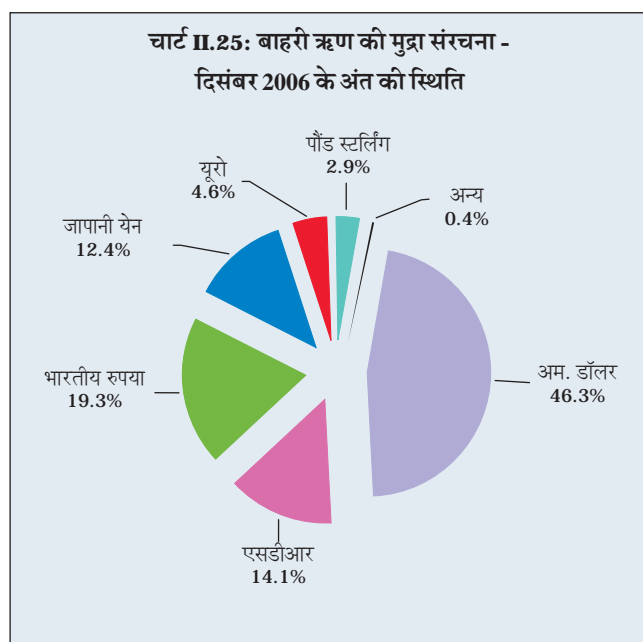
2006 के दौरान बढ़कर 8.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह राशि 1.9 बिलियन अमरीकी डॉलर थी।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

2.165 30 मार्च 2007 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें विदेशी मुद्रा आस्तियां, स्वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) तथा रिजर्व ट्रंच पोजीशन (आरटीपी) शामिल है, बढ़कर 199.18 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (चार्ट II.24)। वर्ष 2006-07 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान निवल पूंजी अंतर्वाह की राशि चालू खाता घाटे की राशि से अधिक थी। समग्र रूप में, वर्ष 2006-07 में विदेशी मुद्रा भंडार में 47.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की बढ़ोतरी हुई जबकि वर्ष 2005-06 में यह बढ़ोतरी 10.1 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। 18 मई 2007 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़कर 204.0 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

भारत का बाह्य ऋण

2.166 भारत का बाह्य ऋण दिसंबर 2006 के अंत में 142.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो मार्च 2006 के अंत के स्तर से 16.2 बिलियन अमरीकी डॉलर अधिक है (सारणी 2.57)। दिसंबर 2006 के अंत में बाह्य



ऋण में बढ़ोतरी का कारण बाह्य वाणिज्यिक उधारों में वृद्धि, अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों तथा अल्पावधि ऋण में बढ़ोतरी होना है। निवेश में वृद्धि का कारण बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा अल्पावधि ऋण में बढ़ोतरी होना है, जबकि अनिवासी भारतीयों की जमा राशि में वृद्धि का कारण अनिवासी जमा राशि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होना है। दिसंबर 2006 के अंत में भारत के बाह्य ऋण के मुद्रा संयोजन में अमरीकी डॉलर का वर्चस्व बना रहा (चार्ट II.25)।

सारणी 2.58 : ऋण संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	मार्च 06 के अंत में	दिसंबर 06 के अंत में
1	2	3
अल्पावधि / कुल ऋण	6.9	7.0
अल्पावधि ऋण/ आरक्षित निधि	5.7	5.7
रियायती ऋण/ कुल ऋण	31.2	28.3
आरक्षित निधि / कुल ऋण	120.0	124.3

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

2.167 बाह्य ऋण वहनीयता संकेतकों में सुधार जारी रहा। मार्च 2006 के अंत तथा दिसंबर 2006 के अंत के बीच कुल ऋण में अल्पावधि ऋण का अनुपात तथा विदेशी मुद्रा भंडार में अल्पावधि ऋण का अनुपात लगभग एकसमान रहा। मार्च 2006 के अंत के 31.2 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2006 के अंत में बाह्य ऋण की तुलना में रियायती ऋण का हिस्सा घटकर 28.3 प्रतिशत तक आ गया जो भारत के बाह्य ऋण स्टॉक में गैर-रियायती निजी ऋण की मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बाह्य ऋण के मुकाबले 34.6 बिलियन

अमरीकी डॉलर अधिक था, जो दिसंबर 2006 के अंत में बाह्य ऋण की राशि की तुलना में 124.3 प्रतिशत है (सारणी 2.58)।

VII. समग्र मूल्यांकन

2.168 वर्ष 2006-07 की गतिविधियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, हाल में हुई वृद्धि की तेज गति को बनाए रखने में सक्षम रही है। घरेलू तथा बाह्य गतिविधियां, समग्र रूप में वृद्धि समर्थनकारी रही हैं। वर्षा के स्थानिक वितरण असमान होने तथा प्रारंभ में कम वर्षा होने के बावजूद दक्षिण पश्चिम मानसून वर्ष 2006 में सामान्य के काफी करीब रहा। अगस्त 2006 तथा जनवरी 2007 के बीच तेल की कीमतों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई थी, परंतु हाल के महीनों में उसमें तेजी आ गई है। औद्योगिक उत्पादन में दो अंकीय वृद्धि दर के चलते औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन काफी अच्छा रहा। औद्योगिक कार्यकलापों को बढ़ाने में विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। विनिर्माण क्षेत्र की यह वृद्धि पिछले 10 वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि है। जैसा कि उच्च ऋण वृद्धि दर एवं कंपनियों द्वारा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से भारी मात्रा में संसाधन जुटाए जाने से स्पष्ट होता है, औद्योगिक क्षेत्र में सुदृढ़ता आई है जिसका कारण घरेलू तथा निर्यात की सुदृढ़ मांग तथा वित्तीयन की संतोषजनक स्थिति है। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयातों में भारी वृद्धि निवेश मांग में सुदृढ़ता को दर्शाती है। रिजर्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए व्यापार आत्मविश्वास सर्वेक्षण, समग्र आर्थिक स्थिति तथा निवेश के उत्साहवर्धक माहौल को दर्शाता है। सेवा क्षेत्र, समग्र वृद्धि प्रक्रिया के प्रमुख कारक के रूप में बना रहा। प्रमुख संकेतक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि सेवा क्षेत्र में अच्छी वृद्धि जारी रहेगी। अप्रैल 2006 को वाषिक नीति वक्तव्य में रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 7.5-8.0 प्रतिशत आंकी गई थी जो जनवरी 2007 की तीसरी तिमाही समीक्षा में लगभग 8.5 - 9.0 प्रतिशत आंकी गई है। सीएसओ के अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2006-07 के लिए 9.2 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में वर्ष 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लगभग 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

2.169 केंद्र सरकार के वर्ष 2006-07 के संशोधित अनुमानों में सभी प्रमुख घाटा संकेतक अर्थात् - सकल राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा तथा प्राथमिक घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपातों के रूप में, बजट में निर्धारित लक्ष्यों से कम थे। इसका मुख्य कारण कर तथा कर से इतर दोनों स्रोतों से भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होना है जो विशेष रूप से गैर-योजना संघटकों पर अधिक मात्रा में हुए व्यय से भी अधिक था। कर राजस्व में सुधार होने तथा उपदान (सब्सिडी) की राशि में कमी आने के आधार पर 2007-08 के बजट अनुमानों में सभी प्रमुख घाटा संकेतकों में और कमी दर्शायी गई है। दूसरी ओर, वर्ष 2007-08 में पूंजी परिव्यय में वृद्धि होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2006-07 में इसमें कमी आई थी।

वर्ष 2007-08 के केंद्रीय बजट में, सुदृढ़ कर प्रणाली की रणनीति को जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें कर की दरें तथा छूटें कम होंगी, कर का आधार व्यापक होगा तथा सामाजिक तथा भौतिक बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश उपलब्ध कराते हुए गैर-विकास व्यय को कम किया जाएगा।

2.170 वर्ष 2006-07 में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति मुख्यतः प्राथमिक वस्तुओं तथा कतिपय विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों से निर्धारित हुई। पिछले दो वर्षों से मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक के रूप में खनिज तेल की कीमतों का काफी प्रभाव रहा, परंतु सितंबर 2006 के प्रारंभ से तेल की कीमतों में कमी आने और आधार वर्ष के प्रभाव के चलते उसका असर क्रमशः कम होता गया। तेल की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का असर पेट्रोल तथा डीजल तक सीमित रहा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से अधिक रहा जिसका मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भार अधिक होना है। मूल्य स्थिरता के लक्ष्य के अनुरूप मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक ने विभिन्न उपायों (ओएमओ, एमएसएस तथा सीआरआर) का लचीलेपन के साथ यथोचित उपयोग करके चलनिधि की सक्रिय मांग के प्रबंधन की नीति को जारी रखा। तदनुसार, उसने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की वृद्धि की और 23 दिसंबर 2006 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात में चरणबद्ध रूप में 150 अंकों की वृद्धि की। वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि उसका यह प्रयास होगा कि वर्ष 2007-08 के दौरान मुद्रास्फीति की दर को 5.0 प्रतिशत के आस-पास तक नियंत्रित रखा जाए।

2.171 वर्ष 2006-07 के दौरान वित्तीय बाजार की स्थिति, उतार-चढ़ाव की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर, सामान्य रही। दिसंबर 2006 के मध्य तक अल्पावधि मुद्रा बाजार दरें सामान्यतः रेपो तथा रिवर्स रेपो दर के दायरे में रहीं। तथापि, उसके बाद सरकार की नकदी शेष राशि में भारी परिवर्तन होने, विदेशी मुद्रा के अंतर्वाह तथा बहिर्वाह में उतार-चढ़ाव आने तथा मौद्रिक नीति के कड़ाई के दौर में कुछ बाजार सहभागियों के पास संपार्श्विक जमानत की कमी के चलते मांग दरों में बीच-बीच में वृद्धि हुई। उसी तरह, सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिफल में मजबूती देखी गई। मई-जून 2006 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दरों में मजबूती आने के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिक्री के दबाव, घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि की चिंता तथा अंतर्राष्ट्रीय ईक्विटी बाजारों में घबराहट की स्थिति के चलते ईक्विटी बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया। तथापि उसके बाद शेयर बाजार की स्थिति स्थिर रही, केवल फरवरी-मार्च 2007 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आए उतार-चढ़ाव के अनुरूप शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की छिटपुट घटनाएं हुईं।

2.172 वर्ष 2005-06 के दौरान बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के परिचालन में व्यापकता आई। इस व्यापकता के साथ-साथ आस्तियों की

गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। इस समय सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियां क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत से कम हैं।

2.173 भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषजनक रही। अप्रैल-दिसंबर 2006 के दौरान अदृश्य वस्तु मर्दों के अधिशेष में वृद्धि हुई जिसने पण्य व्यापार के घाटे को कम करने में सहायता की। यात्रा आय, कारोबारी तथा प्रोफेशनल सेवाओं, सॉफ्टवेयर सेवाओं तथा विप्रेषणों, विशेष रूप से अदृश्य वस्तु मर्दों से संबंधित प्राप्तियों में तेज वृद्धि हुई। पोर्टफोलियो तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, दोनों रूप में भारत में भारी मात्रा में पूंजी का अंतर्वाह जारी रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी मात्रा में निवल निवेश किया, अलबत्ता यह निवेश पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम था। वर्ष 2006-07 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना से थोड़ा कम था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह में हुई वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों की रुचि को दर्शाता है जिसका आधार भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी संकेतों का मजबूत होना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति को युक्तिसंगत और उदार बनाने के लिए किए गए नीतिगत पहल का असर तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना है।

2.174 भारत की भुगतान संतुलन की संतोषजनक स्थिति विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई। वित्तीय वर्ष 2006-07 में विदेशी मुद्रा भंडार में 47.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। बाह्य ऋण वहनीयता संकेतकों में भी सुधार हुआ।

2.175 वर्ष 2006 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ वृद्धि जारी रही, हालांकि हाल की तिमाहियों में इसमें थोड़ी-सी कमी आई। तथापि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना, बाजार की अधोगामी प्रवृत्ति जोखिम (डाउनसाइड रिस्क) के अधीन है। सतत वैश्विक असंतुलन संबंधी समायोजन की अनिश्चितता के अतिरिक्त अन्य प्रमुख जोखिमों में, सीमित अतिरिक्त क्षमता के कारण मुद्रास्फीति का दबाव, विशेष रूप से यूएस में वेतनों में वृद्धि से होने वाला दबाव, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि की संभावना, यूएस में आवास बाजार की कमजोरी तथा वैश्विक जोखिमों के बारे में वित्तीय बाजारों की आत्मसंतुष्टि वाली प्रवृत्ति संबंधी चिंताएं प्रमुख हैं।

2.176 इस पृष्ठभूमि में, वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह उल्लेख किया गया है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिकूल तथा अप्रत्याशित स्थितियों को छोड़कर तथा मुद्रास्फीति संभावनाओं सहित अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकलन के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान समग्र वृद्धि की गति निरंतर सुदृढ़ता तथा गतिशीलता के वातावरण में हुई जिसे कारोबारी तथा ग्राहक विश्वास तथा बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रुचि का समर्थन मिला। वृद्धि की यह गति निवेश की दर में बढ़ोतरी, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दोनों में पूंजी के उपयोग में सुधार एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था



मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट

के साथ सुदृढ़ संपर्क द्वारा निर्धारित थी। अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन के चलते मांग के दबाव में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं जिसके प्रमुख कारणों में सकल मांग में बढ़ोतरी, वैश्विक जीडीपी में उत्साहपूर्ण वृद्धि का समर्थन, विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, कंपनियों की मूल्य-निर्धारण की क्षमता के अधिकतम उपयोग तथा आस्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी होना है। सुदृढ़ समष्टि-आर्थिक कार्य-निष्पादन से उत्पन्न उत्साह को कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय कमी, कृषि में आपूर्ति संबंधी अड़चनों तथा भौतिक बुनियादी सुविधाओं में अंतर, आपूर्ति में कमी के चलते मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी, क्षमता में बढ़ते दबाव तथा आस्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी के रूप में जोखिमों के बढ़ रहे विन्यास के प्रति देखने की आवश्यकता है। औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र की निरंतर वृद्धि में कृषि उत्पादन में कमी तथा भौतिक बुनियादी ढांचे में व्यापक कमियों के चलते अड़चनें आईं। यह भी संकेत है कि सकल घरेलू बचत दर में सुदृढ़ वृद्धि तथा पूंजी के उपयोग की कुशलता में कुछ सुधार के चलते वृद्धि की दर बनी रहेगी जबकि इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी क्षेत्रों की आपूर्ति पक्षीय समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। मांग में बढ़ोतरी का प्रारंभिक असर स्फीतिकारी दबावों एवं समष्टि-आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम के रूप में दिखाई देता है जो पूंजीगत वस्तुओं तथा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की निरंतर मांग, मुद्रा तथा ऋण की उच्चतर दरों, कुछ क्षेत्रों में वेतन में बढ़ोतरी के दबाव, निविष्टियों की लागत में वृद्धि तथा कारपोरेट क्षेत्रों के मूल्य-निर्धारण की क्षमता में बढ़ोतरी के रूप में परिलक्षित होता है। नीतिगत रूप से सबसे बड़ी चुनौती यह है

कि मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित रखते हुए उच्चतर वृद्धि के एक और चरण की ओर किस प्रकार आगे बढ़ा जाए।

2.177 वर्ष 2007-08 की मौद्रिक नीति का दृष्टिकोण सामान्यतः वैश्विक तथा विशेष रूप से घरेलू गतिविधिजन्य परिस्थितियों से निर्धारित होगा। संभावित समष्टि-आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों से यह संकेत मिलता है कि भारत में एक ऐसे माहौल का निर्माण हुआ है जो वर्तमान की वृद्धि दर को बनाए रखने में सक्षम है। इस महत्वपूर्ण बात का पुनः उल्लेख किया जाता है कि मौद्रिक नीति का लक्ष्य वृद्धि को बनाए रखते हुए मूल्य तथा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। आगे आने वाले समय में नीतिगत प्राथमिकता मूल्य स्थिरता बनाए रखने एवं मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को नियंत्रित करने की होगी। तदनुसार, मौद्रिक नीति के समग्र दृष्टिकोण में ये बातें शामिल होंगी : (i) वृद्धि की गति को बनाए रखने के उद्देश्य से निर्यात तथा निवेश मांग को समर्थन देने वाले मौद्रिक तथा ब्याज दर वातावरण के निर्माण को सुनिश्चित करते हुए मूल्य स्थिरता तथा सुस्थिर मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर बल दिया जाना; (ii) ऋण की अधिक उपलब्धता तथा वित्तीय समावेशन के लिए प्रयास करने के साथ-साथ समष्टि-आर्थिक तथा विशेष रूप से, वित्तीय स्थिरता की प्राप्ति के लिए वित्तीय बाजार में क्रेडिट की गुणवत्ता तथा सुव्यवस्थित स्थिति पर पुनः बल दिया जाना; (iii) मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं तथा वृद्धि की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली वैश्विक तथा घरेलू स्थितियों से सभी संभावित उपयुक्त उपायों से शीघ्रता से निपटना।